पोस्टल रजि.नं.यूए-नैनीताल-356-2021-2023

BLM Academy

Affiliated to C.B.S.E. New Delhi, C.B.S.E. Affiliation No.: 3530343
ISO 9001:2015 (QMS) Certified School

Wish You all a Very Happy New Year

"The Best Way To Predict Your Future Is To Create It With BLM Academy."

Vision -
To prepare the children empowered with Indian ethical and spiritual values to face the global challenges.

Mission-
To produce enriched and enlightened human resource for the country.

Pillars -
SATYA, PURUSHARTH & PARAMARTH

Goal-
ब्रह्म तद् लक्ष्यम्

Admission Open
For The Academic Session 2025-26
(Classes Nursery to IX & XI)

LIMITED SEATS
APPLY NOW

Streams: Science, Commerce & Humanities

Celebrate The Gift of Life

+91 7055515681
+91 7055515683
www.blmacademy.com
Padampur Devaliya, Gora Parao, Haldwani (Nainital), Uttarakhand
blma.principal@gmail.com

प्रणवो धनुः शरो हि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते।
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ।। (मुण्डक उपनिषद)

ई-मेल: uttranchaldeepatrika@gmail.com

सितंबर 2025

उत्तरांचल दीप पत्रिका

यशस्वी पत्रकार वेदप्रकाश गुप्ता को समर्पित

₹:40

नंदादेवी राजजात यात्रा अगले बरस

झुकता है ट्रंप झुकाने वाला हो

Web: uttaranchaldeep.com

भावपूर्ण श्रद्धांजलि

FOUNDER OF

UTTARANCHAL DEEP
BLM ACADEMY
TRINITY INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES
SHRI SHYAM COLONISERS Pvt. Ltd.
V.P. GUPTA INFRATECH
NUPUR NRITYA KALA KENDRA

A loving tribute to

Shri.Ved Prakash Gupta Ji

OUR ROLE MODEL

(29th Feb, 1944 - 06th Sep, 2014)

सदैव आपके

श्रीमति आदेश अग्रवाल (पत्नी)
श्री जय प्रकाश एवम् श्रीमति मंजू अग्रवाल (भाई एवम् बहू)
श्रीमति नीरू अग्रवाल (बहू)
श्री मदन मोहन एवम् नीलम अग्रवाल (भाई एवम् बहू)
श्री साकेत एवम् सौम्या अग्रवाल (पुत्र एवम् पुत्र वधु)
श्री विनीत अग्रवाल एवम् शैली अग्रवाल
श्री पियूष एवम् श्वेता अग्रवाल
श्री विपुल एवम् दिपिंका अग्रवाल

श्री पर्वत एवम् मिलिंद अग्रवाल
श्रीमति रितु एवम् संजय अग्रवाल (बेटी एवम् दामाद)
श्रीमति मीनू एवम् देवेंद्र सिंह बिष्ट (बेटी एवम् दामाद)
श्रीमति पूजा एवम् डा० नवीन अग्रवाल (भतीजी एवम् दामाद)
श्रीमति श्रुति एवम् नितिन अग्रवाल (बेटी एवम् दामाद)
अपूर्वा, सक्षम, समर्थ, सिद्धांत, ऋशिका, ऋद्धिमा,
नंन्दिनी, माधव, मिहिर, प्रिशा, शिव्या, इस्नितिका,
दित्या, प्रानिश, ईविश्का, निर्वी प्रकाश

सांध्य दैनिक उत्तरांचल दीप दैनिक
V.P. GUPTA INFRATECH
Trinity
SHRI SHYAM

मासिक उत्तरांचल दीप पत्रिका

वर्ष:8, अंक 5, सितंबर 2025

संस्थापक संपादक
स्व.वेदप्रकाश गुप्ता
प्रधान संपादक
साकेत अग्रवाल
संपादक
श्रीमती आदेश अग्रवाल
मुख्य कार्यकारी संपादक
केके चौहान
मुख्य उप संपादक
उदयभान सिंह
मार्केटिंग हेड
तारु तिवारी
प्रबंधक
दीपक तिवारी
वरिष्ठ संवाददाता
रवि दुर्गापाल

उत्तरांचल दीप ब्यूरो
दिल्ली : शालिनी चौहान
लखनऊ : पारस अमरोही
रुद्रप्रयाग : हिमांशु पुरोहित
नैनीताल : अफजल फौजी
अल्मोड़ा : कमल कपूर
पिथौरागढ़ : ललित जोशी
बागेश्वर : नरेंद्र बिष्ट
चंपावत : मनोज राय
बरेली : अनुज सक्सेना
मुरादाबाद : आशेंद्र कुमार अग्रवाल
डोईवाला : चंद्रमोहन कोठियाल
किच्छा : राजकुमार राज
रामनगर : एचसी भट्ट
थल्यूड़ : मुकेश रावत
रुद्रपुर : मुकेश गुप्ता
बाजपुर : इंद्रजीत सिंह
ग्राफिक्स डिजाइन: देवेंद्र सिंह बिष्ट
सभी पद अवैतनिक एवं परिवर्तनीय

मुख्यालय
हल्द्वानी: चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने
नैनीताल रोड, हल्द्वानी (उत्तराखंड)

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक श्रीमती आदेश अग्रवाल द्वारा उत्तरांचल दीप, चंद्रकांता हाउस, जजी के सामने नैनीताल रोड हल्द्वानी से मुद्रित व प्रकाशित।
आएनआई नंबर: UTTHIN/2018/77440
पोस्टल रजि.नं.यूए-नैनीतील-356-2021-2023

उत्तरांचल दीप पत्रिका में प्रकाशित लेख, पत्र व अन्य कालम में लेखकों के विचार होते हैं, उनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
समस्त विवाद हल्द्वानी न्यायालय के अधीन होंगे।

www.uttaranchaldeep.com
uttranchaldeepatrika@gmail.com
+91 8881788066 @uttaranchaldeep

अंदर

10

हर तरफ तबाही

इस मॉनसून सीजन ने हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड को ऐसे जख्म दिए हैं, जिन्हें भरने में न जाने कितने साल लग जाएंगे, कुछ इलाकों में तो ऐसी तबाही मची कि क्षेत्र का भूगोल ही बदल गया, गढ़वाल हो या कुमाऊं उत्तराखंड के दोनों मंडलों में भारी बारिश न जमकर तांडव किया है।

12

वैश्विक

टैरिफ लगाने की 5 वजह

ट्रंप और मोदी की मुलाकात कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन होनी थी, लेकिन ईरान-इजराइल टेंशन की वजह से ...

16

बिहार

तेज प्रताप बनाम तेजस्वी

राजद में कुछ लोग तेज प्रताप के निष्कासन से खुश नहीं हैं, उनका मानना है कि ...

14

उत्तराखंड

मदरसा बोर्ड खत्म होगा

उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 व उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी व फारसी मदरसा अधिनियम 2019 लागू है ...

बिहार

18

वोट चोर कौन?

राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर नेहरू का पाप भी सार्वजनिक करा दिया, वोट चोरी इंदिरा गांधी ने ...

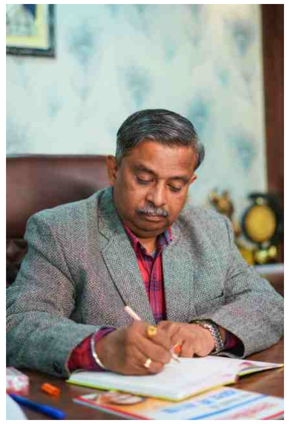

साकेत अग्रवाल

मोदी का दिवाली गिफ्ट

15 अगस्त को लालकिले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर देश को तोहफा देने की घोषणा की थी। इनकम टैक्स में भारी भरकम छूट के बाद मोदी सरकार ने आम आदमी को जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव कर दिवाली का उपहार भी दे दिया है। जीएसटी परिषद ने काफी समय से चले आ रहे जीएसटी के 4 स्लैब को दो स्लैब में बदल दिया है। पहले चार स्लैब थे यानी 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 फीसदी जीएसटी अलग-अलग सामान पर लोगों को चुकाना होता था। किंतु अब जीएसटी परिषद ने जीएसटी के दो स्लैब बना दिए हैं। इनमें पहला 5 प्रतिशत और दूसरा 18 फीसदी है। इसके साथ ही एक स्पेशल स्लैब 40 फीसदी का भी रखा गया है जिसमें सिर्फ सिन गुड्स, लग्जरी गुड्स और हानिकारक आइटाइम्स को रखा गया है। नए स्लैब में दैनिक उपयोग की अधिकतर वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। एक तरह से कर प्रणाली में किया गया यह बड़ा बदलाव नई आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक बेहतर कदम माना जा सकता है।

वैसे तो नई कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के स्लैब में 2017 में इसके लागू होने के बाद कई परिवर्तन किए गए हैं, किंतु वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने फिलहाल जो फैसले किए, वे कई मायनों में अहम कहे जा सकते हैं। अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से ही वैश्विक व्यापार में बड़ी उथल-पुथल चल रही है। ट्रंप ने खासतौर पर भारत को निशाना बनाया है, जिससे भारतीय कारोबारी तनाव में हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को देखते हुए जीएसटी स्लैब में सुधार बहुत जरूरी हो गया था। वैसे भी चार तरह के टैक्स स्लैब के कारण जीएसटी प्रणाली का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा था। उम्मीद की जा रही है कि टैक्स में छूट से घरेलू खपत बढ़ेगी, जिससे ट्रंप की टैरिफ से होने वाले नुकसान को किसी हद तक कम किया जा सकेगा।

सरकार ने जीएसटी प्रणाली में सुधार करते हुए जो दो स्लैब रखे हैं, वो दिवाली से पहले 22 सितंबर से लागू भी हो जाएंगे। जीएसटी परिषद ने कुछ आवश्यक वस्तुओं को टैक्स फ्री करने के साथ कई वस्तुओं पर टैक्स घटाकर घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और छोटे कारोबारियों को भी बड़ी राहत दी है। पहले जिन वस्तुओं पर 12 फीसदी और 28 फीसदी का टैक्स लगता था उसे अब कम स्लैब के दायरे में लाया गया है जो आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत देने वाली बात है। खाने-पीने की चीजों और जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है। लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं के लिए 40 फीसदी का एक स्पेशल टैक्स स्लैब जरूर बनाया गया है, जिसे अनुचित नहीं कहा जा सकता।

सरकार ने 33 जीवन रक्षक दवाओं जिन पर 12 प्रतिशत जीएसटी था उसे अब टैक्स फ्री कर दिया है। कैंसर की दवाओं पर भी कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। इससे निश्चत ही उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिनके अपने गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। क्योंकि आज के दौर में यदि किसी मध्यम वर्गीय परिवार के किसी सदस्य को कैंसर जैसी बीमारी होती है तो समझो महंगे इलाज की वजह से उसका सब कुछ बिक जाता है। लेकिन कैंसर की दवा को टैक्स फ्री कर सरकार ने ऐसे परिवारों का बड़ी राहत दी है। जीएसटी स्लैब कम करने से रेस्टोरेंट संचालकों को कारोबार बढ़ने की उम्मीद जगी है क्योंकि रेस्टोरेंट में खाना खाने पर ग्राहक को 18 प्रतिशत टैक्स देना होता था, लेकिन अब इसे घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। नए जीएसटी स्लैब के बाद सिंगल-स्क्रीन थिएटरों में सिनेमा देखना भी सस्ता हो गया है। क्योंकि 100 रुपये तक या उससे कम कीमत वाले टिकट पर पहले 12 प्रतिशत टैक्स लगता था लेकिन नए जीएसटी स्लैब में इसे घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। सभी तरह की ब्रेड (पराठा, रोटी, खाखरा, पिज्जा ब्रेड) पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। कपड़े और फुटवियर 2500 रुपये तक सस्ते होंगे, इन पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। यानी 12 प्रतिशत वाले 99 फीसदी आइटम को 5 फीसदी जीएसटी स्लैब में शिफ्ट किया गया। जबकि 28 फीसदी वाले अधिकतर सामान को 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में लाया गया है। किसानों को बड़ी राहत देते हुए ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स 18 फीसदी से 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में आएंगे। बायो-कीटनाशक, बायो-फर्टिलाइजर, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स को भी 12 प्रतिशत की जगह 5 फीसदी जीएसटी में शामिल कर दिया है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर भी 12 से 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। कृषि, बागवानी, वानिकी मशीनरी जुताई, खेती, कटाई व गहाई के लिए लगने वाला 18 प्रतिशत जीएसटी अब 5 प्रतिशत हो गया है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। भाजपा शासित राज्य तो जीएसटी स्लैब घटाने के पक्ष में थे, लेकिन पश्चिम बंगाल, पंजाब, कर्नाटक और केरल जैसे गैरभाजपा राज्यों को डर था कि जीएसटी घटने से उनका राजस्व भी घटेगा, लिहाजा गैरभाजपा शासिक राज्यों को मनाने की कोशिश हुई मैराथन मीटिंग में पश्चिम बंगाल और पंजाब तो राजी हो गए, लेकिन कर्नाटक और केरल आखिर तक अड़े रहे। वे चाहते थे कि राज्यों को राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई का ठोस आश्वासन मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा ने सभी को मना लिया और अपना मकसद पूरा कर लिया।

गुरना देवी मंदिर में आस्था

वाहन चालक और उसमें सवार यात्री गुरना माता से सफल यात्रा की कामना करते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा आने-जाने पर मंदिर की घंटिया बजाई जाती हैं, जिसे सफल यात्रा होने का शुभ संकेत माना जाता है।

उत्तरांचल दीप डेस्क

देवभूमि उत्तराखंड देवस्थली भी है। यहां के हर मंदिर की अपनी अलग मान्यता है, एक अलग रहस्यमयी कहानी है। जो श्रद्धालुओं को न सिर्फ आकर्षित करती है बल्कि आस्था व्यक्त करने के लिए विवश करती हैं। इसी राज्य में जहां चार धाम हैं वहीं बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो अपने चमत्कार के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। ऐसे ही मंदिरों की श्रृंखला में पिथौरागढ़ शहर से करीब 13 किलोमीटर दूर टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नकपुर तवाघाट में गुरना माता का मंदिर है। एक तरह से यह मंदिर पिथौरागढ़ जिले के प्रवेश द्वार पर स्थित है। इस मंदिर का वास्तविक नाम पाषाण देवी मंदिर है, लेकिन गुरना गांव के समीप होने की वजह से यह गुरना माता मंदिर के नाम से विख्यात है। गुरना गांव की सीमा पर ही मुख्य सड़क के किनारे एक ठंडी जल धारा बहती थी। पिथौरागढ़ आने जाने वाले वाहन चालक इस जल धारा से मीठा पानी भरते थे। उस दौर में पिथौरागढ़ पहुंचने वाले अधिकांश वाहन बड़े ही होते थे। बड़े वाहन चालक इस जल धारा से पानी पीकर और हाथ मुंह धोकर ताजगी के साथ शहर में प्रवेश करते थे। इस जल धारा से करीब 50 मीटर की दूरी पर सड़क से नीचे की ओर एक छोटा सा पाषाण देवी का मंदिर था। वाहन चालक पिथौरागढ़ सकुशल पहुचंने पर मंदिर में हाथ जोड़कर देवी का ध्यान कर माता का धन्यवाद करते थे कि वो अपनी यात्रा सकुशल कर लौटे हैं। धीरे-धीरे जो वाहन चालक पिथौरागढ़ से बाहर जाते थे उनके चालक भी अपनी आगे की यात्रा मंगलमय होने की कामना के लिए यहां वाहन रोकने लगे। अपनी आगे की यात्रा के लिए जल धारा का मीठ पानी भरकर साथ ले जाने लगे थे। 1952 से पूर्व यानी आजादी से पहले यह छोटा सा पाषाण देवी का मंदिर सड़क से बहुत नीचे था, जहां स्थानीय ग्रामीण व कुछ अन्य श्रद्धालु रोजाना पूजा अर्चना करते थे। 1950 में पिथौरागढ़ से हल्द्वानी और टनकपुक के लिए मोटर मार्ग का निर्माण शुरू हुआ और यातायात सेवा शुरू हुई। तवाघाट से ऊपर की सड़क घुमावदार थी जिसके कारण पिथौरागढ़ मुख्यालय से तवाघाट के बीच आए दिन दुर्घटनाएं होती थीं। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि एक दिन गुरना देवी मंदिर के पुजारी को सपने में आभास हुआ कि गुरना मंदिर को सड़क के आसपास स्थापित करने से देवी मां जरूर अपने भक्तों पर कृपा करेंगी। पुजारी ने सपने में जो कल्पना की, ठीक वैसा ही हुआ। पुजारी ने रात में देवी मां ने जो आभास कराया था उसका जिक्र ग्रामीणों से किया। ग्रामीणों ने पुजारी की बातों को सत्य माना और इसे देवी की इच्छा मानते हुए सड़क के पास भव्य मंदिर बनाने के लिए सहयोग किया। 1952 में गुरना गांव में सड़क के पास मंदिर बन गया और इस क्षेत्र में आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं का दौर थम सा गया। इसे ग्रामीण आज भी माता का चमत्कार ही मानते हैं।

वैष्णो देवी का अवतार हैं गुरना माता

कुमाऊं रेजिमेंट के पिथौरागढ़ प्रवास के बाद यह मान्यता भी बनने लगी की जम्मू की वैष्णो देवी माता का स्थानीय अवतार ही गुरना माता हैं। इसलिए ग्रामीण गुरना मां को माता वैष्णो देवी का स्वरूप मानते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि पहले रात को यहां पर अकसर बाघ दिखाई देता था, जिसे बाघ दिखता था, उस पर माता की कृपा हमेशा बनी रहती थी। मंदिर मुख्य राजमार्ग पर होने से अब यहां हजारों यात्री मां के दर्शन कर धन्य होते हैं। प्रत्येक वाहन यहां रुक कर मां के आशीर्वाद के रूप में धूप-अगरबत्ती अपने वाहन के आगे लगाकर अपनी यात्रा की शुरुआत करता है। वाहन चालक और उसमें सवार यात्री गुरना माता से सफल यात्रा की कामना करते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा आने-जाने पर मंदिर की घंटिया बजाई जाती हैं, जिसे सफल यात्रा होने का शुभ संकेत माना जाता है। माता गुरना देवी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर आए दिन भंडाला और हवन पूजन आदि का आयोजन कराते हैं। वर्तमान में गुरना माता पूरे पिथौरागढ़ जिले की आराध्य देवी है। इस मंदिर की मान्यता इतनी व्यापक है कि हर रोज डेढ़ से दो हजार लोग गुरना मां के दर्शन करते हैं। मंदिर में मंदिर के नियमों का पालन करना आवश्यक है। यहां मार्च से लेकर जून तक और सितंबर से लेकर दिसंबर तक कभी भी श्रद्धालु आ सकते हैं। अगर पिथौरागढ़ में एक-दो दिन रुकना चाहते हैं तो आने से पहले कोई होटल बुक कर लीजिए। कुछ गर्म कपड़े, फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा सा कैमरा व पैदल चलने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का जूता अपने साथ अवश्य रखें।

मंदिर की लोकप्रियता से रोजगार मिला

समय के साथ-साथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता बनने लगी कि मां का आशीर्वाद लेने से यात्रा मंगलमय होती है। आज यहां माता का बड़ा मंदिर बन गया है जिसमें स्थानीय तीज त्यौहार पर स्थानीय ही नहीं बल्कि पूरे जिले से श्रद्धालु गुरना मां के दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं। वैसे मंदिर के सामने नियमित रूप से निजी वाहन, सरकारी अथवा सार्वजनिक वाहन रुकते हैं और मां गुरना देवी के मंदिर जाकर आशीर्वाद लेते हैं। सभी यात्री मंदिर में प्रवेश कर टीका लगाते हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही आगे का सफर तय करते हैं। इसी के साथ लगे कुछ छोटे-छोटे होटल भी हैं। गुरना मंदिर का जिक्र अधूरा रहेगा अगर इसके साथ में लगी दुकानों का जिक्र न किया जाए। गुरना मंदिर की प्रसिद्धि के साथ में यहां पर कुछ होटल भी खुले। इन होटलों में उत्तराखंड के सबसे लजीज आलू के गुटके पहाड़ी रायते के साथ परोसे जाते हैं। 2005 तक पिथौरागढ़ की यात्रा करने वाले हर शख्स की जुबान में इन आलू के गुटकों का स्वाद रहता है। हालांकि कभी एक बड़ी कड़ाही में बनने वाले आलू के गुटके अब छोटी कड़ाही में बनते हैं, लेकिन पहाड़ का स्वाद अब भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में इनकी लोकप्रियता और इनसे प्राप्त आमदनी दोनों में गिरावट देखी गई है।

सुर्खियां

विदेशी सोनिया वोटर बनी ?

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी को लेकर सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी पर लंबी चौड़ी प्रेस कांफ्रेंस कर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया तो सोनिया गांधी की नागरिकता वाला बम भी फूट गया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी फिर भी वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ दिया गया था। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दावा किया कि सोनिया गांधी का वोटर आईडी कार्ड उन्हें देश का नागरिकता मिलने से पहले ही मिल गया था। यानी सोनिया गांधी की वोटर आईडी विदेशी नागरिक होते हुए ही बन गई थी। मालवीय का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल हुआ और उन्हें नागरिकता 1983 में मिली। यानी कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एक याचिका अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दायर की गई है। याचिका में मतदाता सूची में उनका नाम शामिल करने के संबंध में सवाल उठाया गया है। याचिका में कोर्ट से पुलिस को इस संबंध में जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया के समक्ष पेश याचिका धारा 175 (4) (जांच का आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति) के तहत दायर की गई है। इसमें पुलिस को इस आरोप की जांच करने के निर्देश देने की मांग की गई है कि सोनिया गांधी 1983 में भारतीय नागरिक बनीं, लेकिन उनका नाम 1980 की मतदाता सूची में कैसे जोड़ा गया था। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने दलील दी कि कुछ दस्तावेजों के अनुसार यह स्पष्ट है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल, 1983 को भारत की नागरिकता ली थी। नारंग का कहना है कि उनका नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल था, जिसे 1982 में हटा दिया गया था। 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद इसे फिर से जोड़ा गया। नारंग ने कहा कि नाम हटाने का कारण कहीं नहीं मिलता। इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले या फॉर्म 8 (ब्यौरे में सुधार के लिए आवेदन) दाखिल करे। लेकिन, इसके लिए जरूरी शर्त यह है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। याचिका में सवाल किया गया है कि 1980 में जब सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया था, तब चुनाव आयोग को कौन से दस्तावेज दिए गए थे? क्या इसमें कुछ जालसाजी हुई है और एक संवैधानिक संस्था के साथ धोखा किया गया है। नारंग ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि पुलिस को उचित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।

धराली गांव होगा शिफ्ट

5 अगस्त को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली गांव की खीर गंगा में आए विनाशकारी सैलाब ने धाराली का नक्शा ही बदल दिया। जहां गुलजार होटल, होमस्टे और बाजार था वहां 20 फीट मलबा खड़ा हो गया। यानी खीर गंगा में बहकर आई सिल्ट ने एक नया पहाड़ बना दिया। इस आपदा में तबाह हुआ धराली गांव अब दोबारा उस जगह नहीं बसेगा। यह फैसला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक के बाद किया है। यानी धराली गांव अब सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। नदियों के किनारे और लैंडस्लाइड वाले संवेदनशील क्षेत्रों में अब किसी तरह का कोई नया निर्माण नहीं होगा। इस तरह की संवेदनशील जगहों पर बसे अन्य गांवों को भी शिफ्ट किए जाने की योजना है। क्योंकि बीते 10 वर्षों में धराली इलाके में तीन आपदाएं आ चुकी हैं। तीन बार गांव तबाह हुआ है, लेकिन हर बार स्थानीय लोगों ने वहां नई इमारतें खड़ी कर लीं। फिलहाल आपदा के बाद से धराली गांव मलबे में दबा है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सेब के बागानों और राजमा की खेती के लिए प्रसिद्ध धराली गांव ऐतिहासिक रूप से प्राचीन काल से ही अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। क्योंकि यह गंगोत्री धाम मंदिर के रास्ते में पड़ता है। स्थानीय लोककथाओं और परंपराओं के अनुसार यह क्षेत्र लंबे समय से स्थानीय गढ़वाली समुदाय का निवास स्थान रहा है। यह गांव अपनी शांत वादियों और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण देश-विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। शासन में अपर सचिव बंशीधर तिवारी का कहना है कि धराली के विस्थापन के लिए स्थानीय लोगों से चर्चा शुरू कर दी है। लोग चाहते हैं कि उन्हें 8 से 12 किलोमीटर दूर लंका, कोपांग या जांगला में बसा दिया जाए। 5 अगस्त को ही हर्षिल में आई आपदा में सेना का कैंप भी बह गया था। इसलिए नया कैंप बनाने के लिए सेना श्रीखंड पर्वत और आसपास के ग्लेशियरों, झीलों की रेकी कर रही है। विनाशकारी आपदा के पहले दिन सरकार ने 4 लोगों की मौत और 30 लोगों के लापता होने की पुष्टि की थी। जबकि 10 अगस्त को कहा गया था कि 15 लोग लापता हैं, इनका कहीं कुछ पता नहीं है। जबकि स्थानीय लोग 60 लोगों के लापता होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन जिनके अपने लापता हैं उनके परिजन अब शव मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

ट्रैक्टर में लगेगा डाटा रिकॉर्डर

देश भर में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। अब इसके लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटरयान संशोधन नियमावली 2025 तैयार की है। इस नियमावली के तहत 1 अक्टूबर 2026 को या उसके बाद सभी ढुलाई वाले ट्रैक्टर एआईएस 140 कोड व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस होंगे। जिस तरह किसी प्लेन के क्रैश होने पर हादसे की जानकारी के लिए ब्लैक बॉक्स होता है। उसी तरह ट्रैक्टरों में भी इवेंट डाटा रिकॉर्डर (ईडीआर) में सारी जानकारी रिकॉर्ड होंगी। इससे दुर्घटना के कारण का पता लगाया जा सकेगा। कई तरह के अन्य बदलाव भी 2026 के बाद बनने वाले ट्रैक्टर और ट्रॉली में किए जाएंगे। इसे लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। यानी केंद्रीय मोटरयान नियमावली 2025 के प्रारूप में जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट संचालित हो रहे हैं, सभी में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगेंगे। जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी। यात्री खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। उत्तर प्रदेश में रोडवेज की बसें एआईएस 140 कोड व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस हो गई हैं। अब आने वाले समय में ट्रैक्टरों को वीएलटीडी से लैस करने का सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। कंपनी से ही ट्रैक्टरों में वीएलटीडी लगकर आएगा। केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मोटरयान (संशोधन) नियमावली 2025 का जो फॉरमेट तैयार किया जा रहा है, उसके मुताबिक 1 अक्टूबर 2026 को या उसके बाद सभी ढुलाई वाले ट्रैक्टर एआईएस 140 के अनुरूप वाहन लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण से लैस किए जाएंगे। वीएलटीडी को एआईएस 16722-2018 के अनुरूप एक आरएफआईडी ट्रांसीवर के साथ इंटीग्रेटेड किया जाएगा। जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी ट्राली से आरएफआईडी डाटा को पढ़ने और उसे बैकएंड पर भेजने में सक्षम होगा। सभी ट्रेलरों में एआईएस 16722-2018 के अनुसार निष्क्रिय आरएफआईडी टैग लगाए जाएंगे। जिससे ट्रैक्टरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक पहचान और युग्मन (जोड़) संभव हो सकेगा। 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद सभी ढुलाई वाले ट्रैक्टरों में महत्वपूर्ण वाहन डाटा को कैप्चर और स्टोर करने के लिए एक इवेंट डाटा रिकॉर्डर लगाया जाएगा। ईडीआर परिचालन घटनाओं का विश्लेषण करने और सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिए आवश्यक मापदंडों को रिकॉर्ड करेगा। 1 अक्टूबर 2026 को या उसके बाद एआईएस 9895-2004 के अनुसार 13 पिन या 13 पोल कनेक्टर लगाए जाएंगे। 1 अप्रैल 2027 को या उसके बाद सभी ढुलाई वाले ट्रैक्टरों और ट्रेलरों की आंतरिक युग्मन प्रणाली 5वां पहिया समय-समय पर संशोधित एआईएस 8007-2004 के अनुरूप होगी। कोड एआईएस 140 कोड प्रमाणन संस्था एआरएआई और आईकैट से अप्रूव होता है। इस कोड पर बनी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को विदेशी सेटेलाइट्स भी लोकेट नहीं कर सकतीं। सिर्फ भारत के सेटेलाइट्स से ही वाहनों की लोकेशन संभव है। भारत के लिए ये कोड काफी सिक्योर है।

धामी ने 25000 नौकरी दी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चार साल के कार्यकाल में युवा वर्ग सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर सामने आया है। क्योंकि धामी सरकार के चार साल के कार्यकाल में रिकॉर्ड 25 हजार युवाओं का सरकारी सेवाओं में चयन हुआ है। हाल ही में जनजाति कल्याण विभाग के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद धामी सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्किल का प्रशिक्षण देने पर विशेष फोकस किया। साथ ही लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चिकित्सा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में स्थाई रोजगार दिया गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के स्तर पर अभी कई विभागों की भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस में हैं। जबकि कुछ विभागों में जल्द ही अंतिम चयन की संस्तुति की जाने वाली है, इससे स्थाई नौकरियों का आंकड़ा और बढ़ जाएगा। धामी सरकार युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल के माध्यम से भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। सरकार का प्रयास है कि पहाड़ का पानी और जवानी, उत्तराखंड के काम आए। युवा पलायन करने के बजाय, रोजगार देने वाले बने। धामी सरकार ने साल 9 नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू की थी, इसके लिए युवाओं को आतिथ्य, नर्सिंग, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में प्रशिक्षण देते हुए जर्मनी और जापान में रोजगार के अवसर मिले। योजना के तहत अब तक 154 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें से 37 युवाओं को जापान में रोजगार मिल चुका है। धामी सरकार ने 2024 में सख्त नकल विरोध कानून लागू करते हुए नकल माफिया की कमर तोड़ने का काम भी किया है। इसके बाद से एक भी परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ है। यही नहीं धामी सरकार पेपर लीक में शामिल 100 से अधिक माफिया को जेल भी भेज चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में उत्तराखंड में होने वाले निवेश से भी युवा लाभान्वित हुए हैं। यानी धामी सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के साथ उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे ले जा रही है।

झुकता है ट्रंप झुकाने वाला हो

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी से पंगा लिया तो खुद ट्रंप अपने ही देश में आलोचना का सामना कर रहे हैं, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की आलोचना हो रही है, तो पीएम नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने ट्रंप को घुटनों पर ला दिया और ट्रंप के सुर बदलने लगे हैं।

केके चौहान

झुकता है ट्रंप, झुकाने वाला चाहिए। नास्त्रेदमस ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि समुद्र किनारे से एक लड़का आएगा और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। यह नेता दुनिया की सियासत में भारत का सम्मान बढ़ाएगा। माइकल डी नोस्त्रेदम, जिन्हें नास्त्रेदमस के नाम से भी जाना जाता है, 16वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी ज्योतिषी और चिकित्सक थे। उन्होंने 1555 में अपनी पुस्तक 'लेस प्रोफेटीज' प्रकाशित की, जो रहस्यमय चौपाइयों का एक संग्रह है, जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि यह चौपाई भविष्यवाणी करती है। आज ये बातें सही लगने लगी हैं। समुद्र किनारे बसे गुजरात में जन्मे नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जो आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से पंगा लिया तो खुद ट्रंप को अपने ही देश में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की आलोचना हो रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने ट्रंप को घुटनों पर ला दिया और ट्रंप के सुर बदलने लगे। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने मीडिया से कहा कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हैं लेकिन यह रिश्ता लंबे समय तक एकतरफा ही रहा। क्योंकि अमेरिका पर भारत 'भारी टैरिफ' लगाता रहा है। भारत की वजह से अमेरिका को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ा है। मीडिया से बातचीत करते समय ट्रंप ने एक बार भी ये नहीं कहा कि भारत रूस से तेल खरीदता है। ट्रंप के हालिया बयानों से लग रहा है कि अमेरिका अब डेमेज कंट्रोल करने में लगा है। उसे समझ आ गया है कि भारत से रिश्ते बिगाड़ने से भारत से ज्यादा नुकसान अमेरिका को होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि ट्रंप को आज नहीं तो कल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले को वापस लेना पड़ेगा। यदि टैरिफ का फैसला वापस होता है तो निश्चित ही यह भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। इसे ऐसे भी समझा जाएगा कि अब नरेंद्र मोदी कूटनीति में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बहुत आगे निकल गए हैं। भारत में कहा जा रहा है कि 'झुकता है ट्रंप झुकाने वाला मोदी चाहिए।' इसका नतीजा भी सामने आने लगा है। 2 सितंबर को अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बैसेंट ने एक पॉजिटिव एप्रोच के साथ कहा कि मुझे लगता है कि अंततः दो महान देश इस समस्या का समाधान बातचीत से निकाल लेंगे। इसके अलावा अमेरिकी दूतावास से दोस्ती की दुहाई और शीर्ष डिप्लोमेट की ओर से वार्ता के लिए दिया जा रहा संदेश, साबित करते है कि अमेरिका, भारत को मैसेज दे रहा है कि बैठकर बात करने से बात बन सकती है।

चीन में मोदी का भौकाल

मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका को बिना ट्रंप का नाम लिए जिस तरह जवाब दिया है उसकी दुनिया की मीडिया में चर्चा है। कहा जा रहा है कि भारत नया विश्वगुरु बन गया है। तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ कहने लगे हैं कि ट्रंप ने मोदी का विरोध करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मोदी से पंगा लेकर ट्रंप अपने ही बुने जाल में खुद फंस गए हैं। विदेशी मीडिया में मोदी-मोदी हो रहा है, मोदी हेडलाइन बने है। ये पहला मौका है जब मोदी की चर्चा दुनिया की वो मीडिया भी कर रही है जो हमेशा भारत विरोधी रही है। कोरोना के समय पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था। आपदा को अवसर में बदला जाना चाहिए। ट्रंप ने भारत के सामने एक आपदा खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने अपने दिमाग से ट्रंप के दबाव को अवसर में बदल दिया। चीन के तिनजियांग शहर में जहां दुनियाभर के पावरफुल नेता मौजूद थे कोई किसी से हाथ मिला रहा था, कोई किसी से बात कर रहा था। वहां मोदी का भौकाल देखकर ट्रंप को झुकना पड़ा, रातों-रातों ट्रंप की सोच बदल गई। ट्रंप को लगा होगा कि ये 2014 से पहले का भारत होगा। ये भारत भी पाकिस्तान जैसा देश होगा, इसलिए ट्रंप अपनी बात भारत के मुंह में डाल देंगे, लेकिन इस बार ट्रंप फेल हो गए। चीन में दुनिया की तीन बड़ी ताकतों को एक साथ देख अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया 'संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। रक्षा से लेकर द्विपक्षीय संबंधों तक, यह हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थाई मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है।' ट्रंप के सुर इसलिए बदले क्योंकि रूस, चीन और भारत की ताकत का अंदाजा उन्हें हो गया है। चीन और भारत की आबादी 280 करोड़ से ज्यादा है। चीन में मिडिल क्लास की आबादी 50 करोड़ है तो भारत में मिडिल क्लास की संख्या 43 करोड़ है। दोनों देशों का बाजार बड़ा है, दोनों देशों में काम करने वाले लोगों की क्षमता ज्यादा है। ये सब देख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी दोस्त माने जाने वाले छोटे से यूरोपीय देश फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब ने ट्रंप से ग्लोबल साउथ, खासकर भारत के संदर्भ में कहा कि विदेश मामलों में ज्यादा गरिमापूर्ण नजरिया अपनाना चाहिए। अमेरिका को दिए एक संदेश में स्टब ने कहा कि विदेश नीति सहयोगी नहीं रही तो अमेरिका और पश्चिमी देश अपना खेल हार जाएंगे।

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बैसेंट ने कहा कि मुझे लगता है कि दो महान देश टैरिफ का समाधान बातचीत से निकाल लेंगे, अमेरिकी दूतावास से दोस्ती की दुहाई और शीर्ष डिप्लोमैट की ओर से वार्ता का संदेश, साबित करता है कि अमेरिका, भारत को बैठकर बात करने का मैसेज दे रहा है।

ब्रिक्स देशों के सामने जी-7 कमजोर

अमेरिका को समझ आ रहा है कि चीन, भारत और रूस के साथ ब्रिक्स देशों की ताकत बढ़ेगी तो जी-7 कमजोर पड़ेगा। ब्रिक्स देशों को समझने के लिए थोड़ा ये आंकड़े देखिए। ब्रिक्स देशों की कुल जीडीपी 42 ट्रिलियन डॉलर है। दुनिया की जीडीपी का 41 फीसदी हिस्सा ब्रिक्स के पास हैं, जिसमें रूस-चीन और भारत शामिल हैं। अमेरिका के गुट जिसे जी-7 कहते हैं उसमें सभी देश अमीर हैं, फिर भी दुनिया की जीडीपी का सिर्फ 30 फीसदी हिस्सा है। ब्रिक्स देशों की जीडीपी ग्रोथ रेट 4 फीसदी है, जबकि जी-7 देशों की ग्रोथ रेट सिर्फ 1.7 फीसदी है। इस तरह ब्रिक्स देश मिलकर ट्रंप की सारी दादागिरी निकाल सकते हैं। भारत खुद के दम पर दुनिया में परचम लहरा रहा है, मोदी जैसा नेता भारत के पास है, जो आज तक सियासत में कभी झुके नहीं। खुद मोदी कह चुके हैं कि वो देश नहीं झुकने देंगे, ट्रंप को जरूरत थी तो हमने नमस्ते किया, अब ट्रंप जब हमारे विरोधी हो गए तो हमने चीन के साथ रिश्ते सुधार लिए। यही राजनीति की सही समझ है। लिहाजा ट्रंप के लिए अब ये संकट खड़ा हो गया है कि यूरोप के देश जो पहले ही अपना वजूद तलाश रहे हैं, उनके साथ मिलकर दुनिया की तीन महाशक्ति भारत, रूस और चीन का कैसे मुकाबला कर पाएंगे? सवाल ये भी क्या 21वीं सदी का किंग साउथ एशिया होगा? ये भी ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाला हो सकता है।

मोदी व पुतिन एक ही कार में

चीन में हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रिट्ज-कार्लटन होटल में द्विपक्षीय बैठक के लिए जाना था। पुतिन अपनी प्रसिद्ध बख्तरबंद लिमोजिन कार से मोदी को होटल ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 10 मिटन तक नरेंद्र मोदी का इंतजार किया। दो शक्तिशाली नेताओं के एक साथ एक कार में 45 मिटन तक बात करने ने सबका ध्यान खींचा। कयास लगाए गए कि जो बात चारदीवारी में नहीं हो सकती थी वो बेहद गोपनीय बातें बख्तरबंद लिमोजिन कार में की गई। यह मुलाकात कोई साधारण गपशप नहीं थी, बल्कि दो बड़े नेताओं के बीच गहरी और गोपनीय चर्चा का हिस्सा थी। हालांकि मीडिया के पूछने पर पुतिन ने कहा यह कोई राज नहीं है, मैंने उन्हें (मोदी) अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप से हुई बातचीत के बारे में बताया है। बातचीत इतनी अहम थी कि उसे बीच में रोकना मुनासिब नहीं था इसलिए दोनों एक घंटे तक कार में ही रहे। दो बड़े नेताओं को इस तरह एक कार में देखकर अमेरिका भी निश्चित रूप से हैरान हो गया होगा।

टैरिफवार को करारा जवाब

चीन के तिआनजिन में आयोजित एसओसी समिट में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ने दुनिया का ध्यान खींचा है। तीनों बड़े नेताओं की गर्मजोशी और एकजुटता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफवार को करारा जवाब दे दिया है। एससीओ समिट के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना जवाब दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था को ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा था, भारत को झुकाने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व वाले भारत की न तो इकोनॉमी डेड है और ना ही भारत किसी के सामने झुकता है। यहां तक की चीन के साथ भी रिश्ता बराबरी पर होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन की धरती से ही ऐलान कर दिया है तुर्की हो या फिर पाकिस्तान कोई भी आतंकवाद का साथ देगा तो ठीक नहीं होगा। इसके समर्थन में शी जिनपिंग ने कहा कि सभी देशों को न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर चलना चाहिए और मिलकर कोल्ड वॉर वाली मानसिकता, गुटबाजी और दबाव बनाने जैसी हरकतों का विरोध करना चाहिए. जिनपिंग की ये बातें ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ को लेकर तो थी ही, साथ ही पाकिस्तान ने जो स्थिति भारत के साथ बना रखी है, उसे भी नसीहत देने वाली थी।

- **राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त यूरोपीय देश फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब ने ट्रंप से ग्लोबल साउथ, खासकर भारत के संदर्भ में, विदेश मामलों में ज्यादा गरिमापूर्ण नजरिया अपनाने को कहा है, स्टब ने कहा कि विदेश नीति सहयोगी नहीं रही तो अमेरिका और पश्चिमी देश अपना खेल हार जाएंगे।**
- **अमेरिका को समझ आ रहा है कि चीन, भारत और रूस के साथ ब्रिक्स देशों की ताकत बढ़ेगी तो जी-7 कमजोर पड़ेगा, ब्रिक्स देशों की जीडीपी 42 ट्रिलियन डॉलर है, अमेरिका के गुट जिसे जी-7 कहते हैं उसमें सभी देश अमीर हैं, फिर भी दुनिया की जीडीपी का सिर्फ 30 फीसदी हिस्सा है।**
- **पीएम मोदी ने ट्रंप की गलत फहमी दूर कर दी, यानी किससे रिश्ता रखना है, किससे तोड़ना है, ये भारत खुद तय करेगा, किसी के कहने पर भारत अपनी विदेश नीति तय नहीं करेगा, चीन और भारत के रिश्ते चुनौती भरे हैं, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई है।**

ट्रंप की गलत फहमी दूर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति और नीयत यही थी कि वह भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करें। भारत और रूस के रिश्तों में दरार पैदा करें, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप की गलत फहमी दूर कर दी, यानी किससे रिश्ता रखना है, किससे तोड़ना है, किससे तेल खरीदना है, ये भारत खुद तय करेगा। किसी के कहने पर भारत अपनी विदेश नीति तय नहीं करेगा। अमेरिका यही सोचता था कि भारत और चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ कभी नहीं पिघलेगी, लेकिन पीएम मोदी ने पासा पलट दिया। भले ही भारत और चीन की दोस्ती की राह में फूल कम और कांटें ज्यादा हों, लेकिन एक नई शुरुआत जरूर हो गई है। भारत का नजरिया साफ है कि उसकी विदेश नीति किसी प्रभाव या दवाब से तय नहीं होगी। अगर भारत के हित को प्रभावित करने की कोशिश हुई तो वह अपनी रणनीति और कूटनीति दोनों बदल देगा। आज जापान के साथ भारत कारोबार बढ़ा रहा है, चीन ने संकेत दिए तो रिश्तों की खाई पाटने की शुरुआत भी होगी। एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के मुंह पर साफ कह दिया कि आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकती। एससीओ घोषणा-पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी के साथ सभी मुल्कों ने एकजुटता दिखाई। या यूं कहें कि पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी। ये मोदी के भारत की ताकत का एहसास करती है। यही नए भारत की नीति है। ये नए भारत की ताकत है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद करने वाले अजरबैजान की हेकड़ी निकाल दी। अजरबैजान एससीओ का सदस्यता बनना चाहता था, लेकिन भारत ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर रोक लगा दी। ●

हर तरफ तबाही

इस मॉनसून सीजन ने हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड को ऐसे जख्म दिए हैं, जिन्हें भरने में न जाने कितने साल लग जाएंगे, कुछ इलाकों में तो ऐसी तबाही मची कि क्षेत्र का भूगोल ही बदल गया, गढ़वाल हो या कुमाऊं उत्तराखंड के दोनों मंडलों में भारी बारिश न जमकर तांडव किया है।

अफजल फौजी
नैनीताल

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं तो कहीं नई झीलें स्थानीय लोगों के साथ सरकार को डरा रही हैं। नदी, नाले सब उफान पर हैं, पुल, बस्ती, सड़कें सैलाब में बह रहे हैं या मलवे में दब गए हैं। यानी तीन राज्यों का बुनियादी ढांचा और सुविधाएं सब कुछ तहस नहस हो गया है। सितंबर आ गया, लेकिन मानसून है कि लौटने का नाम ही नहीं ले रहा। मौसम विभाग रोजाना अलर्ट जारी करता है। उत्तरी भारत में मुख्य रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व जम्मू में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं जिससे स्थानीय निवासियों के साथ पर्यटन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बहुत से स्थानों पर भूस्खलन का खौफ है। लैंडस्लाइड से सड़कें तबाह और बर्बाद हो गई है, तो बहुत सी सड़के जमीन में धंस गई हैं। राज्य सरकारें पहाड़ी इलाकों में लोगों को नहीं जाने की सलाह दे रही हैं। होटल मालिकों और होम स्टे के संचालकों का कहना है कि सितंबर में त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार तो उनका कारोबार ही तबाह हो गया है। क्योंकि आने वाले दिनों में वर्षा के अनुमान के कारण पर्यटक अब दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो रहे है। उत्तराखंड में यह साल मॉनसून के लिहाज से आफत भरा रहा है। इस मॉनसून सीजन ने हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड को ऐसे जख्म दिए हैं, जिन्हें भरने में न जाने कितने साल लग जाएंगे। कुछ इलाकों में तो ऐसी आपदा आई कि क्षेत्र का भूगोल ही बदल गया। गढ़वाल हो या कुमाऊं उत्तराखंड के दोनों मंडलों में भारी बारिश न जमकर तांडव किया है।

- **इस साल मणिमहेश यात्रा के दौरान 16 लोगों की मौत हुई है, इनमें से सात श्रद्धालुओं की मौत मणिमहेश कैलाश परिक्रमा के दौरान हुई, जबकि नौ ने रास्ते में ही दम तोड़ा, भारी बारिश की वजह से राधा अष्टमी पर मणिमहेश डल झील में होने वाला पारंपरिक शाही स्नान भी इस बार नहीं हो सका।**
- **हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा तबाही हुई है, इस साल बारिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के आंकड़ों के अनुसार अकेले अगस्त में राज्य में 431.3 मिमी बारिश हुई, जो 1949 के बाद अगस्त में हुई सबसे अधिक बारिश है।**

उत्तराखंड को जन-धन की हानि

उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़े गवाह है कि इस मानसून सीजन में 75 लोगों की जान जा चुकी है। 90 से ज्यादा लोग लापता हैं। जिन्हें खोजने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आदि कई विभाग सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। घायलों का आंकड़ा भी 107 के पार है, वहीं करोड़ों रुपये की नीजि व सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। इनमें 226 मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं। लगभग 30 से अधिक घर ऐसे हैं जिन्हें गंभीर क्षति पहुंची है। जबकि 1800 से ज्यादा मकान को मरम्मत की जरूरत है। बारिश से वन्यजीवों का जीवन भी खतरे में पड़ा है, लेकिन बेजुबानों के साथ वन संपदा के नुकसान का आकड़ा किसी के पास नहीं है। पशु पक्षी सब कुदरत के कहर का शिकार हुए हैं। बारिश से पशुपालकों को भी भारी नुकसान का अनुमान है। भूस्खलन और बाढ़ की वजह से 1400 से अधिक मवेशियों की मौत हुई है। पशुपालकों के साथ किसानों व फल उत्पादकों की 190 हेक्टेयर से अधिक में लगी फसल बारिश में बह गई है। आपदा ग्रस्त बहुत से गांव जिला और तहसील मुख्यालय से कट हुए हैं। बात सरकार को बारिश से हुए नुकसान की करें तो लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा 554.38 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। लोकनिर्माण विभाग की सड़कें, पुल, पुलिया बारिश के सैलाब में बह गए हैं। दूसरे नंबर पर ऊर्जा विभाग को 448 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यानी बारिश से ऊर्जा विभाग की लाइने, पोल सब बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं। तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को क्षति पहुंची है। जिसके तहत बनी सड़क व पुलिया बारिश की भेंट चढ़ गई। यानी इस योजना के तहत सरकार को 415 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। चौथे नंबर पर सिंचाई विभाग को 400 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान अभी तक हो चुका है। इसके साथ ही पेयजल निगम को 90 करोड़ रुपये की क्षति पहुंची है, लघु सिंचाई विभाग को 35 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। पंचायती राज विभाग को भी 10 करोड़ रुपये का नुकसान बताया गया है। यानी अकेले उत्तराखंड सरकार को यह मानसून सीजन करीब 2000 करोड़ रुपये का पड़ा है। हालांकि अभी कुछ जिलों की रिपोर्ट शासन को नहीं मिली है। बारिश का सितम जारी रहा और सैलाब यूं ही आता रहा तो ये नुकसान और ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि सितंबर में भी उत्तराखंड में बारिश का सितम जारी रहा है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन का कहना है कि उत्तराखंड में धराली और थराली जैसी आपदा के बाद सरकार को बहुत से परिवारों का पुनर्वास करना है, लिहाजा उनके पुनर्वास की योजना बनाकर तथा मानसून सीजन में हुए नुकसान का आकलन करके आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाना है। ताकि केंद्र सरकार से आपदा राहत के लिए फंड मिल सके।

सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तरकाशी जिला

इस साल मॉनसून के शुरुआत में ही उत्तरकाशी जिले में हाईवे पर पहाड़ से पानी के साथ सैलाब आया था जिसमें सात मजदूर बह गए थे, इनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। उत्तरकाशी के ही धराली में 5 अगस्त को खीरगंगा में आए प्रलयकारी सैलाब के बाद से 65 लोग अभी तक लापता है। उत्तरकाशी के अलावा चमोली के थराली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल में भी बारिश से कई लोगों की जानें गई है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान और मौतें उत्तरकाशी जिले में हुई है। गढ़वाल के मुकाबले कुमाऊं में जान माल का नुकसान बहुत कम हुआ है। पिथौरागढ़ जिले के देवतपुरचौड़ा गांव में पहाड़ी से बोल्डर गिरने से एक किशोर की मौत हुई थी तथा दो लोग घायल हुए थे। गांव के मंदिर और स्कूल को भी नुकसान पहुंचा था। कुल मिलाकर बारिश जिस तरह की तबाही मचा रही है उससे पहाड़ों पर रहने वाले परिवारों की नींदें उड़ी हुई है। ज्यादातर परिवार रातों को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं वो सो जाएं लैंडस्लाइड के साथ आए बोल्डर उनके घर और परिवार को तबाह न कर दें। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले परिवार रातों को जाग रहे हैं।

हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही

सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। इस साल हुई बारिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के आंकड़ों के अनुसार अकेले अगस्त में राज्य में 431.3 मिमी बारिश हुई, जो 1949 के बाद अगस्त में हुई सबसे अधिक बारिश है। 1901 के बाद से दर्ज किए गए बारिश के आकड़ों से पता चलता है कि 121 वर्षो बाद ये नौवीं सबसे अधिक बारिश है। इससे पहले, 1927 में 542.4 मिमी बारिश दर्ज की गई थी, जो अब तक की सबसे अधिक बारिश थी। यह बारिश सामान्य से 68 प्रतिशत बहुत ज्यादा है। क्योंकि सामान्य रूप से अगस्त में

बारिश जिस तरह की तबाही मचा रही है उससे पहाड़ों पर रहने वाले परिवारों की नींदें उड़ी हुई है, ज्यादातर परिवार रातों को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, उन्हें डर रहता है कि कहीं वो सो गए तो लैंडस्लाइड के साथ आए बोल्डर उनके घर और परिवार को तबाह न कर दें।

256.8 मिमी बारिश होती रही है। अकेले अगस्त में कांगड़ा में सबसे अधिक 816.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। जबकि लाहौल-स्पीति में सबसे कम 129.7 मिमी बारिश हुई। बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और ऊना जैसे जिलों में भी सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश हुई। हमीरपुर, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में भी सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। मानसून सीजन में 20 जून से 31 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश से 320 लोगों की जान जा चुकी है और 379 लोग घायल हुए हैं। जबकि 40 लोग अभी लापता हैं। बारिश की वजह से 4,569 कच्चे-पक्के घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। 3,710 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं तथा 1,885 पालतू पशुओं की मौत हुई है। कुल मिलाकर राज्य की तीन करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति बारिश की भेंट चढ़ गई है। बारिश के कारण मंडी जिले में 282 सड़कें, शिमला में 255, चंबा में 239, कुल्लू में 205 और सिरमौर जिले में 140 सड़कें पूरी तरह बंद हो गई।

मणिमहेश यात्रा अधूरी रही

बारिश के कारण चंबा जिले में 25 अगस्त से लगातार बारिश के कारण 27 अगस्त को मणिमहेश यात्रा रोक दी गई। इस साल ये यात्रा 15 अगस्त से शुरू हुई थी और 8 सितंबर को यात्रा का समापन होना था, लेकिन भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने इसे समय से पहले रोकने का फैसला किया। भारी बारिश के कारण यात्रा के दौरान हुए लैंडस्लाइड से जगह-जगह सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त होने से 15000 से अधिक श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा मार्ग में फंस गए। इस साल मणिमहेश यात्रा के दौरान 16 लोगों की मौत भी हुई है। 16 में से सात श्रद्धालुओं की मौत मणिमहेश कैलाश परिक्रमा के दौरान हुई, जबकि नौ ने तीर्थयात्रा मार्ग के अलग-अलग स्थानों पर दम तोड़ा। ऐसा पहली बार हुआ है कि मणिमहेश यात्रा को समय से पहले रोका गया है। भारी बारिश की वजह से राधा अष्टमी पर मणिमहेश डल झील में होने वाला पारंपरिक शाही स्नान भी इस बार नहीं हो सका। डल झील के बजाय 84 मंदिर में इस रस्म को पूरा किया गया। ऐसा शायद पहली बार हुआ हो, जब मणिमहेश में राधा अष्टमी पर स्नान नहीं हुआ। जबकि राधा अष्टमी पर मणिमहेश में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रही है, लेकिन इस बार नजारा बदला हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में होने वाली मणिमहेश यात्रा में देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि यहां शिव का निवास है। मणिमहेश को पंच कैलाशों में गिना जाता है। मणिमहेश समुद्रतल से करीब 14500 फीट की ऊंचाई पर है। हिमाचल के चंबा जिले के हड़सर से मणिमहेश के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। 13 किलोमीटर के कठिन पैदल मार्ग में कई जगह खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। यह चढ़ाई आमतौर पर दो दिनों में पूरी की जाती है, जिसमें पहला दिन हड़सर से धनछो तक और दूसरा दिन धनछो से मणिमहेश झील तक ट्रैक किया जाता है। यहां ऑक्सीजन की कमी के कारण भी कई बार श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। मणिमहेश को विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा के बराबर दर्जा दिया जाता है। मणिमहेश यात्रा जन्माष्टमी से शुरू होती है और राधा अष्टमी पर शाही स्नान के साथ इसका समापन होता है। इस बार की बारिश से हुई तबाही को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज देने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया गया है और जिन लोगों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें 7 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यदि घर के अंदर का सामान नष्ट हुआ है तो 70,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में और दिए जाएंगे। सीएम ने अधिकारियों को बारिश के हुई तबाही की रिपोर्ट बनाने के लिए भी कहा है ताकि रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा सके।

वैश्विक

टैरिफ लगाने की 5 वजह

ट्रंप और मोदी की मुलाकात कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन होनी थी, लेकिन ईरान-इजराइल टेंशन की वजह से ट्रंप अचानक अमेरिका लौट गए और मोदी को फोन कर वॉशिंगटन आने के लिए कहा, किंतु मोदी ने वॉशिंगटन जाने से इनकार कर दिया, ट्रंप को ये बात चुभ गई।

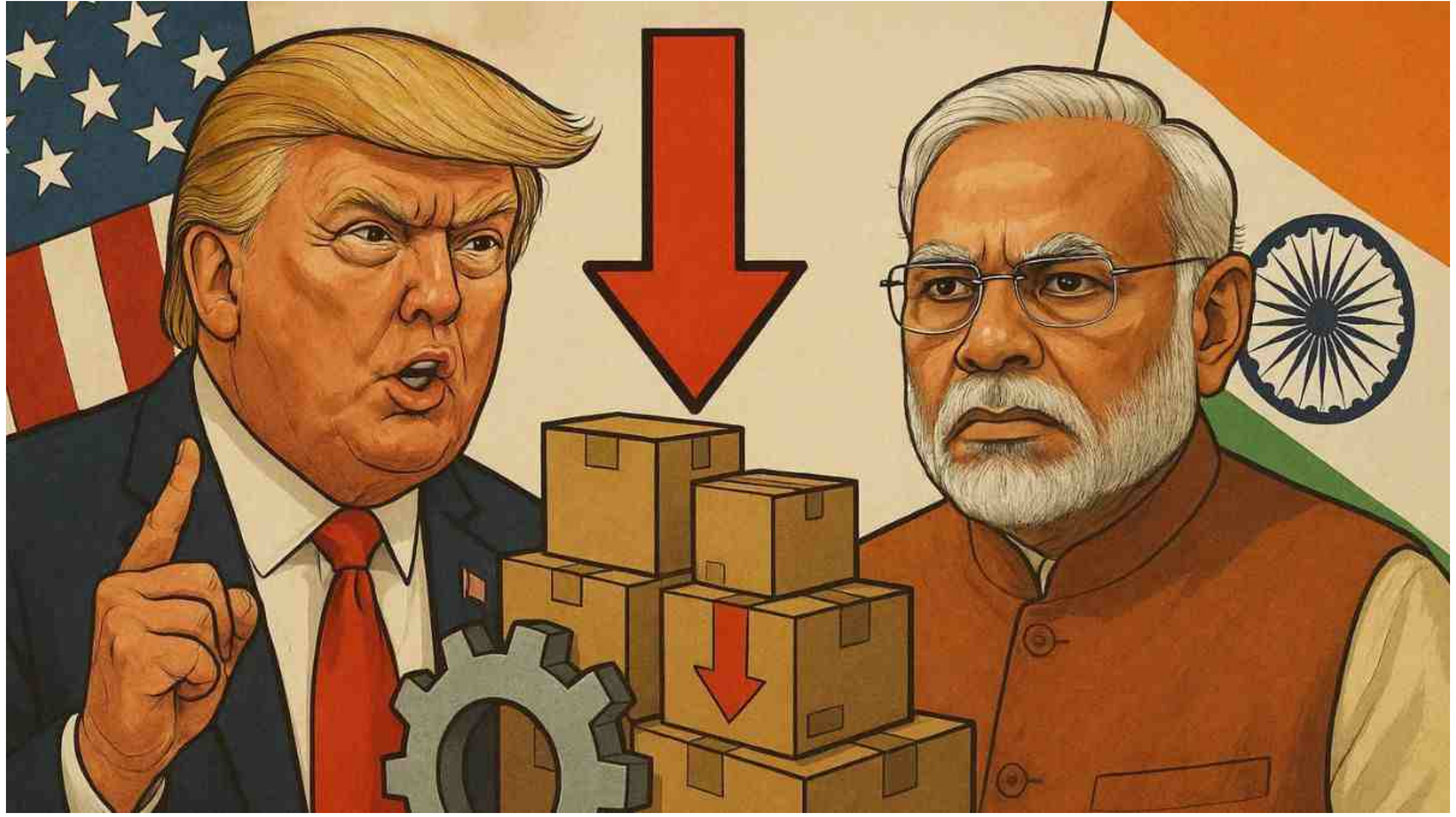

शालिनी चौहान
नई दिल्ली

दुनिया भर में आज इस बात की चर्चा है कि अमेरिका ने भारत पर सबसे ज्यादा 50 प्रतिशत टैरिफ क्यों लगाया? अमेरिका में भी लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर चीजों को अपने देश में महंगा क्यों कर दिया? खैर टैरिफ को लेकर जितने मुंह, उतनी बातें हो रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि ट्रंप मानते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने दावा किया कि रूस से तेल खरीदकर भारत ने पुतिन को युद्ध लड़ने में आर्थिक मदद की है। अगर मोदी रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो टैरिफ वापस हो जाएगा और रूस यूक्रेन का युद्ध भी रुक जाएगा। क्या अमेरिका के इस तर्क में कोई दम है? क्योंकि अमेरिका के ही एक और एक्सपर्ट का तर्क दूसरा है, ये भी ट्रंप के ही सलाहकार हैं। अमेरिका की नेशनल इकॉनमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हैसेट का कहना है कि भारत पर इतना टैरिफ लगाने की वजह ये है कि भारत ने अमेरिका के कृषि और डेयरी सेक्टर की कंपनियों के लिए अपना बाजार खोलने से मना कर दिया। मोदी इस बात पर अड़े हैं कि वो अपने किसानों, दुग्ध उत्पादकों और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं कर सकते। तो दूसरी ओर ट्रंप भी अड़े हुए हैं, इसलिए कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। खुद ट्रंप मानते हैं कि रूस-यूक्रेन में युद्ध से अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्री को भारी मुनाफा हो रहा है। फिर भी अमेरिका युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन असली वजह कुछ और है। दरअसल दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच कर बचकानी हरकतें कर रहे हैं।

50 फीसदी टैरिफ लगाने की 5 वजह

वैश्विक राजनीतिक के जानकार ट्रंप के टैरिफ लगाने की 5 वजह मानते हैं इनमें पहली वजह ये है कि जुलाई 2019 में जब इमरान खान अमेरिका गए थे तो ट्रंप ने उनसे कह दिया था कि कश्मीर के मसले पर मोदी ने उनसे मध्यस्थता करने को कहा है। ट्रंप के इस झूठे बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जाहिर की और ट्रंप को बता दिया था कि भारत, कश्मीर के मसले पर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। ट्रंप और मोदी के बीच तल्खी की दूसरी वजह, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हुई एक घटना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप और कमला हैरिस दोनों उम्मीदवारों से मिलने का समय मांगा था। ट्रंप ने तो समय दे दिया था, ट्रंप ने अपनी रैली में इसकी घोषणा भी कर दी कि मोदी मुझसे मिलने आ रहे हैं। लेकिन अंतिम क्षण में कमला हैरिस ने मोदी को मिलने का समय नहीं दिया। मोदी को लगा कि सिर्फ एक पार्टी के उम्मीदवार से मिलना ठीक नहीं होगा, इसलिए मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात कैंसिल कर दी थी। ट्रंप को मोदी का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। तीसरी बात भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का श्रेय लेने से जुड़ी है। ट्रंप अब तक 42 बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया। सीजफायर का फैसला उनके कहने पर हुआ। हालांकि बीच-बीच में वो सीजफायर कराने से मुकरते भी रहे हैं। किंतु भारत कई बार ये साफ कर चुका है कि सीजफायर का फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ। संसद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम में दुनिया के किसी देश की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन ट्रंप सुनने को तैयार नहीं हैं। ट्रंप पर तो शांति दूत बनने के भूत सवार है, इसलिए वो अब भी सीजफायर कराने का दावा करते हैं। चौथी वजह, ट्रंप और मोदी की मुलाकात कनाडा में होनी थी। जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों की मीटिंग तय थी, लेकिन ईरान-इजराइल टेंशन की वजह से ट्रंप जी-7 सम्मेलन छोड़ कर अचानक अमेरिका लौट गए और मोदी को फोन कर वॉशिंगटन आने के लिए कहा। ये वही दिन था जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व्हाइटहाउस में ट्रंप से लंच पर मिलने वाले थे। लेकिन मोदी ने वॉशिंगटन जाने से इनकार कर दिया। ट्रंप को ये बात चुभ गई। ये चार वो कारण हैं जिनकी वजह से चिढ़ कर ट्रंप ने टैरिफ लगाकर मोदी को टारगेट किया।

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप और कमला हैरिस दोनों से मिलने का समय मांगा था, ट्रंप ने समय दे दिया और अपनी रैली में इसकी घोषणा भी कर दी, लेकिन अंतिम क्षण में कमला हैरिस ने मोदी को समय नहीं दिया, मोदी को लगा कि एक पार्टी के उम्मीदवार से मिलना ठीक नहीं होगा, इसलिए मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात कैंसिल कर दी थी।

ट्रंप ने मोदी को फोन किया

ट्रंप और मोदी के रिश्तों में खटास बढ़ने की पांचवीं वजह जर्मनी मीडिया ने बताई। जर्मनी के बड़े अखबार 'फ्रैंकफर्टर ऑलगेमाइन जितुंग' का दावा है कि 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने मोदी को चार बार कॉल किया, लेकिन मोदी ने ट्रंप की कॉल रिसीव नहीं की। इसकी वजह क्या थी? ये औपचारिक रूप से किसी ने नहीं बताई। लेकिन पता ये चला है कि ट्रंप अक्सर दुनिया के नेताओं को अपने पर्सनल नंबर से कॉल करते हैं। जिन नेताओं को ट्रंप ने अपने पर्सनल नंबर दिए हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी है। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने मोदी को अपना पर्सनल नंबर दिया था। लेकिन इस बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने सुरक्षा एजेंसियों के कहने पर अपना फोन और नंबर दोनों बदल दिए। शायद उन्होंने अपने नए नंबर से ही प्रधानमंत्री मोदी के मोबाइल पर कॉल किया था। किंतु नया नंबर होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की कॉल्स रिसीव नहीं की होगी। लगता है ट्रंप ने इस बात को दिल पर ले लिया और अब टैरिफ को बदले का हथियार बना लिया है।

ट्रंप के लिए मोदी को समझना आसान नहीं

डोनाल्ड ट्रंप को भारत से जो भी समस्या हो पर एक बात तो पक्की है कि राज कोई बड़ा है। सिर्फ रूस से तेल खरीदने को लेकर तो भारी भरकम टैरिफ नहीं लगाई जा सकती। क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप इतनी मदद भेजते हैं कि उसके आगे रूस को भारत के तेल से होने वाली कमाई आटे में नमक के बराबर है। ट्रंप की समस्या इतनी बड़ी है कि उन्होंने भारत को चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपनी गोद में बैठा लिया है। जबकि भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा कर वर्षों की दोस्ती में दरार पैदा डाल दी है। क्योंकि जिस चीन से अमेरिका की खुली दुश्मनी है, उस तक को टैरिफ में छूट दे रखी है। ट्रंप के इस रवैये की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। मोदी ने ट्रंप के आगे झुकने से इनकार कर दिया। शायद ट्रंप ने मोदी को समझने में भारी से भारी गलती कर दी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह चुके हैं कि रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है, लेकिन उस पर अधिक टैरिफ नहीं लगाया गया है। वहीं रूस से सबसे अधिक एलएनजी यूरोप खरीदता है। लेकिन उनके साथ अलग मानदंड अपनाए गए हैं, ये अनुचित है। अगर दलील ऊर्जा को लेकर है और कौन रूस से अधिक खरीदता है उसे लेकर है, तो भारत इन दोनों मामलों में पीछे है। एस जयशंकर का कहना था कि दुनिया ने कभी ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं देखा जिन्होंने अपनी विदेश नीति को इतने सार्वजनिक तौर पर संचालित किया हो। अमेरिका में भी भारत को लेकर ट्रंप की नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं और चिंता जाहिर की जा रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे सलाहकार और अमेरिका की नेशनल इकॉनमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हैसेट का कहना है कि भारत पर इतना टैरिफ लगाने की वजह ये है कि भारत ने अमेरिका के कृषि और डेयरी सेक्टर की कंपनियों के लिए अपना बाजार खोलने से मना कर दिया।

अमेरिका में ट्रंप की आलोचना

ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर खुद अपने देश में आलोचना का सामना कर रहे हैं। अमेरिका की रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई है और कहा है कि अमेरिका को समझना चाहिए कि चीन का सामना करने के लिए उसे भारत जैसे मित्र की जरूरत है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि ट्रंप अपनी नीतियों से अपने सहयोगियों को दूर कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी भारत पर लगाए टैरिफ का विरोध कर रहे हैं। 20 अगस्त को निकी हेली ने अमेरिकी मैगजीन न्यूजवीक में भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर ट्रंप की नीति पर लेख तक लिख डाला। निकी हेली ने लिखा कि व्यापार विवाद और रूस से तेल आयात जैसे मुद्दों पर सख्त बातचीत जरूरी है, लेकिन हमें असली मकसद नहीं भूलना चाहिए। चीन का सामना करने के लिए अमेरिका को भारत जैसे दोस्त की जरूरत है। निकी हेली और डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ही रिपब्लिकन पार्टी से हैं, लेकिन कई मौकों पर निकी हेली ने ट्रंप का खुलकर विरोध किया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि ट्रंप अपनी नीतियों से अपने दोस्तों को दूर कर रहे हैं। जॉन केरी एक डेमोक्रेट हैं और पांच बार सीनेटर रह चुके हैं। वो ओबामा प्रशासन के दौरान 2013 से 2017 के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री रहे हैं। जॉन केरी ने कहा राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच जो तनाव है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि एक महान देश को अपनी महानता जताने के लिए हमेशा लोगों को धमकियां देना जरूरी नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कूटनीति के जरिए हल ढूंढने की बजाय आदेश और दबाव डालने का तरीका अपनाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी भारत पर लगाए गए ट्रंप के टैरिफ का कड़ा विरोध किया है। जॉन बोल्टन ने एक इंटरव्यू में कहा, ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ लगाया, लेकिन चीन पर नहीं लगाया जबकि वो भी रूस से तेल खरीदता है। इससे भारत, चीन और रूस के करीब जाएगा। ट्रंप प्रशासन की यह अनदेखी भविष्य में घातक हो सकती है। उन्होंने पुतिन के भारत दौरे पर आने की योजना और 2018 के बाद पहली बार पीएम मोदी के चीन जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसका अमेरिका पर नकारात्मक असर पड़ा है। बोल्टन, ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे लेकिन 2019 में ट्रंप ने उन्हें हटा दिया था। तब से वह ट्रंप के कट्टर विरोधी हो गए हैं। उन्होंने 2020 में एक संस्मरण लिखा था जिसमें ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा था कि ट्रंप को विदेश नीति के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अमेरिका के अर्थशास्त्री से लेकर बड़े बड़े नेता ट्रंप की आलोचना करते हुए दावा कर रहे हैं कि ट्रंप अपना फैसला बदल दें, क्योंकि टैरिफ से भारत का कुछ नहीं होगा, लेकिन अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा। अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ दावा करते हैं कि ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले से ब्रिक्स संगठन मजबूत होगा। इस तरह ट्रंप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। रिचर्ड वोल्फ का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अमेरिका का भारत को ये बताना कि उसे क्या करना है, 'ये ऐसा है जैसे कोई चूहा, हाथी को मुक्का मार रहा हो।'

मदरसा बोर्ड खत्म होगा

उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 व उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी व फारसी मदरसा अधिनियम 2019 लागू है, नए विधेयक के लागू होने के बाद यह सभी नए अधिनियम के अधीन हो जाएंगे, यानी एक जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड भंग हो जाएगा और उसकी जगह 'उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण' की स्थापना की जाएगी।

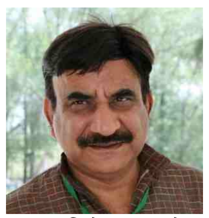

दिनेश मानसेरा
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के बाद एक और ऐसा फैसला लिया है। यह फैसला नए शिक्षा सत्र से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म करने का है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड 2026 में देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां मदरसा बोर्ड की जगह 'अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम' होगा। मदरसा बोर्ड की जगह प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। प्राधिकरण के तहत सिर्फ मुस्लिम समाज को ही अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल नहीं होगा बल्कि उसके साथ ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और सिख समाज को भी अल्पसंख्यकों वाली सुविधाएं मिलेंगी। यानी राज्य में मदरसा बोर्ड के युग का पटाक्षेप हो जाएगा। धामी सरकार का यह निर्णय न केवल प्रशासनिक ढांचे में बदलाव लाएगा, बल्कि इसे शिक्षा के क्षेत्र में 'एक समान नीति' लागू करने की दिशा में एक बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। नए विधेयक से अल्पसंख्यक संस्थानों के दायरे का विस्तार होगा। क्योंकि अभी तक अल्पसंख्यक के नाम पर सारी सुविधाएं मुस्लिम समुदाय को ही मिलती आ रही थी। तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास रखने वाली कांग्रेस ने 'अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम' लागू होने से पहले ही विरोध शुरू कर दिया है। जबकि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष से लेकर कुछ मुस्लिम इसे धामी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय बता रहे है। सरकार 'अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम' को इसी मानसून सत्र में पारित कराना चाहती है। यानी जैसे ही उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 राज्य में लागू होगा, वैसे ही उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाएगा। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार का मकसद उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों को अत्याधिक और स्मार्ट शिक्षा से जोड़ना है फिर चाहे वो मुस्लिम हों या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र हों। यह विधेयक 17 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में लाया गया था। बैठक में इस विधेयक पर बकायदा चर्चा हुई और उसके बाद कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर भी लगा दी थी। विधेयक के विधानसभा में पास होने के बाद अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को एक जगह लाया जाएगा।

अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा

अब तक उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी व फारसी मदरसा अधिनियम 2019 लागू है। इस विधेयक के लागू होने के बाद यह सभी नए अधिनियम के अधीन हो जाएंगे। यानी एक जुलाई 2026 से मौजूदा मदरसा बोर्ड को भंग कर उसकी जगह 'उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण' की स्थापना की जाएगी। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और ग्यारह सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। अध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय का एक शिक्षाविद् होगा, जिसे 15 वर्ष या उससे अधिक का शिक्षा प्रबंध का अनुभव हो। इस प्राधिकरण से राज्य के 452 मदरसों समेत सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को नई मान्यता लेनी होगी। सरकार का कहना है कि यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। मान्यता पाने के लिए शैक्षिक संस्थानों को प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए शैक्षिक संस्थानों की संपत्ति उनके खुद के नाम पर होनी चाहिए। यानी सरकार की मंशा साफ है कि अब कोई भी गली मोहल्ले में मदरसा खोलकर शिक्षा के नाम पर दुकान नहीं चला पाएगा। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों बेहतर शिक्षा देना सरकार का मकसद है।

शिक्षा पर प्राधिकरण की नजर होगी

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम उत्तराखंड में 2026 के शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में गुरुमुखी और पाली भाषा भी पढ़ना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही सभी अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार भी मजबूत होंगे। इस अधिनियम के बनने से अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक संस्थानों में पारदर्शिता पूरी तरह से बनी रहेगी। उन्हें इस पारदर्शिता के बाद मान्यता भी आसानी से मिलेगी। कई बार देखा गया है कि कई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में अनुदान का दुरुपयोग होता रहा है। उस पर भी कड़ाई से नजर रखी जा सकेगी। सीएम धामी का कहना है कि अधिनियम बनने के बाद ऐसा नहीं है कि मदरसे में जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, वो नए अधिनियम के तहत बंद हो जाएगी। यानी धार्मिक शिक्षा पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। लेकिन इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि उत्तराखंड के अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में जो पढ़ाई करवाई जा रही है, वो उत्तराखंड बोर्ड के मानक के तहत हो। इस पर भी नजर रखी जाएगी। नया कानून लागू होने के बाद सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संसाथानों को नए सिरे से प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। प्राधिकरण का काम शिक्षा की गुणवत्ता, वित्तीय मामलों की देखरेख और धार्मिक सद्भावना जैसी तमाम शिक्षा नजर रखना होगा। इसके अलावा प्राधिकरण संस्थानों के कार्यों में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

छात्रों के हित में नया अधिनियम

उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि नया अधिनियम उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस अधिनियम के बनने से आने वाले समय में अल्पसंख्यक और खासकर मुस्लिम समुदाय के छात्रों को बेहद फायदा होने वाला है। इससे हमारी धार्मिक मान्यताओं और शिक्षा पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बल्कि इस अधिनियम के बनने से मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी भविष्य में आईएएस, आईपीएस समेत बड़ी-बड़ी नौकरियों में जा सकेंगे। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कुख्यात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा का कहना है कि राज्य सरकार हाल में हुए पंचायत चुनावों में हार की बौखलाहट निकाल रही है। ऐसे कानून बना रही है जिससे एक खास समुदाय को प्रताड़ित किया जा सके। पंचायत चुनाव में शर्मनाक हार को छिपाने के लिए ही मदरसा शिक्षा बोर्ड को खत्म किया जा रहा है। भाजपा के राज में अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, सड़कें दुरुस्त करने के लिए पैसा नहीं है, रोजगार की ठोस नीति नहीं है, लेकिन हिंदू-मुस्लिम का नैरेटिव सेट करने का एजेंड़ा है। अगर शिक्षा उन्नयन का उद्देश्य है तो नया प्राधिकरण बनाने की क्या जरूरत है? कानून ऐसा बनाते, जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधरे। इससे साफ होता है भाजपा की नीयत ठीक नहीं है। यह सच है कि मदरसा बोर्ड खत्म करने के प्रस्ताव को लेकर विपक्षी दल पहले ही नाराजगी जता चुका था।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, शिक्षा संस्थानों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, इसमें संस्थान के किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और संचालित हो, परिषद से संबद्ध हो और इसका प्रबंधन पंजीकृत सोसायटी, न्यास, या कंपनी द्वारा किया जा रहा हो शामिल है।

मान्यता के लिए शर्ते

नए अधिनियम के लागू होने के बाद, विधेयक के जरिए ही अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन होगा। पूर्व में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से धार्मिक शिक्षा देने के लिए इसी प्राधिकरण से पुनः मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, शिक्षा संस्थानों को कुछ अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी। इनमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि संस्थान किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और संचालित हो, परिषद से संबद्ध हो और इसका प्रबंधन एक पंजीकृत निकाय (सोसायटी, न्यास, या कंपनी) द्वारा किया जा रहा हो। इसके अतिरिक्त गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों का नामांकन 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। प्राधिकरण अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मों और भाषाओं से संबंधित विषयों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करेगा और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अतिरिक्त विषयों से संबंधित परीक्षाएं आयोजित करने, छात्रों का मूल्यांकन करने और प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मार्गदर्शन करेगा। इसलिए यह विधेयक राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

लैंड जिहाद पर कसा शिकंजा

उत्तराखंड में तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। कुछ मुसलमानों ने वन विभाग, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग की खाली पड़ी भूमि पर जगह-जगह मजारें बनाकर लैंड जिहाद चला रखा था। कांग्रेस के शासनकाल में वोट बैंक बढ़ाने के लिए बाहर से मुस्लिमों को लाकर बसाया गया था। इनके बीच में रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी छिपे हुए हैं। बदलती डेमोग्राफी के कारण पुष्कर सिंह धामी सरकार का रुख एकदम सख्त है। सरकार की सख्ती के कारण उत्तराखंड में अब तक 600 के करीब मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है। 250 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। जिलेवार बात करें तो हरिद्वार में 85, ऊधम सिंह नगर में 66, देहरादून में 44, नैनीताल में 24, पौड़ी में 2 और अल्मोड़ा में 1 मदरसे को सील किया गया है, इनमें से कई मदरसे अवैध रूप से सालों से चलाए जा रहे थे। प्रशासन ने भी दावा किया था कि जिन मदरसों को सील किया गया है वो सब अवैध थे। लिहाजा सील करने की कार्रवाई शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी थी। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पिछले कई सालों से अवैध मस्जिद, मदरसे और मजारों के खिलाफ अभियान चला रखा है। सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट पहुंच रही हैं कि उत्तराखंड में बड़ी तादाद में अवैध तरीके से मदरसे चलाए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश में जमीन जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 6500 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को जिहादियों से मुक्त कराया गया है। उनकी सरकार प्रदेश में पहली बार सख्त भू- कानून लेकर आई है, जिससे किसानों की जमीनों को अब लैंड माफिया नहीं हड़प पाएंगे। इससे साफ होता है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज करने वालों पर आगे और भी सख्ती बरतेंगे।

- **उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और ग्यारह सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, अध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय का एक शिक्षाविद् होगा, जिसे 15 वर्ष या उससे अधिक का शिक्षा प्रबंध का अनुभव हो।**
- **तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास रखने वाली कांग्रेस ने 'अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम' लागू होने से पहले ही विरोध शुरू कर दिया था, जबकि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष से लेकर कुछ मुस्लिम इसे धामी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय बता रहे है, इससे शिक्षा में पारदर्शिता आएगी।**

तेज प्रताप बनाम तेजस्वी

राजद में कुछ लोग तेज प्रताप के निष्कासन से खुश नहीं हैं, उनका मानना है कि चुनाव जीतने के लिए तेजस्वी व तेज प्रताप को मिलकर लड़ना चाहिए था, लेकिन दोनों के एक-दूसरे के सामने आने से ज्यादा नुकसान तेजस्वी को होगा, क्योंकि तेज प्रताप के पास को खोने के लिए कुछ नहीं है।

उदय भान सिंह
लेखक

बिहार में अभी विधानसभा चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मान लिया है कि वो सत्ता में आ चुके हैं। यानी दोनों मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि 'वोटर अधिकार यात्रा' करने से ही उन्हें भारी बहुमत मिल जाएगा। इसलिए वो अभी से आपे से बाहर हुए जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों की हेकड़ी राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव निकाल रहे हैं। लालू यादव के बड़े बेटे व पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने ही छोटे भाई तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसे है। उन्होंने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर भी तंज कसा और ऐसी बातें कहीं, जो कांग्रेस और राजद के नेताओं को नागवार गुजरने वाली हैं। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया (एक्स) पर लिखा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार-तार करने निकले हैं। तेज प्रताप के इस बयान से सियासी गलियारे में खलबली मची हुई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के समर्थक उनके इस बयान से बोखला रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यही नहीं बिहार में हुए वोटर वेरिफिकेशन (एसआईआर) पर लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आमने-सामने हैं। एक तरफ तेजस्वी चुनाव आयोग और एनडीए पर वोट चोरी का आरोप लगा लगा रहे। तो वहीं तेज प्रताप का कहना है कि वोट चोरी के नाम पर तेजस्वी और राहुल गांधी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तेजप्रताप यादव ने बिहार के मतदाताओं के अपील करते हुए कहा कि कोई वोट चोरी नहीं हो रही है, लोग राहुल और तेजस्वी के भ्रम में ना फंसे। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुद्दा है। लोगों को इन्हीं बातों पर टिके रहना चाहिए। तेज प्रताप ने नबीनगर विधानसभा से विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के गाड़ी चालक और उसके साथ एक पत्रकार भाई को जयचंद द्वारा मारे-पीटे जाने की घटना को बेहद ही शर्मनाक बताते हुए कड़ी आलोचना की थी। तेज प्रताप ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को नसीहत देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं तेजस्वी से कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है। अपने आसपास के जयचंदों से सावधान हो जाओ नहीं तो चुनाव में बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा।

तेजस्वी के खिलाफ तेजप्रताप

बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद सीएम बनने के मुंगेरीलाल के सपने देखने वाले तेजस्वी यादव के हसीन सपनों पर खुद उनके बड़े भाई ने ग्रहण लगा दिया है। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव ने नया सियासी दांव खेला है। राजद से छह साल के लिए निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने 'टीम तेज प्रताप' के बैनर तले पांच पार्टियों...'विकास वंचित इंसान पार्टी (वीवीआईपी), 'भोजपुरिया जन मोर्चा', 'प्रगतिशील जनता पार्टी', 'वाजिब अधिकार पार्टी' और 'संयुक्त किसान विकास पार्टी' के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। उनके इस कदम से बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही लालू यादव का कुनबा बिखर गया है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान तेजस्वी यादव को ही होने वाला है। क्योंकि तेज प्रताप उन्हीं के लिए 'वोट कटुआ' साबित होंगे। यही वजह है कि बिहार की सियासत में तेज प्रताप यादव का नया गठबंधन सुर्खियों का केंद्र बन गया है। दरअसल जिस समय तेज प्रताप यादव को पार्टी के निष्कासित किया गया था उस वक्त लालू प्रसाद यादव को भी शायद इसका अहसास नहीं था कि तेज प्रताप इतने कम समय में ही पूरे दम-खम के साथ राजद के खिलाफ ताल ठोंक देगा। किंतु राजद से निष्कासित होने के बाद तेज प्रताप ने निषाद नेता प्रदीप निषाद की पार्टी सहित पांच दलों से गठजोड़ कर लिया। बिहार की सियासत में ये सवाल गूंज रहा है कि तेज प्रताप अपने छोटे भाई और उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे? उनके एक और कदम ने तब खलबली मचा दी जब उन्होंने राजद और कांग्रेस को भी गठबंधन में शामिल होने का न्योता दे दिया। जानकार कहते हैं कि तेज प्रताप का यह बयान उनके भाई तेजस्वी यादव और राजद के प्रति उनकी नाराजगी को बता रहा है। इससे उनके बीच दरार और बढ़ने वाली है।

बिहार में निषाद समुदाय की आबादी लगभग 14 प्रतिशत है जो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है, ऐसे में तेज प्रताप का यह गठबंधन निषाद वोटों को एकजुट करने की अहम रणनीति हो सकती है, तेज प्रताप के इस गठबंधन से मुकेश सहनी की निषाद समाज पर पकड़ कमजोर हो सकती है।

तेजस्वी से तेज है तेज प्रताप

तेज प्रताप ने निषाद नेता प्रदीप निषाद की वीवीआईपी से गठजोड़ कर निषाद समुदाय को लुभाने की शानदार राजनीतिक कोशिश की है। प्रदीप निषाद पहले मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के साथ थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है। बिहार में निषाद समुदाय की आबादी लगभग 14 प्रतिशत है जो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। ऐसे में तेज प्रताप यादव का यह गठबंधन निषाद वोटों को एकजुट करने की अहम रणनीति हो सकती है। तेज प्रताप के इस गठबंधन से मुकेश सहनी की इस समुदाय में पकड़ कमजोर हो सकती है। तेज प्रताप यादव ने मुकेश सहनी पर सियासी हमला करते हुए उन्हें 'बहरूपिया' कहा था। तेज प्रताप का यह तंज भी सहनी और तेजस्वी यादव को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। बिहार के जानकार कहते हैं कि राजद से निष्कासन और परिवार से दूरी ने तेज प्रताप को सियासी तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने का अवसर दिया है। उनकी 'टीम तेज प्रताप' और महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा उनके बगावती तेवर दिखाते हैं। वे एक ओर गठबंधन के साथ अलग-अलग जाति के वोटों को जोड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी के कोर वोटर में भी सेंध लगाने में लगे हैं। उनकी यह दोहरी राजनीतिक रणनीति राजद और तेजस्वी यादव को मुश्किल में डाल सकती है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि तेजस्वी यादव की बौखलाहट यह है कि वे किसी भी रूप में तेज प्रताप को उभरने नहीं देना चाहते। इसलिए तेज प्रताप की कथित प्रेमिका प्रकरण को इतने जोर-शोर से उठाया था। वैसे लालू यादव के कुनबे में विवादों की चिंगारी भी खुद तेज प्रताप यादव ने ही लगाई है। कुछ दिनों पहले तेज प्रताप के फेसबुक पेज पर घोषणा की गई थी कि वो एक युवती के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। यह पोस्ट तेजी से वायरल होने लगी तो उन्होंने कुछ घंटों बाद ही इस पोस्ट को हटा दिया और एक्स प्लेटफार्म पर दावा किया कि उनका फेसबुक पेज हैक हो गया था। लेकिन बाद में साफ हो गया कि वो पत्नी एश्वर्या को छोड़कर किसी दूसरी महिला के संपर्क में रहे थे।

तेजस्वी को ज्यादा नुकसान

दो भाइयों के आमने सामने आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती राजद की संगठनात्मक संरचना को बचाने की है। राजद को करीब से जानने वालों का कहना है कि पार्टी में बहुत से लोग तेज प्रताप के निष्कासन से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि चुनाव जीतने के लिए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को मिलकर लड़ना चाहिए था। लेकिन अब एक-दूसरे के सामने आने से ज्यादा नुकसान तेजस्वी यादव को ही होगा। क्योंकि तेज प्रताप यादव के पास को खोने के लिए कुछ नहीं है। तेज प्रताप ने जो कुछ भी हासिल किया अथवा इस साल के आखिर में करेंगे वो उनकी जीत के रूप में ही देखा जाएगा। इसलिए तेज प्रताप कथित रूप से राजद के कोर वोट बैंक यादव, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग में सेंध लगाने के समीकरणों में जुटे हुए हैं। भले ही तेज प्रताप यादव का नया गठबंधन छोटे दलों के साथ है, लेकिन उनके बागी तेवरों ने राजद के भीतर टेंशन तो बढ़ा ही रखी है। अगर तेज प्रताप निर्दलीय या नई पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो वोटों का बंटवारा राजद को नुकसान पहुंचा सकता है।

- **तेज प्रताप यादव ने बिहार के मतदाताओं के अपील करते हुए कहा कि बिहार में कोई वोट चोरी नहीं हो रही है, लोग राहुल और तेजस्वी के भ्रम में ना फंसे, बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुद्दा है, लिहाजा लोगों को इन्हीं बातों पर टिके रहना चाहिए।**
- **पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी व तेजस्वी लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या लोकतंत्र को तार-तार करने निकले हैं, तेज प्रताप के इस बयान से सियासी गलियारे में खलबली है।**

तेज प्रताप का विक्टिम कार्ड

हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव ने पटना के होटल में मीडिया के सामने विक्टिम कार्ड भी खेला। उन्होंने कहा 'बहुत सारी चुनौती है। पूरा बिहार और देश जानता है कि किस तरह से मेरे साथ अन्याय हुआ है। राजद में बैठे कुछ विभीषणों ने ही उनके साथ खेला किया है और चुनाव में वो उनकी पोल खोलकर रहेंगे। हमने महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। महुआ के लिए हमने बहुत काम किया है'। महुआ से तेजस्वी यादव के चुनाव लड़ने वाले सवाल पर तेज प्रताप ने ताल ठोंक कर कहा कि तेजस्वी वहां से किसी भी सूरत में कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा 'टीम तेज प्रताप एक प्लेटफार्म है, जो चुनाव में युवाओं को समर्थन देगी। जो लड़ना चाहेंगे, उन्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा'। तेज प्रताप बोले कि महुआ सीट को अमानत के तौर पर हमने मुकेश रोशन को सौंपा था। उस समय कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो बना था, जिस कारण मुझे हसनपुर से लड़ना पड़ा था। 'मैं आगे बिहार के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मेरे दुश्मन बहुत लोग हैं। मीडिया के माध्यम से वो सुनेंगे तब बुरा लगेगा। कभी तेजस्वी को 'अर्जुन' और खुद को 'कृष्ण' बताने वाले तेज प्रताप यादव को राजद और लालू परिवार से बेदखल कर दिया गया। कभी मां के सम्मान के लिए पत्नी को छोड़ने का दावा करने वाले तेज प्रताप को उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने ही पार्टी और परिवार से बेदखल किया। बिहार की राजनीति में दशकों से काबिज लालू परिवार में शुरू हुए झंझावत अब किस करवट बैठेंगे? यह कहना अभी मुश्किल है। लेकिन लालू यादव ने जिस तरह से तेज प्रताप को निकाला है, उससे खुद लालू यादव पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। हालांकि 'लालू के लाल' तेज प्रताप ने भी पूर्व में कई ऐसे काम किए, जिसने राजद की मुश्किलें बढ़ाई। लेकिन तब कार्रवाई के बजाए लालू यादव अपने लाल को पनाह देते रहे। जानकारों का कहना है कि लालू परिवार में शुरू से ही तेज प्रताप यादव उस मनमर्जी वाले बच्चे की तरह रहे, जो सामाजिक-राजनीतिक मान-मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए केवल अपनी मर्जी के साथ जीना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर अब तेजस्वी और तेज प्रताप में वर्चस्व की लड़ाई है।

बिहार को स्कॉटलैंड बना दूंगा

बिहार विधानसभा चुनावों से पहले तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पद के लिए स्वयं दावा पेश कर दिया है। हालांकि इसमें इंडिया गठबंधन की सहमति शामिल नहीं है। यानी तेजस्वी अभी से ख्याली-पुलाव पकाते हुए सरकार बनने पर बिहार को स्कॉटलैंड बनाने का वादा कर रहे हैं। ये उस परिवार के लाल है जिस परिवार के राज में बिहार में गड्ढों में सड़क होती थी। अपराध चरम पर था इसलिए जंगल राज का दाग आज तक लालू प्रसाद यादव के परिवार पर लगा हुआ है। इस सब के बीच तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव खुद को भावी मुख्यमंत्री मान रहे तेजस्वी का सारा खेल बिगाड़े में लगे हैं। हालांकि लालू परिवार तेज प्रताप को गंभीरता से नहीं ले रहा है। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक चाल तेज प्रताप चल रहे हैं उससे राजद को बड़ा नुकसान होने से इनकार नहीं किया जा सकता।

वोट चोर कौन ?

राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर नेहरू का पाप भी सार्वजनिक करा दिया, वोट चोरी इंदिरा गांधी ने भी की इसलिए 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव में वोट चोरी और चुनावी अनियमितताओं का दोषी ठहराया था।

डा.वीरेंद्र पुष्पक, वरिष्ठ पत्रकार

बिहार में चुनावों की घोषणा भले ही न हुई हो, लेकिन माहौल गरमाने लगा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 'वोटर अधिकार यात्रा' का नेतृत्व कर थकान मिटाने के लिए विदेश चले गए हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन के नेताओं की वोटर अधिकार यात्रा 16 दिनों में 25 जिलों और 110 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी। करीब 1300 किलोमीटर की इस यात्रा का उद्देश्य कथित तौर पर लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के खिलाफ आवाज उठाना था। राहुल गांधी ने इसे नैतिक लड़ाई बताया। यात्रा के दौरान विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाई। उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र का मुद्दा है। ऐसे में हर कोई सवाल कर रहा है कि राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में इस तरह की यात्रा निकालने कब जा रहे हैं? क्योंकि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 35 से 50 लाख फर्जी वोट बनवा रखे हैं। अब यदि ये फर्जी वोट मतदाता सूची से हटाए जाते हैं तो क्या राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में भी वोट चोरी का नारा बुलंद करेंगे? शायद ही राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में इस तरह की कोई यात्रा निकालने की हिम्मत कर पाए। खैर बिहार की बात करते हैं, बिहार में कांग्रेस का जनाधार खिसका हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस परजीवी पार्टी बन गई है। जो दूसरों के सहारे चुनाव में कुछ फायदा ले सकती है। यानी कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रही है। इसलिए बिहार में चुनाव से पहले लालू यादव और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के कंधे पर सवार होकर कांग्रेस कुछ फायदा उठाना चाहती है, जबकि राजद को कांग्रेस से कोई फायदा शायद ही हो। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस का रिकार्ड है कि वो हरियाणा में अकेले लड़ी हार गई। मध्य प्रदेश में अकेले लड़ी पराजित हो गई। दिल्ली में अकेले लड़ी हार गई। इससे पहले यूपी में लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी तो लोकसभा में पहले से ज्यादा सीट हासिल कर ली। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना से गठबंधन करके लड़ी तो लोकसभा में अच्छा नतीजा लेकर आई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भले ही वोट अधिकार यात्रा को सफल मान रहे हों, लेकिन चुनौती कम नहीं है। तेजस्वी यादव को पहली चुनौती तो उनका बड़ा भाई तेज प्रताप यादव ही दे रहे हैं। दूसरे प्रशांत किशोर भी बिहार में जनस्वराज पार्टी के साथ ताल ठोक रहे हैं। ये दोनों नेता किसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम वोट में ओबेसी भी सेंध लगाएंगे, जिसका फायदा एनडीओ को होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

विपक्षी एकता का प्रदर्शन

चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलवाकर 65.5 लाख वोटरों के नाम सूची से हटा दिए हैं। इनमें स्थाई रूप से पलायन करने वाले, दिवंगत मतदाताओं के साथ एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाता शामिल हैं। इसे कांग्रेस और राजद वोट चोरी नाम दे रहा है। इसके विरोध में ही वोट अधिकार यात्रा का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इस यात्रा को नैतिक लड़ाई के रूप में पेश किया गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि वो उन लाखों लोगों के मताधिकार की रक्षा करना चाहते हैं, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं उन्हें फिर से शामिल कराने की क्या कोई कोशिश की है? शायद नहीं, ये सवाल तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने भी उठाया है। उनका कहना है कि यात्रा निकालने से अच्छा होता कि राहुल और तेजस्वी मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उन्हें फिर से शामिल कराते। इससे शायद सकारात्मक संदेश जाता। इसलिए बिहार की जनता को वोट अधिकार यात्रा में वोटर्स की चिंता कम और पॉलिटिकल ड्रामा ज्यादा दिखाई दिया। हालांकि राहुल गांधी ने विपक्षी एकता दर्शाने की भरपूर कोशिश की। इसी वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना 'वोट चोर, गद्दी छोड़' जैसे नारे लगाए गए।

कांग्रेस की हालत अपने दम पर चुनाव लड़ने की नहीं रही है, बिहार में तेजस्वी के कंधे पर सवार होकर कांग्रेस कुछ लाभ चाहती है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस का रिकार्ड है कि वो हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली में अकेले लड़ी हार गई, जबकि यूपी में लोकसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ी तो पहले से ज्यादा सीट हासिल कर ली।

तेजस्वी के भाई तेज प्रताप का कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा निकालने से अच्छा होता कि राहुल और तेजस्वी मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उन्हें फिर से शामिल कराते, इससे सकारात्मक संदेश जाता, इसलिए बिहार की जनता को यात्रा में वोटर्स की चिंता कम और पॉलिटिकल ड्रामा ज्यादा दिखाई दिया।

इंडिया गठबंधन के कई नेता अलग-अलग समय पर वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। जो विपक्षी एकता का सिर्फ प्रदर्शन भर था। वोट अधिकार यात्रा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, रेवंत रेड्डी, अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, सिद्धारमैया शामिल हुए। आरजेडी से तेजस्वी यादव पूरे समय यात्रा में रहे और लालू यादव बीच-बीच में शामिल होते रहे। गैर कांग्रेसी नेताओं में समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, डीएमके के एमके स्टालिन और कनिमोझी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन, तृणमूल कांग्रेस से यूसुफ पठान और ललितेश त्रिपाठी, एनसीपी (शरद पवार) से सुप्रिया सुले और जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना (यूबीटी) से संजय राउत, वामपंथी पार्टियों से दीपांकर भट्टाचार्य (सीपीआई-एमएल), डी राजा (सीपीआई), एमए बेबी (सीपीआई-एम) और वीआईपी से मुकेश सहनी यात्रा में शामिल हुए। हालांकि इन नेताओं की सिर्फ हाजिरी ही लगवाई गई, क्योंकि बिहार में इनमें से किसी एक नेता का भी कोई जनाधार नहीं है। फिर इन नेताओं से बिहार की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ वो सभी नेता भी जानते हैं जो यात्रा का हिस्सा बने। इस एकता का बिहार की राजनीति और विधानसभा चुनाव पर कितना असर होगा ये भी नेता जानते हैं। एक तरह से कहें तो यह यात्रा और एकता सिर्फ ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं थी।

कांग्रेस कराती थी वोट चारी?

राहुल गांधी और तेजस्वी का दावा है कि चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर दलितों, ओबीसी, मुस्लिम और गरीबों के ही नाम काटे हैं, ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि विपक्षी नेताओं को किस माध्यम से पता चला कि मतदाता सूची से सिर्फ दलितों, ओबीसी, मुस्लिम और गरीबों के ही नाम काटे गए हैं? क्या सवर्ण समाज के नाम नहीं काटे गए हैं? अगर काटे गए हैं तो सवर्णों का नाम लेने से इन दोनों नेताओं को घृणा क्यों है? विपक्षी नेताओं को कैसे पता कि जिनके नाम कटे हैं वो कांग्रेस, राजद को ही वोट देते हैं? राहुल गांधी का एक और दावा है कि 2014 से पहले गुजरात में वोट चोरी होती थी, इसके बाद पूरे देश में वोट चोरी शुरू हो गई। यानी राहुल गांधी स्वीकार रहे हैं कि केंद्र में 2014 से पहले जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी तब वोट चोरी होती थी। यानी कांग्रेस वोट चोरी कराती थी। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया तो उनके पूरे खानदान का रिकार्ड भी सामने आ गया। भाजपा बता रही है कि कैसे उनके पूर्वज पंडित जवाहर लाल नेहरू ने वोट चोरी की थी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 35 से 50 लाख फर्जी वोट बनवा रखे हैं, अब यदि ये फर्जी वोट मतदाता सूची से हटाए जाते हैं तो क्या राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में भी वोट चोरी का नारा बुलंद करेंगे ?

1946 में कांग्रेस के आंतरिक चुनाव में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट और पंडित जवाहर लाल नेहरू को केवल एक वोट मिला और एक वोट पाने वाले नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए। कांग्रेस की ये पहली वोट चोरी अभी तक छिपी हुई थी, लेकिन राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर नेहरू का पाप भी सार्वजनिक करा दिया। दूसरी वोट चोरी इंदिरा गांधी ने की, इसलिए 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव में वोट चोरी और चुनावी अनियमितताओं का दोषी ठहराया था। यानी हाईकोर्ट ने गांधी परिवार के वोट चोर होने पर मोहर लगाई। राजीव गांधी को जिताने के लिए कांग्रेसियों ने 97 बूथों पर वोट चोरी की थी। गांधी परिवार के चौथे नेता राहुल गांधी को वोट चोरी का मौका नहीं मिला तो बोखलाहट में देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को ही वोट चोर बताने लगे। इसलिए कांग्रेस लगातार सिमटती जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि इंडिया गठबंधन न बना होता और कांग्रेस अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ती तो संभवतः राजनीति के नक्शे से साफ हो जाती।

तेजस्वी बने राहुल के पिछलग्गू

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा से यह भी साबित होता है कि 16 दिन तक बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर कांग्रेस और राजद ने सिर्फ बिहार की जनता को गुमराह करने का काम किया गया है। इस वोटर अधिकार यात्रा का एक दिलचस्प पहलू ये है कि 16 दिन तक तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पिछलग्गू बनकर घूमते रहे। तेजस्वी यादव ने पूरी यात्रा के दौरान कई बार अति उत्साह में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की, राहुल गांधी तो इससे गदगद हुए लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं बताया। इससे साफ है कि राहुल गांधी सिर्फ तेजस्वी यादव का बिहार में इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस को यदि कुछ सम्मानजक सीट मिलती हैं तो फिर वो तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम नहीं बनने देंगे। इसलिए राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने तक की घोषणा नहीं की। इसी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी की छवि जमीनी स्तर के नेता के तौर पर बनाने की कोशिश की गई, इसलिए उनके ईको सिस्टम ने सफेद टी-शर्ट के ऊपर गमछा डालकर खुली जीप में ग्रामीणों से बात करते हुए राहुल को दिखाया। राहुल गांधी मखाने के पानी भरे खेत में जुराब पहन कर उतरे। जहां उन्होंने देखा कि यह सुपर फूड कैसे उगाया जाता है। लिहाजा पार्टी ने राहुल गांधी की ऐसी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर यह साबित करने की कोशिश की कि राहुल गांधी ही गरीबों के मसीहा हैं। कांग्रेस का ईको सिस्टम राहुल गांधी को पीएम मोदी के खिलाफ एक मजबूत चुनौती देने वाले नेता के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की हैसियत रखते हैं। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने तो दुनियाभर में भारत का विरोध करने वाले नेताओं तक को पानी पिला रखा है। राहुल गांधी और उनके ईको सिस्टम को समझना चाहिए कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंगा लिया था, नताजी जस्टिन ट्रूडो के हाथ से सत्ता ही चली गई। मालद्वीप के पीएम ने भारत से पंगा लेने की कोशिश की थी, लेकिन मालद्वीप घुटनों पर आ गया। ताजा मामला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड का है, जिन्होंने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाई तो अपने ही देश में आलोचना का शिकार हुए और ट्रंप को यू-टर्न लेना पड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी की इस कूटनीति के आगे राहुल गांधी क्या कहीं ठहरते हैं ?

संसद

माननीयों पर कानून का शिकंजा

कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर डा.मनमोहन सिंह तक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की फेहरिस्त तो बहुल लम्बी है, लेकिन इनके लिए कोई कानून न होने से सभी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करने के बाद भी अपने पद पर रहकर जलवा जलाल कायम रखते रहे हैं।

कृष्ण कुमार चौहान

भ्रष्टाचार सरकारी सिस्टम के डीएनए शामिल हो गया है। नीचे वाला जब 500 रुपये की भी रिश्वत लेता है तो कहता है कि जनाव हमें क्या बचेगा, सब ऊपर वालों को चला जाता है, ये हर रिश्वतखोर मुलाजिम का तकिया कलाम है। अब ये ऊपर वाला कौन है, एक सरकारी मुलाजिम के सबसे ऊपर तो अफसर और उसके बाद मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ही है। दुर्भाग्य से देश की आजादी के बाद से भ्रष्टाचार फलता फूलता रहा है। कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर डा.मनमोहन सिंह तक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की फेहरिस्त तो बहुल लम्बी है, लेकिन इनके लिए कोई कानून न होने से सभी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करने के बाद भी अपने पद पर रहकर जलवा जलाल कायम रखते रहे हैं। शायद इसलिए मोदी सरकार को 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक का सिस्टम भ्रष्टाचार की दलदल धंसा है। इसके उदहारण दो साल से देश भी देख रहा है। समाजसेवी अन्ना हजारे के कंधे पर सवार होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल जब शराब घोटाले में जेल गए तो जिद कर बैठे कि वो तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल गए, लेकिन जेल में रहकर भी मंत्री बने रहे। जेल में वीआईपी सुविधा लेते रहे। केजरीवाल ने तो बाकायदा कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें जेल से सरकार चलाने के लिए अधिकारियों से मिलने की इजाजत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनका यह आग्रह ठुकरा दिया था।

कानून में असमानता

जेल में रहकर वीआईपी सुविधा लेने के पीछे तर्क दिया जाता था कि जब तक अदालत माननीय अपराधी को दोषी करार न दे दे और सजा न सुना दे तब तक माननीय बेकसूर हैं। जबकि यह सुविधा लोकसेवक यानी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी और आम नागरिक के लिए नहीं थी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी संगीन अपराध में 50 घंटे तक पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा में रहता है तो उसकी नौकरी ही चली जाती है। कानून की इसी असमानता को समाप्त करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 130वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई। इस विधेयक के दायरे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र व राज्य के मंत्रियों को शामिल किया गया है। यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी मंत्री पर ऐसा कोई गंभीर आरोप लगता है, जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है और वह 30 दिन तक जेल या हिरासत में रहता है, अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है तो उसे 31वें दिन स्वतः ही पदमुक्त मान लिया जाएगा। यह नियम प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों, केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों पर लागू होगा। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 75 (केंद्रीय मंत्री), अनुच्छेद 164 (राज्य मंत्रिपरिषद), और अनुच्छेद 239 (दिल्ली सरकार) में किया जा रहा है। अभी तक संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, जिसकी वजह से पिछले वर्षों में कुछ मंत्री और मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए भी अपने पदों पर बने रहे। यानी सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के किसी भी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि गिरफ्तारी या हिरासत में रहने पर मुख्यमंत्री या मंत्री को उनके पद से हटाया जा सके।

विपक्ष की भ्रष्ट व आपराधिक मनोवृति

130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा है कि अब देश की जनता को यह तय करना है कि क्या जेल में रहकर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का सरकार चलाना उचित है? अथवा नहीं! हालांकि लोकसभा में विपक्ष ने इस बिल का कड़ा विरोध किया और बिल को फाड़ कर गृह मंत्री की तरफ फेंक दिया था। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से प्रस्तावित तीनों विधेयकों का विरोध किया, उससे उनकी भ्रष्ट व आपराधिक मनोवृति को संरक्षण देने वाली कलई खुल गई। देश में यथार्थवादी सियासत को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रवादी भाजपा अकसर राजनीति की उन दुःखती हुई नसों पर ही हाथ रखती आ रही है जो इस देश व समाज को बदलने की हिम्मत रखती हैं। इससे निश्चित ही सोकॉल्ड सेक्यूलर्स, समाजवादियों व साम्यवादियों की बौखलाहट देखने को मिली है। इस मानसून सत्र में राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और जनता के आक्रोश को देखकर अमित शाह ने संसद में लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया। संशोधन विधेयक में महत्वपूर्ण बात यह है कि संवैधानिक पदों पर रहते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री जेल से सरकार नहीं चला पाएंगे। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में गिरते नैतिकता के स्तर को बचाना और राजनीति में शुचिता लाना है। हकीकत में ये तीनों विधेयक कानूनी रूप ले लेंगे उसके बाद कोई भी नेता जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकेगा। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट कहा कि, संविधान जब बना था तब हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि भविष्य में राजनीति में ऐसे व्यक्ति भी आएंगे, जो गिरफ्तार होने से पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देंगे। सच में बीते कुछ वर्षों में, देश में ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति देखी कि जब मुख्यमंत्री या मंत्री बिना इस्तीफा दिए जेल से अनैतिक रूप से सरकार चलाते रहे।

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, एनसीपी, शिवसेना सहित इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से प्रस्तावित तीनों विधेयकों का विरोध किया, उससे उनकी भ्रष्ट व आपराधिक मनोवृति को संरक्षण देने वाली कलई खुल गई।

राजनीति का शुद्धिकरण

अमित शाह ने कांग्रेस को टारगेट करते हुए कहा कि देश ने वो समय भी देखा है जब इसी सदन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन संख्या-39 के माध्यम से प्रधानमंत्री को ऐसा विशेषाधिकार दिया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। कांग्रेस की कार्य संस्कृति व नीति रही कि वो प्रधानमंत्री को संविधान संशोधन करके कानून से ऊपर कर देते हैं। जबकि भाजपा की नीति है कि हम अपनी ही सरकार के प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्रियों को भी कानून के दायरे में ला रहे हैं। भाजपा हमेशा नैतिक मूल्यों के पक्ष में रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सिर्फ आरोप लगने पर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी ओर इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई 'अनैतिक परंपरा' को कांग्रेस पार्टी आज भी आगे बढ़ा रही है। जिस लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए कांग्रेस अध्यादेश लाई थी, जिसका राहुल गांधी ने सदन में विरोध किया था, वही राहुल गांधी अब लालू यादव को गले लगाकर घूम रहे हैं। अब हर किसी के जहन में सवाल आएगा कि आखिर इस बिल से भाजपा आम लोगों को क्या संदेश देना चाहती है? तो जवाब होगा कि संसद का मॉनसून सत्र पूरा होने के महज एक दिन पहले केंद्र की एनडीए सरकार ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया और इसे व्यापक चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया। ऐसा इसलिए किया गया कि इस विधेयक के जरिए भाजपा सिर्फ यह नहीं बताना चाह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जा रही है, बल्कि राजनीति के अपराधीकरण को लेकर भी एक ठोस संदेश दे रही है। इससे आम लोगों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। भाजपा का मानना है कि इस बिल को लोग पसंद करेंगे, जिससे इसका सकरात्मक संदेश जाएगा। क्योंकि जब लालबत्ती खत्म करने का फैसला लिया गया था तो युवाओं ने सरकार की सराहना की थी, क्योंकि युवा वीआईपी कल्चर के खिलाफ रहे हैं। वहीं राजनीति में भ्रष्ट लोग ना रहें, इसे लेकर भी वर्षों से युवाओं में चर्चा होती रहती है। शाह ने 2010-11 के अन्ना आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा चूंकि जनलोकपाल व भ्रष्टाचार के खिलाफ चली इस लड़ाई में देश के युवाओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया था। इसलिए इस तीनों बिल के जरिए हम अपनी मंशा साफ कर रहे हैं कि भाजपा राजनीति में अपराधीकरण और करप्शन के खिलाफ है और करप्शन के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। रही बात राजनीति और नैतिकता की तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यह बहुत जरूरी है।

संविधान निर्माताओं ने भी यह सोचा होगा कि अपराधी और भ्रष्ट लोगों को राजनीति से दूर रखा जाए, लेकिन तब इस कानून का प्रावधान इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि उस समय राजनीति में नैतिकता थी, आरोप लगने भर से नेता कुर्सी छोड़ देते थे, लेकिन अब यह स्थिति नहीं है।

अपराधी और भ्रष्ट लोग सत्ता से दूर रहें

भाजपा की सोच है कि संविधान निर्माताओं ने भी यह सोचा होगा कि अपराधी और भ्रष्ट लोगों को राजनीति से दूर रखा जाए, लेकिन तब इसका प्रावधान इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि उस समय राजनीति में नैतिकता थी। आरोप लगने भर से लोग कुर्सी छोड़ देते थे। लेकिन अब स्थिति यह नहीं है। अब लोग जेल से ही सरकार चलाना चाहते हैं। लिहाजा कानून के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अपराधी और भ्रष्ट लोग सत्ता से दूर रहें। कुल मिलाकर मौजूदा बिल राजनीति में व्याप्त व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ऐसा किया जाना राष्ट्रहित और जनहित दोनों में जरूरी है। भाजपा ने ठीक ही कहा है कि इस बिल के दायरे में पीएम और केंद्र के मंत्री भी हैं, ऐसे में विपक्ष की इस बात की हवा खुद ही निकल जाती है कि केंद्र सरकार अपने मातहत राज्य सरकारों के खिलाफ इसका दुरुपयोग कर सकती है। चूंकि निर्वाचित प्रतिनिधि भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर केवल जनहित और जनता के कल्याण के लिए कार्य करें। वहीं यह भी अपेक्षा की जाती है कि पद पर आसीन मंत्रियों का चरित्र और आचरण संदेह से परे होना चाहिए। ऐसे में जब कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहा हो और जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में रखा गया हो, वह संवैधानिक नैतिकता और सुशासन के सिद्धांतों में बाधा डाल सकता है और जनता द्वारा उसमें व्यक्त किए गए संवैधानिक विश्वास को कमजोर कर सकता है। कुल मिलाकर यह भाजपा का एक ऐसा मास्टरस्ट्रोक है, जिससे न सिर्फ शरारती विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया, बल्कि भ्रष्टाचारी राजनीतिक मिजाज और अपराध को बढ़ावा देने के स्वभाव या फिर उससे आंखें मूंदे रखने के स्वभाव की भारी राजनीतिक कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ेगी। यानी एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद को कानून के दायरे में लाने का संविधान संशोधन पेश किया है, तो दूसरी ओर कानून के दायरे से बाहर रहने, जेल से सरकारें चलाने एवं कुर्सी का मोह न छोड़ने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया है।

खतरनाक रास्ते पर राहुल गांधी

राहुल गांधी जिस सीएसडीएस के सह निदेशक संजय कुमार द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए महाराष्ट्र लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मतदाता आंकड़ों को लेकर वोट चोरी का नारा बुलंद कर रहे हैं उस संजय कुमार के खिलाफ महाराष्ट्र में तीन एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं।

डा.भारत भूषण
आईएफटीएम

विपक्ष खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी एंड कंपनी पिछले 11 वर्षों से प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स ही कर रही है, लेकिन हर चुनाव में या कहें की हर बार उनकी प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स का हश्र बद से बदतर ही हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी बिना सोचे समझे ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं जिनमें अरबन नक्सलवाद की झलक होती है। उन्हें देश की सरकार पर, सेना पर, कोर्ट पर अथवा किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है। लेकिन भारत विरोधी हर ताकत पर भरोसा है। इसलिए वो अपने बुने जाल में खुद ही फंस जाते हैं। संविधान व लोकतंत्र को खतरा बताने वाला नैरेटिव तो राहुल गांधी का सबसे फेवरेट है। वो हाथ में लाल डायरी लेकर घूमते हैं जिसे वो संविधान बताते हैं, जबकि भारतीय संविधान की जिल्द का रंग नीला है। इसके अलावा हर चुनाव में वो एक नया प्रोपेगैंडा लेकर प्रकट होते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में नारा दिया था 'चौकीदार चोर है', इस बार बिहार में नारा है 'महाराजा वोट चोर है' वो बिहार की जनता के सामने झूठ परोस रहे हैं कि पहले वोट चोरी होगा, फिर राशन कार्ड और उसके बाद घर, जमीन, जायदाद सब मोदी सरकार चोरी कर लेगी। यही नैरेटिव 2024 के लोकसभा चुनाव में लेकर आए थे, संविधान खतरे में बताया था और आरक्षण खत्म करने का आरोप सरकार पर लगाया था फिर भी सत्ता का मुंह नहीं देख पाए थे। जाति जनगणना का राग भी अलापा, सेना की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, भारतीय भूमि पर चीन का कब्जा बताया लेकिन कोई हथकंडा काम नहीं आया। जिस तरह नक्सलवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते ठीक वैसे ही राहुल गांधी को अब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। लिहाजा सीबीआई, ईडी, आईटी, चुनाव आयोग न्यायपालिका तक पर सवाल उठाते रहते हैं। राहुल गांधी के आरोपों का सच सामने आता है तो उनकी ही नहीं बल्कि उनका साथ देने वाले राजनीतिक दल भी असहज हो जाते हैं। अकेले राहुल गांधी की वजह से उनकी बहन प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सहयोगी दल के नेता सबके सब जनता की नजरों में गिर जाते हैं। खुद अपनी व अपनी पार्टी की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगवा लेते हैं। राहुल गांधी तो माफी मांगने में भी एक्सपर्ट हैं क्योंकि पीएम मोदी के लिए चौकीदार चोर कहा तो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, राफेल में कमीशन का आरोप लगाने पर सुप्रीम कोर्ट में खेद जताया, सावरकर मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, सारे मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं मामले में माफी नहीं मांगी तो दो साल की सजा हो गई। चार ऐसे मामले मुझे याद हैं जिन पर राहुल ने कोर्ट में सरेंडर किया। अब वोट चोरी का मुद्दा उनके गले में फांस बन गया है। राहुल या तो माफी मांगेंगे वरना जेल भी जा सकते हैं। क्योंकि किसी भी संवैधानिक संस्था पर बिना किसी सबूत के चोरी का गंभीर आरोप लगाकर उसकी विश्वसनीयता को खतरा पैदा करना, किसी भी संवैधानिक संस्था के प्रति जनता में भ्रम पैदा करना अपराध के दायरे में आता है इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त कह चुके हैं कि राहुल गांधी के पास दो विकल्प हैं पहला देश से माफी मांगे दूसरा अपने आरोपों की सत्यता के लिए आयोग को शपथ पत्र दें। ऐसा न करने के बाद क्या होगा यह अभी साइलेंट है?

सीएसडीएस पर तीन एफआईआर

राहुल गांधी जिस सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के सह निदेशक संजय कुमार द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए महाराष्ट्र लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मतदाता आंकड़ों को लेकर आज तक वोट चोरी का नारा बुलंद कर रहे हैं उस संजय कुमार के खिलाफ महाराष्ट्र में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में तीन एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं।

जब नेता गलत जानकारी फैलाते हैं, तो इसका असर समाज की सोच पर पड़ता है, जो पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है, लिहाजा झूठे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए सभी सबूतों और तथ्यों की मुक्कमल जांच होनी चाहिए ताकि सबूतों के अभाव में वो कोर्ट से बरी न हो सकें।

सीएसडीएस के सह निदेशक संजय कुमार सोशल मीडिया और मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सीएसडीएस के संजय कुमार ने ही दावा किया था कि नागपुर की हिंगना विधानसभा में 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 4,66,203 थी और विधानसभा चुनावों में यह संख्या घटकर 2,86,931 हो गई थी यानी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं में 38.45 प्रतिशत की कमी का दावा किया था। इसी तरह उन्होंने नासिक की देवलाली सीट के बारे में लिखा था कि वहां 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 4,56,072 थी जबकि वास्तविक संख्या 2,76,902 थी। सीएसडीएस के हेरफेर वाले चुनावी आंकड़े जारी करने पर भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएसएसआर) ने संजय कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। परिषद ने कहा कि सीएसडीएस ने आंकड़ों के हेरफेर और निर्वाचन आयोग की शुचिता को कमजोर करने के लिए एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया है। संजय कुमार को समझना चाहिए था कि सोशल मीडिया के युग में इतिहास की खुदाई के लिए पुरातत्व विभाग की जरूरत नहीं होती है। कई बार स्क्रीनशॉट ही काफी होते हैं, जिससे सफेद झूठ सामने आ जाता है। संजय कुमार के इन्हीं भ्रमित करने वाले चुनावी आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी उछल रहे। सरकार और चुनाव आयोग को चोर बता कर बदनाम कर रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी नारा दे रहे हैं 'वोट चोर गद्दी छोड़।' इससे उनकी मनोस्थिति का पता चलता है कि वो मानसिक रूप से कितने अमर्यादित हो चुके है।

जनता को भड़का रहे हैं राहुल

2018 में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव होने थे। तब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, लेकिन अपने ऊटपटांग बयानों और हरकतों के कारण काफी चर्चित थे। उन्हीं दिनों उन्होंने गौतम अडानी की कंपनी को लेकर अमेरिकी फर्म हिंडेनबर्ग की एक रिपोर्ट पर खूब हंगामा किया था। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राफेल के मुद्दे पर देश की जनता को भड़काने के लिए नारा दिया चौकीदार चोर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी देश की जनता को भड़का कर देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। क्योंकि सीएसडीएस के झूठे आकंड़ों के आधार पर वो जनता को भड़का रहे हैं कि सरकार तुम्हारा घर-बार, जमीन जायदाद सब कुछ छीन लेगी। उन्हें लगता है कि इस तरह जनता को भड़का कर सड़क पर लाया जाए और सरकार के खिलाफ विद्रोह कराया जाए। ऐसे संकेत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी दिए हैं। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बेहद खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं। विपक्ष के नेता भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम षड्यंत्रों के बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जॉर्ज सोरोस का कहना है कि उसने भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए एक ट्रिलियन डॉलर रखे हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और कई वामपंथी संगठनों में बैठी भारत विरोधी ताकतें देश के खिलाफ साजिश रच रही हैं। ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की गतिविधियों से दूर रहे। नेताओं में भी कानून का डर होना चाहिए, तभी वे अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और सच को सामने रखेंगे। यह जनता के हक की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर नागरिक को सही जानकारी पाने का अधिकार है।

चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने की साजिश

वोट चोरी के झूठे आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने वाले नेताओं पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यह न केवल लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है, बल्कि इससे समाज में अविश्वास भी बढ़ता है। जब नेता ऐसी गलत जानकारी फैलाते हैं, तो इसका असर आम लोगों की सोच पर पड़ता है, जो पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करता है। नेताओं पर कार्रवाई करते समय सभी सबूतों और तथ्यों की मुक्कमल जांच होनी चाहिए, ठोस प्रमाण के आधार पर ही कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए। ताकि सबूतों के अभाव में कोर्ट से बरी न हो सकें। राजनीति में पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर अपने फायदे की राजनीति करती हैं। इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए एजेंसियों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही फैसले होने चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आए और जनता को न्याय मिले। यदि वोट चोरी के झूठे आरोपों पर कार्रवाई नहीं होती, तो लोकतंत्र का ढांचा कमजोर पड़ सकता है। चुनाव प्रक्रिया से जनता का भरोसा उठ सकता है। मतदाता चुनावी प्रक्रिया से ही दूरी बना सकता है। इसलिए नेताओं को जवाबदेह बनाना बेहद जरूरी है। इससे नेताओं में अनुशासनहीनता कम होगी और जनता को सही दिशा में ले जाने का रास्ता साफ होगा।

- **राहुल गांधी की वजह से उनकी बहन प्रियंका गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सहयोगी दल सबके सब असहज हो जाते हैं, जनता की नजरों में गिर जाते हैं, खुद अपनी व अपनी पार्टी की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगवा लेते हैं।**
- **सीएसडीएस के संजय कुमार ने ही दावा किया था कि नागपुर की हिंगना विधानसभा में 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 4,66,203 थी और विधानसभा चुनावों में यह संख्या घटकर 2,86,931 हो गई थी यानी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं में 38.45 प्रतिशत की कमी का दावा किया था।**

राहुल के नेतृत्व को नकारा

राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति में विश्वास रखते हैं उससे उनका कद लगातार घटा है। लिहाजा 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के कुछ ही महीने बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया था। उन्होंने कहा था कि वे इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने को तैयार हैं। उनके बयान का लालू यादव ने यह कह कर समर्थन किया था कि वे ममता की बात से सहमत हैं। इसके बाद तो ममता बनर्जी जैसे इंडिया ब्लॉक के दूसरे नेताओं के भी राहुल के खिलाफ कंठ खुल गए थे। जम्मू-कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तो इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व को ही नकार दिया था। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हों या सपा मुखिया अखिलेश यादव सभी राहुल गांधी की राजनीति से आज भी खुश नहीं हैं। इसलिए राहुल लाख कोशिशें करें, उनकी राह उतनी आसान नहीं, जितनी वे साथी दलों से उम्मीद पाले हुए हैं। क्योंकि कांग्रेस की देश में जो दयनीय स्थिति है, उसमें विपक्ष की मदद के बिना राहुल गांधी का पीएम बनने का सपना सच नहीं हो सकता। यही वजह है कि कभी ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे विपक्षी नेताओं द्वारा खारिज किए जा चुके राहुल ने बिहार के एसआईआर के मुद्दे को राष्ट्रीय आवाज बनाने की कोशिश की है। दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने एसआईआर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया। संसद की कार्रवाई तक ठप की गई। शायद राहुल गांधी को अभी भी लगता है कि नरेंद्र मोदी का सितारा गर्दिश में है। विपक्ष की यह धारणा 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से बनी है। भाजपा की 240 सीटों को विपक्ष मोदी मैजिक की फीकी पड़ती चमक के रूप में देख रहा है। इसलिए राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी कर तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद हासिल किया। लेकिन कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में बिना वोट चोरी किए कांग्रेस सत्ता में है। ये राहुल गांधी कैसे भूल जाते हैं। इसलिए ही राहुल गांधी को राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि जनता भी खारिज कर रही है।

नेपाल

नेपालियों ने नेपाल फूंका

प्रदर्शनकारियों ने जो पोस्टर्स ले रखे थे, उनमें सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ नारे नहीं थे, ज्यादातर पोस्टर्स पर सरकारी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, युवाओं का पलायन, महंगाई, गरीबी जैसे मुद्दों से जुड़े नारे लिखे थे, इससे साफ होता है कि जेन-जी का यह आंदोलन हाईजैक हो गया है।

बाबू सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

दक्षिण एशिया में कौन आग लगा रहा है? श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अब नेपाल को हिंसा की आग में किसने झोंका? कोई कह रहा है कि इसके पीछे अमेरिकन डीप स्टेट का हाथ है, कोई कह रहा है कि चीन के इशारे पर ये सब हो रहा है। लेकिन इन सब से अलग एक बड़ी वजह नेपाल के भ्रष्ट सत्ताधीशों के खिलाफ जनाक्रोश भी है। दक्षिण एशिया में भारत के अलावा नेपाल ही एकमात्र हिंदू-बहुल देश हैं। नेपाल की कुल जनसंख्या में लगभग 81 प्रतिशत यानी 2021 के आंकड़ों के अनुसार 2.36 करोड़ हिंदू हैं जबकि मुस्लिम आबादी 5 प्रतिशत के करीब है। ये वही नेपाल है जिसने 1996 में राजशाही के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन शुरू किया था। फिर 10 वर्षों की हिंसा और अस्थिरता के लंबे दौर से गुजरने के बाद 2006 में जन आंदोलन को अलविदा कहा और 2008 में माओवादियों की जीत के बाद 240 साल पुरानी राजशाही का अंत हुआ था। नेपाल हिंदू राष्ट्र की जगह एक गणतांत्रिक देश बन गया था। राजशाही परंपरा के अंत के बाद जनता के हालात कितने बदले? यह सवाल आज भी जस का तस है। क्योंकि दो दशकों में 13 सरकारें बनी, कई सरकारें गिरी। सत्ता में जो भी रहा उसका विकास हुआ और आम जनता महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से संघर्ष करती रही। लिहाजा नेपाल की सरकारों से निराश जनता एक बार फिर सड़कों पर उतरने को विवश हुई। वैसे जनता के हिंसक होने के पीछे कोई एक वजह नहीं है। इसके पीछे नेताओं का भ्रष्टाचार, नेताओं के परिवारों की शाही जिंदगी, आम आदमी की गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, डेमोग्राफी चेंज, हिंदू राष्ट्र की घोषणा के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रतिबंध नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई? इन सभी मुद्दों पर नेपाल की जनता सरकार को चेता रही थी, लेकिन सत्ता के नशे में जनता की भावनाओं को समझने में सत्ताधारियों ने देर कर दी और जब तक समझ में आया तब तक चिंगारी शोला बन गई। भारत और चीन के बीच स्थित इस हिमालयी देश नेपाल के लिए यह संकट सबसे खराब और खतरनाक है। यह हिंसा 2006 के विद्रोह से भी बड़ी है। नेपाल में जिस तरह अराजकता फैली उसने नेपाल को दशकों पीछे धकेलने का ही काम किया है। किंतु राहत की बात ये है कि हिंसा के पांचवें दिन नेपाल में तमाम उथल-पुथल के बाद सुशीला कार्की के रूप में नया प्रधानमंत्री मिल गया।

नेपाल सेना व पुलिस बेबश

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में जेनरेशन जेड के आंदोलन ने पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। जेन-जी के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के आगे चार बार के प्रधानमंत्री और अनुभवी राजनेता केपी शर्मा ओली को घुटने टेकने पड़े। उन्हें इस्तीफा देकर अज्ञात जगह पर भागना पड़ा। नेपाल में सरकार को उखाड़ फेंकने वाली जेनरेशन-जेड हैशटैग या मीम्स में पैदा नहीं हुई थी। बल्कि नेपाल सरकार के भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, वंशवाद, महंगाई, बेरोजगारी और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ चिंगारी से शोला बनी। इसलिए जेन-जी के आक्रोश और देशव्यापी हिंसा के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। केपी शर्मा ओली ने अपने त्यागपत्र में लिखा कि वह राजनीतिक तरीकों से नेपाल की समस्या के समाधान में मदद के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफे के बाद भी काठमांडू, पोखरा और देश के कई शहरों में सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे। नेपाल की पुलिस और सेना भीड़ के सामने बेबश नजर आई। लिहाजा भीड़ ने संसद भवन, प्रधानमंत्री निवास, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, तमाम बड़े राजनीतिक दलों के दफ्तरों, बैंकों, मंत्रियों के कार्यालय, आवास और कई बड़े होटलों को आग के हवाले कर दिया। अराजकता का आलम ये था कि जेन-जी के प्रदर्शकारियों ने 9 सितंबर को नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के घर में आग लगा दी। जिस समय आग लगाई पूर्व पीएम खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार घर में थी। उनके गंभीर रूप से झुलसने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। आग की इस घटना से पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल को नेपाली सेना ने बचा लिया था। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा पर उनके आवास के अंदर घुस कर अराजक आंदोलनकारियों ने हमला कर दिया। जो मंत्री हाथ लगा उसे भीड़ ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को भी उग्र भीड़ ने नहीं बख्शा। इसके बाद माना गया कि जेन-जी का आंदोलने अराजक तत्वों ने हाईजैक कर लिया। जेन-जी आंदोलन हाईजैक

जेन-जी प्रदर्शनकारियों के बीच अराजक तत्व घुसे और जेन-जी को बदनाम करने के लिए लूटपाट, आगजनी, तोड़फोड़ की, क्योंकि जो प्रदर्शकारी नेपाल को हिंदू राष्ट्र मानते हैं वो कभी भी पशुपतिनाथ मंदिर में बलपूर्वक नहीं घुसेंगे? वो क्यों मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे?

प्रदर्शनकारियों के बीच घुसे अज्ञात अराजक तत्वों ने नक्खू जेल में घुसकर रबी लामिछाने को छुड़ा लिया। रबी 2022 से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष हैं। दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक नेपाल के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे हैं। उनके साथ 13000 और बंदी नेपाल की जेलों से भाग गए। काठमांडू का इंटरनेशनल हवाई अड्डा बंद करना पड़ा। प्रदर्शनकारी एयरपोर्ट में घुस कर देश से भागने वाले नेताओं, मंत्रियों और अफसरों को रोक कर नेपाल में ही सजा देने का नारा बुलंद करने लगे थे। हालांकि सेना ने अपने हेलीकाप्टरों की मदद से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित कुछ मंत्रियों को सेना के बैरक में सुरक्षित पहुंचा दिया था। 9 सितंबर को भीड़ इसलिए उग्र हुई क्योंकि 8 सितंबर को पुलिस फायरिंग में 21 नेपाली युवाओं की मौत हो गई थी। 250 से ज्यादा घायल हो गए थे। ज्यादातर मृत और जख्मी युवाओं के सीने में गोलियां लगी थी। 3 सितंबर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस पर बैन लगा और 8 सितंबर को आंदोलन शुरू हो गया। लाखों की तादाद में नौजवान सड़कों पर आ गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने जो पोस्टर्स हाथों में ले रखे थे, उनमें सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ नारे नहीं थे। ज्यादातर पोस्टर्स पर सरकारी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, युवाओं का पलायन, महंगाई, गरीबी जैसे मुद्दों से जुड़े नारे लिखे थे। इससे साफ है कि जेन-जी का यह आंदोलन हाईजैक हो गया था। प्रदर्शकारियों के नाम पर अराजक तत्वों ने पशुपतिनाथ मंदिर तक में घुसने की कोशिश की गई। यानी प्रदर्शन करने वालों के बीच अराजक तत्व घुसे और जेन-जी को बदनाम करने के लिए लूटपाट, आगजनी, तोड़फोड़ की। क्योंकि जो प्रदर्शकारी नेपाल को हिंदू राष्ट्र मानते हैं वो कभी भी पशुपतिनाथ मंदिर में बलपूर्वक नहीं घुसेंगे? वो क्यों मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे?

भारत और चीन के बीच स्थित इस हिमालयी देश नेपाल के लिए यह संकट सबसे खराब और खतरनाक है, जेन-जी की आड़ में जो हिंसा का तांडव हुआ वो 2006 के विद्रोह से भी बड़ा है, नेपाल में जिस तरह अराजकता फैली उसने नेपाल को दशकों पीछे धकेलने का ही काम किया है।

तख्तापलट के बाद कंफ्यूजन

नेपाल में केपी शर्मा ओली सरकार का तख्तापलट के बाद कंफ्यूजन बरकरार है। क्योंकि नेपाल में तख्तापलट के पीछे चार चेहरे प्रमुख रहे हैं, जिनकी वजह से नेपाल में तख्तापलट की नौबत आई। इनमें पहला नाम है सुदन गुरुंग, दूसरा नाम बालेन शाह, तीसरा नाम जेल से फरार हुए रबि लमिछाने और चौथा नाम नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का है। जेन-जी के आंदोलन के सूत्रधार यही चार किरदार हैं। अब सवाल यही है कि नेपाल की राजनीति में इन चारों चेहरों का क्या असर है? क्या ये चेहरे नेपाल के नए भविष्य की इबारत लिखने में आगे आ सकते हैं? इन चारों किरदारों के समर्थकों में फूट पड़ गई है। 10 सितंबर को यह फूट साफ साफ देखी गई। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की चर्चा के बीच पहले काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह और जेन-जी के संयोजक सुदन गुरुंग का नाम चर्चा में आया। फिर शाम होते होते पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने पर सहमति की खबरें आने लगीं। इसी बीच धरान के मेयर हरक सांगपांग के नाम को लेकर कुछ युवाओं ने नारेबाजी कर दी। सेना मुख्यालय में हुई बैठक में एक गुट ने सुशीला कार्की की उम्र अधिक बताते हुए उनके नाम पर असहमति जता दी। कुछ और समूह भी सामने आ गए, जिन्होंने संविधान का हवाला देते हुए सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का विरोध कर दिया। एक गुट बालेंद्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर अड़ा था, लेकिन शाह ने इस पद को स्वीकार करने से मना कर दिया है और चुनाव के माध्यम से सरकार में आने की इच्छा जताई। इसलिए नेपाल के भविष्य का अभी कोई स्थाई समाधान नजर नहीं आ रहा था। 12 सितंबर को नेपाल के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख ने फिर बैठक बुलाई और अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर सहमति बनाने के लिए प्रदर्शकारियों के प्रतिनिधियों से वार्ता की। जिसका सकारात्म नतीजा सामने आया और अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई। इसके कुछ ही घंटों बाद सुशीला कार्की को राष्ट्रपति ने शपथ भी दिला दी। अब सुशीला कार्की के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेपाल में शांति बहाल करने की है। दूसरी चुनौती प्रदर्शन के दौरान नेपाल में आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट करने वालों से निपटने की है। तीसरी चुनौती नेपाल को फिर से पटरी पर लाने की है, जो हिंसा के दौरान बेपटरी हो चुका है।

अरबों होगा नुकसान

नेपाल में हिंसा की वजह से अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक तरह के कहा जाए कि नेपालियों ने अपने हाथों से अपने ही घर में आग लगाई है। क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, मंत्री, सांसदों के आवास, बैंक तक फूंक डाले इससे सरकार को अरबों रुपये का नुकसान होने का अंदेशा है। अकेले नेपाल की संसद को बनाने में सरकार के 43.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगे थे। लिहाजा हिंसक प्रदर्शन का नुकसान सीधे तौर पर नेपाल की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। इसकी भरपाई भी नेपालियों को ही करनी होगी। इसलिए कहा जा सकता है कि नेपालियों ने अपने ही घरों को फूंका है। नेपाल में हिंसा का असर भारत पर भी हुआ है। काठमांडू हवाई अड्डा बंद होने से एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस को उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। इससे इन कंपनियों को आर्थिक नुकसान हुआ है, क्योंकि पर्यटकों की बुकिंग रद्द हो गई और नई बुकिंग प्रभावित हो गई। ट्रैवल कंपनियों को नेपाल के लिए ग्रुप टूर रोकने पड़े। ●

पहाड़ियों में छिपा ओसला गांव

सेब के पेड़ों से घिरे ओसला गांव तक पहुंचने के लिए सैलानियों को सांकरी में प्रशासन से अनुमति लेनी होती है, लगभग 5 हजार साल पुराना ओसला गांव हर की दून ट्रेक पर है, एक तरह से कहा जाए तो उत्तरकाशी जिले का यह गांव ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे छिपा है।

आदर्श ओझा
ओसला, उत्तरकाशी

कल्पना कीजिए कि आप शहर की भीड़भाड से दूर खूबसूरत पहाड़ों और हरियाली से घिरे एक गांव में हैं। जहां जिंदगी धीमी से भी धीमी चलती है। लेकिन तेज और ठंडी हवाएं चेहरे को स्पर्श करती हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। मैं आपको उत्तराखंड के एक ऐसे ही प्राचीन गांव की सैर पर ले जाना चाहता हूं जो सुंदर तो है ही साथ ही पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। उत्तराखंड के इस सुंदर गांव का नाम ओसला है। ओसला वो गांव है जहां पांडवों की नहीं बल्कि कौरवों में दुर्योधन की पूजा होती है। इस गांव तक पहुंचना भले ही आसान नहीं है, लेकिन रास्ते में पहाड़ के खूबसूरत नजारे थकान को करीब भी नहीं आने देते। ये वही गांव है जहां से हिमालय की सफेद चोटियों से सीधे सामना होता है। सेब के पेड़ों से घिरे ओसला गांव तक पहुंचने के लिए सैलानियों को सांकरी में प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। लगभग 5 हजार साल पुराना ओसला गांव हर की दून ट्रेक पर है। एक तरह से कहा जाए तो उत्तरकाशी जिले का यह गांव ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे छिपा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि समुद्र तल से 2,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस गांव में अभी तक बिजली नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है और कोई सड़क भी नहीं है। गांव तक पहुंचने के लिए अभी भी चार किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है, सर्दियों में तापमान माइनस 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यह क्षेत्र दुर्लभ वन्यजीव हिम तेंदुओं और काले भालुओं का घर भी है। यानी ओसला गांव गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। संसाधनों का अभाव है लिहाजा ओसला गांव के सभी परिवार की बहुत साधारण हैं और आत्मनिर्भर जीवनशैली है। अलबत्ता इस गांव के परिवारों की आजीविका सेब, आलू, राजमा और चावल की खेती पर निर्भर है। क्योंकि यह इलाका पहाड़ी है, इसलिए यहां सीढ़ीदार खेत हैं। पशुपालन में कई परिवार भेड़-बकरियों के पालन पर निर्भर हैं, जिनसे उन्हें कपड़े के लिए ऊन, पीने के लिए दूध और खाने के लिए मांस मिल जाता है। चूंकि यह एक ट्रैकिंग मार्ग भी है, इसलिए ओसला गांव के कुछ लोग ट्रैकिंग के लिए सामान और रसद ढोने के लिए खच्चर पालते हैं। ट्रैकिंग मार्ग की वजह से यहां होमस्टे भी कमाई का एक हिस्सा बन रहे हैं। कुल मिलाकर यह ओसला गांव एक संदेश तो देता ही है कि सीमित संसाधनों के बावजूद गांव इनका भरपूर उपयोग करता है। यानी जीवन में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है जैसी नजीर पेश करता है। इस गांव में पहुंच कर हर किसी को ऐसा लगता है कि हमारे पास जितने ज्यादा विकल्प और अवसर होते हैं, हम उतने ही ज्यादा अधूरे होते हैं।

ओसला गांव एक संदेश तो देता ही है कि सीमित संसाधनों के बावजूद ये गांव उनका भरपूर उपयोग करता है, यानी जीवन में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है जैसी नजीर पेश करता है, इस गांव में पहुंच कर लगता है कि हमारे पास जितने ज्यादा विकल्प होते हैं, हम उतने ही ज्यादा अधूरे होते हैं।

सोमेश्वर देवता में विश्वास

ओसला गांव सिर्फ ट्रैकिंग के लिए ही विख्यात नहीं है बल्कि यहां देवी देवताओं के अनेक मंदिर है। लेकिन बहुत से पहाड़ी परिवार सोमेश्वर देवता को अपना कुल देवता और ग्राम देवता मानते हैं। गांव के परिवार भगवान शिव के रूप में मुख्य रूप से सोमेश्वर देवता को ही पूजते हैं और अटूट विश्वास रखते हैं। सोमेश्वर देवता कई गांवों में स्थानीय देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। इसलिए प्रत्येक गांव में मंदिर होता है, जो सोमेश्वर देवता को समर्पित होता है। सोमेश्वर की पवित्र मूर्ति कभी स्थिर नहीं रहती है। यह प्रत्येक स्थान पर पारंपरिक कैलेंडर और विशिष्ट महीनों के आधार पर एक गांव से दूसरे गांव में जाती रहती है। ओसला गांव का मंदिर गांव के केंद्र में स्थित है जो प्राचीनकाल में लकड़ी की वास्तुकला से बनाया गया था। लकड़ी के मंदिर पर रामायण काल के भगवान श्रीराम, सीताजी, लक्ष्मणजी, हनुमानजी, महाभारत काल के श्रीकृष्ण, पत्ते, पक्षियों में मोनाल, वन्यजीवों की खूबसूरत नक्काशी है। गांव के मंदिर में एक विशेष परिवार या जाति (बाजगी जिसे औजी या ढोली भी कहा जाता है) द्वारा अनुष्ठान किया जाता है। औजी मंदिर के सामने दिन में दो बार ढोल बजाने के लिए मंदिर के पास ही रहते हैं। ओसला गांव का अपना पौराणिक महत्व भी है। गांव के पास में ही एक शानदार स्वर्ग रोहिणी चोटी है। कहा जाता है कि महाभारत काल में युधिष्ठिर एक कुत्ते के साथ इसी चोटी से स्वर्ग गए थे। इसलिए यह इलाका महाभारत काल के लिए भी जाना जाता है। लोकमान्यता है कि ओसला गांव में सोमेश्वर देवता के साथ बहुत से लोग दुर्योधन की पूजा करते हैं। इसके पीछे कहानी यह है कि दुर्योधन ओसला गांव पहुंचा तो उसे गांव के संरक्षक महासू देवता के बारे में पता चला। दुर्योधन ने महासू देवता को प्रसन्न किया और बदले में महासू देवता ने दुर्योधन को यह गांव सौंप दिया था। दुर्योधन ने गांव के परिवारों की रक्षा की इसलिए गांव के लोगों ने दुर्योधन का मंदिर बनाकर महाभारत काल से ही पूजा अर्चना शुरू कर दी।

ओसला की जीवनशैली

ओसला की महिलाएं भेड़ के बालों से ऊन बनाकर हाथ से कपड़े बनाने की अपनी पुरानी हस्तशिल्प कला का उपयोग करती हैं। यह सब पहले ऊन संग्रह की प्रक्रिया से शुरू होता है। यानी सबसे पहले भेड़ों के बाल काटे जाते हैं। यह प्रकिया आमतौर पर गर्मियों में शुरू की जाती है। ताकि कच्ची ऊन इकट्ठा कर सकें, इस ऊन में धूल और अन्य अशुद्धियां होती हैं इसलिए अगली प्रक्रिया में वे ठंडे पानी की मदद से ऊन को साफ करती हैं और इसे धूप में सुखाती हैं। इसे सुखाने के बाद वे पारंपरिक तकली का उपयोग करके धागा तैयार करती हैं, यानी सूत बनाती हैं। इससे ऊन लंबे धागों में बदल जाती है। महिलाएं घरों में बुनाई के लिए बने पारंपरिक हथकरघा की मदद से कपड़ा बुनती हैं। जिनसे शॉल, घाघरी (लंबी स्कर्ट), कमीज आदि सिलाई कर तैयार होती है जो माइनस 15 डिग्री सेल्सियस में उन्हें गर्म रखने के लिए पर्याप्त होते हैं। ओसला गांव के लोग मेहनती, दयालु, प्यार करने वाले, अतिथि का स्वागत करके खुश होने वाले हैं। बुजुर्गों से बात करने पर 70 साल पुरानी पहाड़ी जीवनशैली, धार्मिक मान्यताओं के साथ ऐतिहासिक महत्व की जानकारी मिल जाती है, उत्तराखंड गठन के 25 साल बाद भी गांव में अलग-थलग रहने के अनुभव कराते हैं। युवाओं की मासूमियत महिलाओं का स्नेह उनकी जड़ों का अनुभव कराते हैं। यहां पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता है इसलिए सभी एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, पारंपरिक गीतों पर एक साथ नृत्य करते हैं और खुशियां साझा करते हैं। गांव वालों ने पुराने जमान से अपने लिए कुछ नियम-कानून बना रखे हैं। उनकी अपनी सरकार भी है। सरकार यानी एक राजा है जो महीने में एक बार गांव का दौरा करता है और उस समय पूरे गांव के लिए मुख्य पूजा की जाती है। गांव में करीब 250 घर और 600 से ज्यादा की आबादी है।

किस्सा ट्रैकर्स का

मैं हिमालय शेल्टर संस्था का हिस्सा हूं। यह संस्था ट्रैकर्स को गाइड करने का काम करती है। एक बड़ा ही रोचक किस्सा है जब हमारे ट्रैकर्स अनिल चंदन और उनके परिवार ने हर की दून यानी शिव की घाटी ट्रेक का भरपूर आनंद लिया और ट्रेक पूरा करने के बाद उन्होंने ओसला गांव के होमस्टे में रुकने की योजना बनाई। वो पहले से ही ओसला के बच्चों के लिए कलर किट और रंग भरने वाली ड्राइंग की किताबें उपहार में देने के लिए साथ में लाए थे। ओसला गांव पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया ताकि अगले दिन उपहार वितरण की व्यवस्था कर सकें। स्थानीय शिक्षक और ओसला के लोगों की मदद से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीण सोमेश्वर देवता के मंदिर के पास एकत्र हुए। सभी बच्चे अपने माता-पिता के साथ मंदिर पहुंचे तो अनिल चंदन व उनके परिवार ने बच्चों के लिए कुछ मजेदार खेल और व्यायाम किए। खेलते समय बच्चे बहुत खुश और ऊर्जावान थे, अनिल और उनके परिवार ने भी उन्हें प्रेरित किया और बच्चों का मार्गदर्शन किया। यह 1 घंटे का क्षण था जब अनिल और उनके परिवार ने ओसला गांव के बच्चों के प्रति अपने प्यार के रूप में खुशियां बांटी। ओसला के लोगों ने भी इन विशेष क्षणों का भरपूर आनंद लिया। यह एकजुटता और खूबसूरत जुड़ाव का एक पल था। जब मैं अगली बार अपने ट्रैकस के साथ अपने गांव ओसला गया तो बच्चे अपने भाई-बहन के साथ मिलकर चित्र में रंग भर रहे थे और कुछ घरों में उनकी मां उन्हें चित्र में रंग भरना सिखा रही थीं। इस पल मुझे बस यही लग रहा था कि अनिल चंदन बस यही करना चाहते थे, उनका मकसद उन अलग-थलग रहने वाले खूबसूरत चेहरों पर मुस्कान लाना था।

- **ओसला गांव उत्तराखंड के रिमोट इलाकों में से एक है, सर्दियों में यहां जमकर बर्फबारी होती है, बरसात में पहाड़ की यात्रा नहीं करनी चाहिए, अगर हरियाली का मजा लेना चाहते हैं तो मई-जून में ओसला का अच्छा मौसम रहता है, इसके अलावा बर्फबारी के लिए सर्दियों के मौसम में यहां आ सकते हैं।**
- **संसाधनों का अभाव है लिहाजा ओसला के सभी परिवारों की साधारण हैं व आत्मनिर्भर जीवनशैली है, इस गांव के परिवारों की आजीविका सेब, आलू, राजमा और चावल की खेती पर निर्भर है, पशुपालन में कई परिवार भेड़-बकरियों के पालन पर निर्भर हैं।**

कैसे पहुंचे ओसला गांव

ओसला गांव पहाड़ों से घिरा बेहद सुंदर गांव है। यानी ये ओसला गांव उत्तराखंड के रिमोट इलाकों में से एक है। सर्दियों में यहां जमकर बर्फबारी होती है। बरसात में पहाड़ की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर हरियाली का मजा लेना चाहते हैं तो मई-जून में ओसला का अच्छा मौसम रहता है। इसके अलावा बर्फबारी के लिए सर्दियों के मौसम में यहां आ सकते हैं। गांव में ठहरने के लिए कई सारे होमस्टे हैं जिनमें ठहर सकते हैं। ओसला गांव पहुंचने के लिए सबसे पहले संकरी गांव पहुंचना होगा। अगर देहरादून से यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो देहरादून से संकरी गांव की दूरी लगभग 190 किलोमीटर है। देहरादून से संकरी पहुंचने के दो विकल्प हैं। यदि बजट के अनुकूल यात्रा करना चाहते हैं, तो देहरादून से पुरोला तक बस ले सकते हैं (बस सुबह जल्दी चलती है) फिर पुरोला से सांकरी तक पहुंचने के लिए एक साझा जीप ले सकते हैं, या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें लगभग 12 घंटे का सफर करना होगा। दूसरा विकल्प निजी टैक्सी लेना है, जो देहरादून रेलवे स्टेशन और देहरादून हवाई अड्डे से सीधे सांकरी तक उपलब्ध है और निजी टैक्सी से यह सफर लगभग 7 से 8 घंटे में पूरा हो जाता है। संकरी पहुंचकर गंगाड तक पहुंचने के लिए केवल एक ही विकल्प है। यह वह गांव है जहां से ओसला गांव तक पहुंचने के सार्वजनिक परिवहन या निजी टैक्सी लेकर संकरी से गंगाड गांव 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। फिर ओसला गांव तक पहुंचने के लिए गंगाड से साढे तीन किलोमीटर की पैदल यात्रा ही एक मात्र विकल्प है। ओसला गांव से कई ट्रेक हैं। इनमें उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय ट्रेक में से एक है हर की दून घाटी, जिसे भगवान या शिव की घाटी भी कहा जाता है।

बागी हो रहे कांग्रेसी

कांग्रेस के भीतर लगातार जो असंतोष के सुर सुनाई दे रहे हैं वो सरेआम हो रहे हैं, शशि थरूर, केएन राजन्ना, अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, इन सब के पीछे एक बड़ी वजह संवादहीनता भी है, क्योंकि राहुल गांधी या कहें गांधी फैमिली सिर्फ गिनती के नेताओं से ही संवाद करती है।

अतुल सिन्हा
टीवी जर्नलिस्ट

पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के कई बड़े नेता खुलकर कांग्रेस के खिलाफ अपनी बात रख रहे है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरह सरकार पर बिना किसी सबूत के गंभीर आरोप लगाते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ बयान देते हैं, विदेशों में देश के लोकतंत्र को कमजोर बताते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी नेताओं व आर्मी चीफ की तरह भारत की सेना पर सवाल उठाते हैं या देश की इकनॉमी को डेड बताते हैं उससे कांग्रेसी खुद को असहज समझने लगते हैं, लेकिन पार्टी में रहना है तो किसी की मजाल नहीं कि वो राहुल गांधी को कोई नसीहत दे सके। फिर राहुल गांधी की आदत ऐसी हो गई है कि वो सही कहें या गलत वो जो कहते हैं वही सच है। अब यदि राहुल गांधी सत्य और तथ्य को नहीं समझ पाते हैं तो ये कमजोरी उनकी है। शायद इसलिए कांग्रेस छोड़ चुके वरिष्ठ नेता गुलाम नवी आजाद ने टीवी शो आपकी अदालत में कहा था कि राहुल गांधी को वो काम नहीं करना चाहिए जो उनके लिए है ही नहीं। कोई भी कार्य किसी से जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता, उनके कहने का अर्थ था कि राहुल गांधी को राजनीति में दिलचस्पी नहीं है तो क्यों कर रहे हैं...? उनके परदादा पंडित जवाहर लाल नेहरू, दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी फुल टाइम पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन राहुल गांधी तो 24 मिनट भी पॉलिटिक्स नहीं करते। राहुल गांधी को राजनीति की एबीसीडी तक नहीं आती। वो भी नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत और लोकप्रिय नेता के सामने जो 24 घंटे में 26 घंटे काम करने की कुब्बत रखते हैं। राहुल गांधी को लेकर ये वो टिप्पणी थी जिस पर शो में सबसे ज्यादा ताली बजी थी। खैर गुलाम नवी आजाद ने तो कांग्रेस छोड़ने के बाद इस तरह की टिप्पणी की, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए सांसद शशि थरूर और सोनिया गांधी के करीबी रहे दिग्गज नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल कांग्रेस की नीतियों का खुलकर कर विरोध कर रहे हैं। शशि थरूर ने तो बहुत पहले से ही कांग्रेस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे, लेकिन ताजा बयान पहलगाम में आतंकी हमले के बाद आया था। जब उन्होंने कांग्रेस की लाइन से हटकर सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया था। बाद में ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो सांसदों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए कई देशों में भारत का पक्ष रखने भी गए और भारत सरकार का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मजबूत पक्ष रखा था। अब शशि थरूर ने सरकार के 130वें संविधान संशोधन का समर्थन कर दिया है।

मंत्री ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला

शशि थरूर के बाद कर्नाटक के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'मिशन वोट चोरी' के बीच कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, लिहाजा उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। राहुल गांधी बिहार में मतदाता सूची में संशोधन शुरू किए जाने के बाद से ही चुनाव आयोग और सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। फर्जी आंकड़ों वाली मतदाता सूची दिखाकर उन्होंने परमाणु विस्फोट करने का दावा किया था, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री और सीएम सिद्दारमैया के बड़े समर्थक माने जाने वाले केएन राजन्ना ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी के बयान

> **राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने कहा कि हार की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थोपने से बेहतर होगा कि पार्टी खुद भी इसकी जिम्मेदारी ले, क्योंकि वोटर लिस्ट तो कांग्रेस सरकार में ही बनी थी, तो क्या हमारी सरकार नाकामी नहीं है।**

पर प्रतिक्रिया देते हुए राजन्ना ने कहा कि हार की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थोपने से बेहतर होगा कि पार्टी खुद भी इसकी जिम्मेदारी ले। वोटर लिस्ट में सुधार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट तो कांग्रेस सरकार में ही बनी थी, तो क्या हमारी सरकार नाकामी नहीं है। 'वोटर लिस्ट में सुधार सामान्य प्रक्रिया है। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी यह प्रक्रिया हुई थी। तब पार्टी ने क्यों आंख बंद कर ली थी? अगर यह सच है कि चुनाव में धांधली हुई है, तो यह हमारे लिए शर्म की बात है कि राज्य में हमारी सरकार के रहते हुए हमारी नाक के नीचे यह सब कैसे हो रहा था?' राजन्ना ने सिद्दारमैया सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'अगर चुनाव में धांधली हुई थी तो हमने तब सवाल क्यों नहीं उठाया? खासकर महादेवपुरा में, जहां भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए। तब हमने चुप्पी साधे रखी। अब हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं।' राजन्ना के साथ ही कर्नाटक में जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व केंद्रयी मंत्री सीएम इब्राहिम द्वारा 2018 के विधानसभा चुनावों के दौरान कथित तौर पर वोट खरीदने के खुलासे के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है। यह मुद्दा भाजपा सांसद लहर सिंह सिरोया ने उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त से इस मामले की जांच के लिए औपचारिक रूप से याचिका दायर की है। साक्ष्य के रूप में सीएम इब्राहिम के भाषण की एक वीडियो भी पेश की गई है जिसमें इब्राहिम दावा कर रहे हैं कि 2018 के चुनाव में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने 3,000 वोट खरीदे थे। 2018 में बादामी विधानसभा सीट से सिद्धारमैया की जीत का अंतर केवल 1,696 वोटों का था। जबकि नोटा पर 2,007 वोट पड़े थे। यही वह चुनाव था जिसमें सिद्धारमैया अपनी पारंपरिक सीट चामुंडेश्वरी से हार गए थे।

राहुल हज यात्रा करें

शशि थरूर के बाद कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा करने वाले कर्नाटक के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना को मंत्री पद से हटा दिया गया। हालांकि शशि थरूर को पार्टी से अभी बेदखल नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी शशि थरूर से बेहद खफा है। अब सोनिया गांधी के बेहद करीबी और उनके रणनीतिकार रहे दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने खुलकर नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ की है। फैसल ने कहा कि हमारा देश सशस्त्र बलों की वजह से सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कड़ी मेहनत करके देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे है। देश में महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं को लेकर अच्छा काम हो रहा है। फैसल ने कहा कि कांग्रेस खुद की अपनी अलग दुनिया में जी रही है इसलिए कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। भाजपा की खूबी यही है कि वो पूरा कंट्रोल रखना जानती हैं और हर सामने वाली राजनीतिक पार्टी को खत्म करने की कोशिश करती है। आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा, राजद, शिवसेना, एनसीपी का क्या हाल हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। फैसल पटेल ने कहा कि राहुल गांधी मेहनती नेता तो हैं, लेकिन कांग्रेस में शशि थरूर, डीके शिवकुमार, रेवंत रेड्डी, दीपेंद्र हुड्डा और सचिन पायलट जैसे कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान नेता भी है। लेकिन इसके बाद उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता है। पार्टी में अंदरूनी तौर पर दिक्कतें हैं। मेरा मानना है कि पार्टी चलाने वाले वरिष्ठ नेताओं को युवा नेताओं को मौका देना चाहिए। पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की सलाह पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए भी पार्टी को नुकसान हो रहा है। मैं कांग्रेस का हिस्सा हूं और पार्टी की बहुत सारी बातों पर मेरी असहमति है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने हमारे देश को मुश्किल हालात से निकाला है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान है। एस जयशंकर के लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा सम्मान है। जिस तरह से पीएम मोदी अपनी सरकार चला रहे हैं वो वाकई तारीफ के काबिल है। हाल ही में फैसल पटेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने कांग्रेस के लिए काम करना बंद कर दिया है। मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन कांग्रेस ने मुझे आज तक मौका नहीं दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा के सलाहकार रहे पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का मजाक बनाते हुए कहा कि उन्हें बिहार में यात्रा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें 'हज यात्रा' से ज्यादा फायदा हो सकता है। इसलिए 'हज यात्रा' करनी चाहिए। प्रमोद कृष्ण को तीन साल पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था।

कांग्रेस में हाईकमान कौन?

इसी साल मार्च में राहुल गांधी ने गुजरात दौरा कर बड़ा बम फोड़ने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि गुजरात कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा से मिले हुए हैं। जरूरत पड़ी तो

> **पंडित जवाहर लाल नेहरू, राहुल की दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी फुल टाइम पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन राहुल गांधी तो 24 मिनट भी टिक कर पॉलिटिक्स नहीं करते, वो राजनीति की एबीसीडी तक नहीं जानते, यह कहना है पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का।**

पार्टी को 20 से 30 लोगों को कांग्रेस से निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए। राहुल गांधी की इस बात से कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैरान रह गए थे। कई कांग्रेसी नेताओं को तो राहुल का 2013 वाला बयान याद आ गया। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस को इस तरह बदलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। दुर्भाग्य से वो बदलाव करने वाला दिन दिल्ली में आज तक नहीं आया। हां एक बदलाव जरूर आया है वो ये कि कांग्रेस के अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन हो, लेकिन हाईकमान गांधी परिवार ही है। ये बात कई मौके पर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कह भी चुके हैं। जून में कर्नाटक में संभावित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर नए सिरे से चल रही चर्चा के बारे में मीडिया ने जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल किया तो उनका एक ही जवाब था 'यह पार्टी हाईकमान के हाथ में है।' डीके शिवकुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर खड़गे ने मीडिया से कहा था, 'कोई नहीं कह सकता कि हाईकमान में क्या चल रहा है।' ऐसे में सवाल उठता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की खुद की कांग्रेस में हैसियत क्या है? क्या वो भी भारत के प्रधानमंत्री रहे डा. मनमोहन सिंह की तरह रिमाट कंट्रोल वाले कांग्रेस अध्यक्ष हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का जमीर इतना गिर चुका है कि वो अपने बेटे-बेटियों की उम्र के राहुल गांधी के इशारों पर नाचते हैं। करीब तीन साल पहले गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था। तब तय किया गया था कि खड़गे पार्टी चलाएंगे और गांधी परिवार पर्दे के पीछे से मदद करेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि खड़गे भी राहुल के हस्तक्षेप से नाखुश हैं।

संवादहीनता से खोखली होती कांग्रेस

कांग्रेस के भीतर बगावत और असंतोष का उभरना कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक कई राज्यों में बगावती सुर उभरे हैं। कुछ राज्यों में पार्टी इसे दबाने में कामयाब रही तो कई प्रदेशों में भारी कीमत चुकानी पड़ी। मध्य प्रदेश में सिर्फ 15 महीने में कमलनाथ सरकार का गिरना हो या फिर आपसी गुटबाजी और असंतोष के कारण पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में करारी हार मिलना हो। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में पार्टी के आधा दर्जन विधायकों के क्रॉस वोटिंग कर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडराना हो। ये वो घटनाक्रम है जिससे साबित होता है कि कांग्रेस विद्रोह की ज्वाला भड़कने का इंतजार कर रही है? कांग्रेस के भीतर लगातार कई स्तरों पर जो असंतोष के सुर सुनाई दे रहे हैं वो अब सरेआम हो रहे हैं। शशि थरूर, केएन राजन्ना, अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। इन सब के पीछे एक बड़ी वजह संवादहीनता भी है। क्योंकि राहुल गांधी या कहें गांधी फैमिली सिर्फ गिनती के ही नेताओं से संवाद करती है। कार्यकर्ताओं या बाकी पदाधिकारियों से गांधी परिवार का संवाद एक दम बंद है। कांग्रेस के भीतर संवादहीनता का यह सिलसिला केंद्रीय नेतृत्व से लेकर क्षेत्रीय नेतृत्व तक जारी है। कांग्रेस के भीतर एक बड़ी समस्या आम कार्यकर्ताओं से लेकर विधायकों, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं तक से केंद्रीय नेतृत्व के दूरी बनाए रखने की है। यही वजह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद जब आम कार्यकर्ता या नेता हाईकमान तक नहीं पहुंच पाता तो संवादहीनता बढ़ने लगती है। केंद्रीय नेतृत्व जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं से कट चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर मिलिंद देवड़ा तक तमाम ऐसे नेता रहे जिन्होंने पार्टी छोड़ते समय यही आरोप लगाया था कि हाईकमान से संपर्क करने की कोशिश में उन्हें महीनों इंतजार करने के बाद भी वक्त नहीं मिला। गांधी परिवार, खासकर राहुल गांधी से वक्त न मिलने की शिकायत तो आम थी, लेकिन कांग्रेस की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में आने के बाद भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस खोखली होती जा रही है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि जिसे पार्टी में रहना है रहे जिसे जाना है वो जाए। इस तरह के विचार ही पार्टी का सर्वनाश करने के लिए काफी होते हैं। यही हाल रहा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को इतिहास में पढ़ाया जाए, देश में एक थी कांग्रेस।

नजरिया

विद्या भारती का मिशन शिक्षा

विद्यार्थी को शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण कर अधिक अंक लाने के लिए नहीं दी जाती, वह तो जीवन की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हुए कुलदीपक बनाने के लिए समाजसेवी बनाने के लिए देशभक्त निर्माण करने के लिए तथा संपूर्ण मानवता के लिए जीवन खपाने के लिए दी जाती है।

राकेश मैन्दोला
मांडूवाला, देहरादून

बालक ही हमारी आशाओं का केंद्र है, वही हमारे देश, धर्म एवं संस्कृति के रक्षक हैं, उसके व्यक्तित्व के विकास में हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का विकास निहित है। आज का बालक ही कल का कर्णधार है। बालक का नाता भूमि एवं पूर्वजों से जोड़ना, यह शिक्षा का सीधा, सरल तथा सुस्पष्ट लक्ष्य है। शिक्षा और संस्कार द्वारा ही बालक का सर्वांगीण विकास संभव है। बस यही स्वप्न लेकर शिक्षा क्षेत्र को जीवन साधना समझने वाले संघ ने एक जुलाई 1952 में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की थी। संघ की प्रेरणा से निष्ठावान आरएसए नेता कृष्ण चंद्र गांधी ने भाउराव देवरस और नाना जी देशमुख के साथ मिलकर इस पुनीत कार्य की शुरुआत की। राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में लगे लोगों ने नवोदित पीढ़ी को सुयोग्य शिक्षा और शिक्षा के साथ संस्कार देने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर की आधारशिला 1952 में गोरखपुर के पक्की बाग में पांच रुपये मासिक किराये के भवन में रखी थी। पक्की बाग में शिशु मंदिर की स्थापना प्रयोगवादी संघ के कार्यों का एक उदाहरण था। इसके बाद यूपी में धीरे-धीरे और सरस्वती शिशु मंदिर खुलते गए। हालांकि इससे पहले 1946 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता विद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। जिसकी स्थापना संघ प्रमुख एमएस गोलवलकर ने की थी। इन स्कूलों को चलाने के लिए 1958 में शिशु शिक्षा प्रबंध समिति का गठन हुआ। जब अन्य प्रदेशों में भी ऐसे स्कूल खुले तो उनमें भी समितियों का गठन हुआ। पंजाब एवं चंडीगढ़ में सर्वहितकारी शिक्षा समिति और हरियाणा में हिंदू शिक्षा समिति बनी। फिर इसे राष्ट्रीय स्वरूप देते हुए 1977 में विद्या भारती संस्था का गठन किया गया। इस परिकल्पना को पूरा करने का कार्य संघ के द्वितीय सरसंचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर श्री गुरु जी ने किया। उनका मानना था कि राष्ट्र के निर्माण में देश की सांस्कृतिक विरासत की अहम भूमिका होती है उनका विचार था कि बच्चे का संपूर्ण चारित्रिक विकास हो। इसके लिए 1950 में उत्तर प्रदेश में गुरु जी ने भावराव देवरस, नानाजी देशमुख, कृष्ण चंद गांधी से मिलकर चर्चा शुरू की थी। समय आगे बढ़ता गया। 1952 में कृष्ण चंद गांधी गोरखपुर आ गए और जून 1952 में विद्यालय शुरू करने का मन बनाया। फिर 1952 में गुरु पूर्णिमा के दिन सरस्वती शिशु मंदिर नाम से पहला शिशु मंदिर प्रारंभ कर दिया। जिसकी चर्चा देश में चारों तरफ होने लगी और सरस्वती शिशु मंदिरों का ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया।

विद्या भारती ने शिक्षा की चुनौती स्वीकारी

मुगल व अंग्रेजों के आधिपत्य के कारण भारतीय सांस्कृतिक परंपरा एवं संस्कार युक्त गुरुकुल शिक्षा छिन्न-भिन्न हो चुकी थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार ने ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली को पूरे तरीके से खारिज कर दिया था, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने स्कूली शिक्षा को केवल काले अंग्रेज पैदा करने की फैक्ट्री बना डाला था। लिहाजा ब्रिटिश काल में स्वदेश प्रेमियों के ध्यान में यह बात आ गई थी कि यह अंग्रेजी शिक्षा भारतीय नवयुवकों में भारतीयता के संस्कार मिटाकर उनमें अंग्रेजीयत भर रही है, जो आगे चलकर देश के लिए घातक सिद्ध होगी। इस अंग्रेजी शिक्षा के विरोध स्वरूप सबसे पहले रवींद्रनाथ ठाकुर के नाना राज बसु ने राष्ट्रीय शिक्षा का बीड़ा उठाया। उनके बाद महर्षि अरविंद, रवींद्र नाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता, स्वामी दयानंद सरस्वती, लाल-बाल-पाल तथा गांधीजी ने राष्ट्रीय शिक्षा की ज्योति को प्रज्जवलित रखा। स्वाधीनता के बाद सारा देश चाहता था कि अब देश स्वाधीन हो गया है, अंग्रेज चले गए हैं इसलिए अंग्रेजी शिक्षा को हटाकर पुनः भारतीय शिक्षा प्रतिष्ठित करनी चाहिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब एक पत्रकार ने विनोबा भावे से पूछा था कि स्वतंत्र भारत में आप कैसी शिक्षा चाहते हैं? विनोबा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, अब भारत में भारतीय शिक्षा लागू होनी चाहिए। भारतीय शिक्षा को लागू करने के लिए यदि 6 माह का समय लगे तो 6 महीने तक देश के सभी विद्यालय बंद कर देने चाहिए। जब 6 महीने बाद विद्यालय खुले तब उनमें भारतीय ज्ञान ही दिया जाए। किंतु उस समय के नेतृत्व ने विनोबा जी की बात नहीं मानी और वही अंग्रेजी शिक्षा चलने दी। इतना ही नहीं देश की शिक्षा उन लोगों के हाथों में सौंपी जो भारत विरोधी मानस के थे। तब संघ ने शिक्षा क्षेत्र में आना आवश्यक समझा। संघ ने विद्या भारती के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र का वरण तो कर लिया, किंतु उसने शिक्षा को ही क्यों चुना? यह जानना भी आवश्यक है। विद्या भारती ने देश के शिक्षा क्षेत्र की चुनौती को स्वीकार किया है और भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन कर उसका विकल्प विकसित करने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए विद्या भारती ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। उसने अपने लक्ष्य में जो-जो करना चाहती है, उसे स्पष्ट शब्दों में कहा है।

वट वृक्ष बना विद्या भारती

1977 के बाद विद्या भारती धीरे-धीरे पूरे देश में शिक्षा पर कार्य करने लगी। समाज के सहयोग से चलने वाले राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान बन गया। 2025 तक आते आते विद्या भारती ने इसे शैक्षणिक आंदोलन का रूप दे दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ बलिराम हेडगेवार द्वारा दिए गए शिक्षा के मूल मंत्र ने बट वृक्ष का रूप ले लिया, जो आज से गुणात्मक एवं संस्कृति की शिक्षा प्रदान करने का मजबूत आधार बन गया है। वर्तमान में विद्या भारती लक्षद्वीप और मिजोरम को छोड़कर संपूर्ण देश के 684 जिलों में 12,118 विद्यालय, 8000 से अधिक अनौपचारिक शिक्षा केंद्र संचालित कर रही है। जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। इन विद्यालयों में 35.33 लाख छात्र-छात्राएं शिक्षा ले रहे हैं इनमें 40 हजार मुस्लिम छात्र भी है। 1.53 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षा दे रहे हैं। इनमें से 49 शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान एवं महाविद्यालय हैं, 2353 माध्यमिक एवं 923 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 633 पूर्व प्राथमिक एवं 5312 प्राथमिक, 4164 उच्च प्राथमिक एवं 6127 एकल शिक्षक विद्यालय तथा 3679 संस्कार केंद्र हैं। आज नगरों और ग्रामों में वनवासी और पर्वतीय क्षेत्रों में झुग्गी-झोंपड़ियों में, शिशु वाटिकाएं, शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, सरस्वती विद्यालय, उच्चतर शिक्षा संस्थान, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र और शोध संस्थान हैं। इन सरस्वती मंदिरों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसके फलस्वरूप अभिभावकों के साथ तथा हिंदू समाज में निरंतर संपर्क बढ़ रहा है। हिंदू समाज के हर क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा है। वर्तमान में विद्या भारती भारत में सबसे बड़ा गैर सरकारी शिक्षा संगठन बन गया है। विद्या भारती में पूर्व छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके पोर्टल पर 10 लाख 30 हजार पूर्व छात्र-छात्राएं पंजीकृत है। ये 87 देशों में अपना योगदान दे रहे हैं। स्कूली शिक्षा से प्राप्त मूल्यों पर आधारित सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अपनी शिक्षा नीति को सबसे पहले बदलने वाला संस्थान भी विद्या भारती रहा है। 507 अटल टिंकरिंग लैब इन्हीं विद्यालयों में है जो कोडिंग के आधार पर शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं जिनका उद्देश्य नैतिक मानदंडों पर भारतीय दर्शन निर्धारित है।

विद्या भारती देश के 684 जिलों में 12,118 विद्यालय, 8000 अनौपचारिक शिक्षा केंद्र संचालित कर रही है, जिसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना है, इन विद्यालयों में 35.33 लाख छात्र-छात्राएं शिक्षा ले रहे हैं इनमें 40 हजार मुस्लिम छात्र है, 1.53 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षा दे रहे हैं।

लॉर्ड मैकाले ने स्कूली शिक्षा को केवल काले अंग्रेज पैदा करने की फैक्ट्री बना डाला था, लिहाजा ब्रिटिश काल में स्वदेश प्रेमियों के ध्यान में यह बात आई कि यह अंग्रेजी शिक्षा भारतीय नवयुवकों में भारतीयता के संस्कार मिटाकर उनमें अंग्रेजीयत भर रही है, जो आगे चलकर देश के लिए घातक सिद्ध होगी।

आईटीआई, जन शिक्षण संस्थान, स्किल व्यावसायिक शिक्षा केंद्र जनजातीय ग्रामीण शिक्षा में ग्रामीण रोजगार पैदा कर रहे हैं। कारगिल (लद्दाख) शिमला, मंडी (हिमाचल प्रदेश) किफिरे (नागालैंड) जैसे दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड में कहावत है जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे सरस्वती शिशु मंदिर की ज्योति। अनुसंधान केंद्र (गांधीधाम-गुजरात) जैसे भारतीय ज्ञान संस्कार परंपरा को शोध आधारित बना रही है शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मानक परिषद भोपाल कार्य कर रही है। छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए बौद्धिक प्रतियोगिताएं, खेलकूद, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत, सांस्कृतिक कला पर्व, वैदिक गणित एवं शिक्षा में नवाचार की भूमिका को आगे बढ़ा रहा है। शिक्षा के इस अभिनव प्रयोग में अभी तक की सूचना के आधार पर इस वर्ष संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 27 से अधिक छात्र छात्राएं चयनित हुए हैं। जिसमें प्रकाश यादव (प्रयागराज) विभोर सारस्वत (बुलंदशहर उत्तर प्रदेश) ऋषभ चौधरी (गरोठ मध्य प्रदेश) ने टॉप 50 में स्थान प्राप्त किया है यह मूल्य आधारित शिक्षा प्रमाणित करती है कि वैश्विक मानक से कई अधिक बेहतर परिणाम निकलते हैं, जो देश की संस्कृतिक व संस्कारों के चरित्र को जिंदा रखते हैं। विजन 2047 भी पंच परिवर्तन आधारित है। जिस आधार पर विद्या भारती अपने रोड मैप को विद्यालयों के आधार पर देश के समक्ष प्रस्तुत कर रही है।

विद्या भारती का लक्ष्य

विद्या भारती इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना चाहती है, जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत हो, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो तथा जो जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलता पूर्वक कर सके और उसका जीवन ग्रामों, वनों, गिरिकंदराओं एवं झुग्गी-झोपडियों में निवास करने वाले दीन-दुखी, अभावग्रस्त अपने बांधवों को सामाजिक कुरीतियों, शोषण एवं अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समरस, सुसंपन्न, एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए समर्पित हो। विद्या भारती का यह लक्ष्य अपने आप में इतना स्पष्ट एवं इतना सुविचारित है कि कुछ और कहना शेष नहीं रहता। लक्ष्य साफ-साफ बताता है कि हमारे देश में विदेशी नहीं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली हो, जिससे हिंदुत्वनिष्ठ युवा पीढ़ी निर्मित हो, जो राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित हो। इसी लक्ष्य की पूर्ति में विद्या भारती प्रयासरत है। विद्या भारती की मान्यता है कि केवल किताबी ज्ञान जानकारी बढ़ा सकता है, जीवन निर्माण नहीं कर सकता। इसी प्रकार पर्सनालिटी विकास से आकर्षक व्यक्तित्व बनाया जा सकता है, परंतु व्यक्तित्व की मूलभूत संभावनाओं का विकास नहीं हो सकता। विद्यार्थी को शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण कर अधिक अंक लाने के लिए नहीं दी जाती, वह तो जीवन की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हुए कुलदीपक बनाने के लिए समाजसेवी बनाने के लिए देशभक्त निर्माण करने के लिए तथा संपूर्ण मानवता के लिए जीवन खपाने के लिए दी जाती है। ऐसा जीवन केवल पुस्तकें पढ़ने से नहीं बनता बल्कि क्रिया, अनुभव, विचार, विवेक तथा दायित्व बोध आधारित शिक्षा देने से बनता है। यही भारतीय शिक्षा है, इसी शिक्षा से योग्य एवं निष्ठावान नागरिक का निर्माण होते हैं।

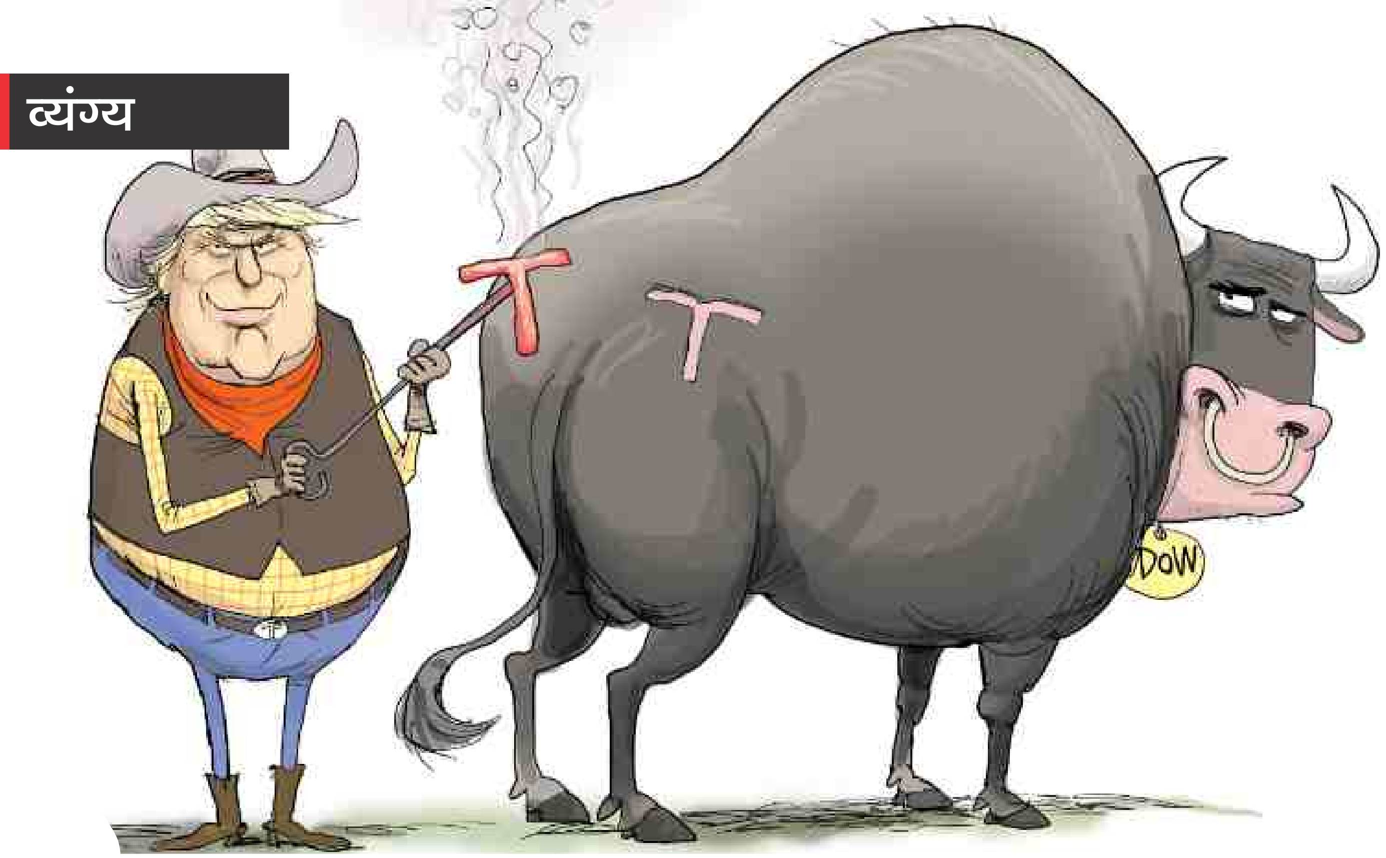

आ बैल मुझे मार है

जब पूरा विश्व कोरोना से त्राहि माम कर रहा था तब भारत के लोग 10 रुपये का बीड़ी का बंडल 100 में खरीद कर सुट्टा मार रहे थे, 10 की सिगरेट 50 में, 100 का हाफ 1000 में और 500 की बोतल 5000 रुपये में खरीदकर कोरोना को चैलेंज कर रहे थे, अब ऐसे लोगों के देश को टैरिफ की धमकी मत देना

प्रदीप डीएस भट्ट
व्यंग्यकार मेरठ

लो...हैलो...मिस्टर मोडी...मिस्टर मोडी हैलो..., आखिर थक हार कर ट्रंप ने अपने असिस्टेंट से कहा, माईकल जरा साइकिल लेकर भारत जा और मालूम करके बता कि मिस्टर मोडी हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे। माइकल के दिल में तो आया कि ट्रंप के कान के नीचे एक बजाए लेकिन कुछ सोचते हुए और दांत पिसते हुए बड़ी शालीनता से बोला वो मोदी है ना उसकी राशि वृश्चिक है। समझदार आदमी ऐसे लोगों से पंगा लेने से पहले पचास बार सोचता है, लेकिन आप हैं कि मोदी को मुनीर समझ रहे हैं। महाराज कोई बीच का रास्ता निकाल लो और मामला सुलटा लो वरना ये नया भारत है उल्टा करके टांग देगा और नीचे से मिर्च की धोकनी अलग से देगा...। शटअप माइकल हम सारी दुनिया के चौधरी हैं जाओ मिस्टर मोडी को बटाओ। अब माईकल का भी सब्र जबाव दे गया और एकदम फूटते हुआ बोला मैं 5 साल भारत में रहा हूं बेवड़े वहां कैसे-कैसे चौधरी हैं तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। सच बता रिया हूं तुम्हारे इन्हीं कुकर्मों की सजा सारा अमेरिका भुगत रहा है और तुम्हारी इज्जत तेजी से घट रही है। असल में मसला तब शुरू हुआ जब ट्रंप बाबू ने ये कहना शुरू किया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया। चलो जी कह दिया तो कह दिया हमने और मोदी जी ने सोचा चलो दोस्त है कोई बात नहीं। युद्ध हमने रोका या पाकिस्तान पैरों में नाक रगड़कर गिड़गिड़ाया वो तो हम ही जानते हैं और हमारे महादेव। लेकिन ये क्या जी मई से लेकर अगस्त तक ट्रंप बिगड़ैल बच्चे की तरह युद्ध मैंने रुकवाया...युद्ध मैंने रुकवाया...की रट लगाकर जमीन पे लोटपोट होकर अपने कपड़े फाड़ने लगे तो, भैय्या हमारे मोदी जी ने संसद में साफ-साफ कह दिया मित्रों युद्ध रुकवाने में किसी देश का कोई हाथ नहीं। ये सुनकर तो ट्रंप के तोते उड़ गए। बस भाई साहब उसने आनन फानन में भारत पर टैरिफ ठोक दिया। तीन दिन बाद एकस्ट्रा टैरिफ और ठोक दी। अब मोदी तो मोदी ठहरे टेंशन लेते ही नहीं वो तो टेंशन देने में यकीन रखते हैं, सो टैरिफ उनके ठेंगे पर। एक दिन बीता एक महीना बीत गया, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा...। और तो और अचानक भारत के रक्षा मंत्री ने अमेरिका की यात्रा स्थगित कर दी। हथियार खरीदने की डील को पॉज (किसी काम को रोकना) कर दिया, समझे नहीं, क्या वही जैसे ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है।

भैय्या हमारे मोदी जी ने संसद में साफ-साफ कह दिया मित्रों युद्ध रुकवाने में किसी देश का कोई हाथ नहीं, ये सुनकर तो ट्रंप के तोते उड़ गए, बस भाई साहब उसने आनन-फानन में भारत पर टैरिफ ठोक दिया, तीन दिन बाद एकस्ट्रा टैरिफ और ठोक दी।

बोखलाए ट्रंप दादा

अब भैय्या ट्रंप दादा व्हाइट हाऊस में बोखलाए से कभी बैडरूम में तो कभी छत पर घूम रहे कि ये क्या हुआ मोदी तो बिलकुल भी टेंशन नहीं ले रहा। क्या करें, क्या न करें की उधेड़बुन में जैसे तैसे नींद आई ही थी कि ट्रंप की मम्मी सपने में प्रकट हो गई, उन्हें देखते ही ट्रंप के मुंह से निकल गया माते इत्ते दिनों बाद अपने कुपुत्र की कैसे याद आ गई। मैरी माता बोली तू सुपुत्र नहीं कुपुत्र है तेरे जीवन का उद्धार करने के लिए ही मैंने नरेंद्र मोदी को तेरे मित्र माई फ्रेंड के रूप में चुना है, लेकिन तू तो निरा हक निकला। तू उसे ही चूना लगा रहा है। तूने अपने पहले टर्न में भले ही 30573 झूठ बोले हों किंतु तू मोदी के गुण गाता नहीं थकता था। पर सेकेंड टर्न के शुरू में उसके लिए 'कुर्सी आगे पीछे करने वाले' नामाकूल अब तू उसके साथ टैरिफ-टैरिफ खेल रहा है। याद रख वो गुज्जू है वो अपनी पे आया तो तेरी गजक बना के खा जाएगा और पानी भी नहीं पिएगा। शायद तूने उसे महात्मा गांधी का रिश्तेदार समझ लिया है जो दूसरा गाल आगे कर देगा। वो तेरा गाल तुझसे ही पकड़वा कर तेरे दूसरे हाथ से इत्ते थप्पड़ लगवाएगा कि तू बस इत्ता ही बोल पाएगा गलती से मिस्टेक हो गई दद्दू। सुनते-सुनते ट्रंप को अपनी मां मैरी में भारत माता दिखने लगीं। बड़े ही कातर नजर से अपनी मां को देखकर ट्रंप बोला तुम ही बताओ मैय्या, मैं क्या करुं। तो सुन कल मोदी को फोन कर माफी मांग ले और बताना मत भूलना कि ये सब करने के लिए मैंने कहा है वरना तू तो उसे चार बार हैलो कह चुका है और मोदी है कि चारों बार रिसीवर उल्टा करके रख देता है। उसे तेरी औकात पता है। एक काम कर पहले अजीत को फोन करना समझे, ट्रंप सर खुजाते हुए बोला कौन अजीत मां? मैरी नजर तिरछी करते हुए बोली अजीत जिसको कोई जीत न सके। मैं अजीत डोभाल की बात कर रही हूं, वो बहुत खतरनाक है, लेकिन जब हंसता है तो समझ में आ जाता है कि वो किसकी बत्ती गुल करके आया है। सुन तू मोदी को डायरेक्ट फोन मत करना अजीत के हाथ पैर जोड़ कर कुछ जुगाड़ लगा ले, वरना कहीं तूने पांचवी बार मोदी को सीधे फोन किया और गलती से मोदी ने रिसीवर उल्टे की जगह सीधा रक्खा तो वो सबसे पहले तुझे दौड़ाएगा फिर सोचेगा आगे बात करनी है या नहीं समझा। ट्रंप ने मां के पैर छुए तो मां खुश हो गई बोली चल तूने कुछ तो अच्छा सीखा मोदी से। अच्छा सुन मोदी भाई है इस बार माफी मिल जाए तो खुद को धन्य समझना।

गुजराती ब्याज सहित लौटाते हैं

गुजराती को गाली दो तो हंस कर लेता है, लेकिन समय आने पर ब्याज सहित लौटा भी देता है। चल अब चलती हूं। जैसे ही मैरी मां अपनी जगह से हिली तो देखा उनके पीछे से ट्रंप के पिताजी फ्रेड ट्रंप प्रकट हो गए। इससे पहले कि डोनाल्ड कुछ कहता फ्रेड ट्रंप बोले क्यूं मेरा नाम खराब करने पर तुला है। ट्रंप ने पिता से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की थी। लिहाजा अचानक ट्रंप को पिता के चेहरे में नाना पाटेकर की झलक दिखाई देने लगी। फ्रेड ट्रंप बोले अपनी मां का कहना मान और मोदी से सुलह कर ले वरना वो मोदी है डोनाल्ड-डोनाल्ड अलग और ट्रंप-ट्रंप अलग करके ही मानेगा और मिलेनिया से तेरा मिलन तो होगा लेकिन मिलेनियम वर्ष के बाद। मोदी को अंडर एस्टीमेट मत कर पगले कभी इस खाली खोपड़ी के जाले साफ करके सोच कि जो मोदी तेरे डिनर को ठुकरा सकता है वो ठुकाई भी तो कर सकता है। अगले दिन ट्रंप ने मोदी जी को सुबह-सुबह फोन खटका दिया राम...राम श्याम...श्याम के बाद...।

ट्रंप- हैलो...हैलो मिस्टर मोडी...मिस्टर मोडी मैं ट्रंप बोल रहा हूं। एक लम्बा पॉज लेने के बाद मोदी जी फिरकी लेते हुए बोले बोलो चौधरी साहब कैसे याद किया?

ट्रंप-ये तुम जवाब देने से पहले इतना लम्बा पॉज क्यों लेते जी मिस्टर मोडी...।

मोदी-ऑपरेशन सिंदूर में पॉज लेने के बाद मेरे कू पॉज लेने का आदत पड़ गई है बिड़ू। अभी जैसे सिंदूर का पॉज चल रहा है वैसे समझ लो...।

ट्रंप-ये तुम कैसे-कैसे वर्ड बोलते हो जी, मेरे पल्ले कुछ भी नई पड़ता मिस्टर मोडी। खैर मुझे कुछ पूछना है, पूछुं क्या?

याद रख मोदी गुज्जू है वो अपनी पे आया तो तेरी गजक बना के खा जाएगा और पानी भी नहीं पिएगा, तूने उसे महात्मा गांधी का रिश्तेदार समझ लिया है जो दूसरा गाल आगे कर देगा, वो तेरा गाल तुझसे ही पकड़वा कर तेरे दूसरे हाथ से इत्ते थप्पड़ लगवाएगा कि तू बस इत्ता ही बोल पाएगा गलती से मिस्टेक हो गई दद्दू।

मोदी-बिंदास होके पूछो चौधरी साहब, हम दोस्तों के दोस्त हैं, पर ये बात अलग है

कि तुम सिर्फ माया और काया के दोस्त हो बीड़ू।

ट्रंप-यार सात महीने हो गए राष्ट्रपति बने हुए, पहले सब सुन रहे थे, अब मेरी कोई नहीं सुनता। जिसे देखो बड़ी-बड़ी आंखें दिखाता है। बाकी को छोड़ों तुम भी तो मुझे इग्नोर मार रहे हो। मैं सच्चा वाला दोस्त हूं तुम्हारा भी और भारत का भी। हमने तुम्हारे कहने पर टीआरएस को आतंकवादी संगठन घोषित किया न।

मोदी-अच्छा फिर फर्जी फील्ड मार्शल मुनीर को लंच क्यूं दिया, बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी को आतंकवादी बताकर बैन क्यूं किया।

ट्रंप-देखो दोस्त एक हफ्ते से हमारा डॉगी खाना नहीं खा रहा था और मुनीर बिन बुलाए मेहमान की तरह आ टपका और लौटने का नाम ही नहीं ले रह था, तो हमने मुनीर को डॉगी के बचे हुए खाने में तड़का लगाकर परोस दिया वो खुश हो गया और मुझे शांति नोवेल अवार्ड दिलाने की चिट्ठी दे गया। खैर छोड़ों तुम एक बार कह देते जंग मैंने रुकवाई है तो मैं भारत पर टैरिफ जीरो पर्सेंट कर देता, बस इत्ती सी बात है। फिर मैं शांति का नोवेल अवार्ड पाने वाला पांचवां राष्ट्रपति बन जाता। दोस्त तुम माने नहीं और मुझे खुजली हो गई। देखो यार मैं अभी तक सात जंग रुकवा चुका हुं, रूस-यूक्रेन भी रुकवा दूंगा और इजरायल और हमास की भी। तुम ऐसा करो रूस से तेल व हथियार खरीदना बंद कर दो।

मोदी-देखो ट्रंप न तो मैं रूस से दोस्ती तोडूंगा न ही रूस से तेल और हथियार खरीदना बंद करूंगा। अमेरिका का इतिहास है उसने हर उस देश को खत्म करने की कोशिश की जिसने उसे चुनौती दी। जापान ने चुनौती दी, तुमने उसे नष्ट कर दिया। यूएसएसआर ने चुनौती दी, तुमने उसके 17 टुकड़े कर दिए, इराक ने सिर उठाया उसे नष्ट कर दिया। अब तुम इजरायल के साथ मिलकर ईरान के साथ भी ऐसा ही करना चाहते हो, लेकिन ईरान ने तुम्हारी पेंट ढीली कर रखी है। अब तुम चीन-रूस के साथ मिलकर भारत को भी लपेट रहे हो बस यहीं तुम गलती कर बैठे। तुमने मोदी, अम्बानी, अदाणी को चीन का जैक मा समझ लिया है क्या? जो विलुप्त हो जाएंगे ये तो मैंने रोका हुआ है वरना ये दोनों गुज्जू अपनी पे आ गए तो 'एक था ट्रंप' होने में देर नहीं लगेगी। तुम सुबह उठते ही आएं बाएं शाएं चालू हो जाते हो जरा फोर्ड की हालत तो देख लो, कित्ते घाटे में आ गई है और ये तो अभी शुरुआत है मियां। तुम चाहते हो सारे देश तुम्हारी चौधराहट कबूल करें, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हें रूस से दिक्कत नहीं है तुम चाहते हो भारत तुमसे तेल खरीदे ठीक है लाओ जिस रेट में रूस दे रहा है तुम आधे रेट में देने की बात करो तुम्हारे सारे तेल के कुएं हमारे। चलते-चलते और सुनो जो ट्रंप एलन मस्क का न हुआ वो और किसी का क्या होगा। ट्रंप ने कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला मोदी बोले आखिरी बात सुनो ट्रंप भारत के लोग अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सनकी भी है, उदाहरण देता हूं जब पूरा विश्व कोरोना से त्राहि माम कर रहा था तब भारत के लोग 10 रुपये का बीड़ी का बंडल 100 में खरीद कर सुट्टा मार रहे थे, 10 की सिगरेट 50 में, 100 का हाफ 1000 में और 500 की बोतल 5000 रुपये में खरीदकर कोरोना को चैलेंज कर रहे थे। अब ऐसे लोगों के देश को टैरिफ की धमकी मत देना और हां हमारे देश में एक और कहावत है 'चौबे जी छोबे जी बनने गए और दुबे जी बनकर लौटे' समझ जा वरना मैं असली चौधरी एक्सपोर्ट कर दूंगा वो तेरी सारी चौधराहट कहां से निकालेंगे तुम खुदई समझ लो।

एमपी के शिल्पकार डॉ.मोहन

मोहन यादव और उनकी सरकार का फोकस मध्य प्रदेश के सर्वांगीण पर है, वह मध्य प्रदेश के युवाओं की बेरोजगारी और उद्योगों की भारी कमी से भली भांति परिचित हैं इसलिए बेहतर प्रशासन और विकास के साथ पूरा ध्यान औद्योगिक विस्तार व रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने पर लगा रखा है।

आलोक एम इंदौरिया
स्तंभकार एवं लेखक

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस तरह से तिनका, तिनका जोड़कर नए मध्य प्रदेश की मूरत बना रहे हैं, उससे देश ही नहीं दुनिया के नक्शे पर मध्य प्रदेश की अपनी अलग पहचान बनेगी, नया मध्य प्रदेश निवेशकों को आकर्षित करेगा। जिससे प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ-साथ रोजगार के नए अवसरों को बेहद कुशलता से सृजित किया जा सकेगा। ये सब मोहन यादव शांत भाव से कर रहे हैं। यकीन मानिए मोहन यादव की मेहनत अगले 2 सालों के बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल देगी। बेशक सीएम मोहन यादव के विकास को लेकर चल रहे जबरदस्त संघर्ष के परिणाम तत्काल दिखाई न दे रहे हों, लेकिन 2 साल बाद जब इसके नतीजे सिलसिले वार आने शुरू होंगे तो मध्य प्रदेश की तस्वीर में कई नए रंग भरे हुए दिखाई देने लगेंगे। ये रंग रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि, दूध डेयरी, पशुपालन, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, वोकल फॉर लोकल व कृष्ण पाथेय सहित विकास के सभी आवश्यक क्षेत्रों के होंगे। यह सब मिलकर एक ऐसा गुलदस्ता तैयार करेंगे जो देश भर में मध्य प्रदेश की एक नई और अलग पहचान बनाने वाले साबित होंगे।

विजनरी है मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 19 माह पहले कमान संभालने वाले मोहन यादव बेशक पहले एक सामान्य मंत्री के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने कॉलेज की शिक्षा में जो आमूल चूल परिवर्तन किया वो आज मील का पत्थर साबित हो रहा है। मंत्री के रूप में उनका दीर्घकाल का अनुभव नहीं था, मगर मोहन यादव बेहद विजनरी यानी भविष्यदृष्टि संपन्न व्यक्ति हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। एक मुख्यमंत्री के रूप में जिसका कोई गुट या खेमा ना हो ऐसा व्यक्तित्व जब मुख्यमंत्री के सिंहासन पर बैठता है तो उसके सामने भीतर की चुनौती बहुत होती हैं। मोहन यादव के तारतम्य में यह इसलिए उद्धृत करना लाजमी है क्योंकि उनसे बेहद वरिष्ठ विधायकों को आज मोहन यादव के नेतृत्व में काम करना पड़ रहा है। मगर अपने कार्य, व्यवहार से मोहन यादव ने इन सभी वरिष्ठों को यह कभी जाहिर नहीं होने दिया कि वह एक मुख्यमंत्री है। डॉ मोहन यादव का व्यवहार सभी से न केवल अपनत्व से परिपूर्ण है बल्कि अहंकार से रहित है, इसमें दो मत नहीं है।

मोहन सरकार का ही कमाल है कि मध्य प्रदेश के निर्यात में 1 वर्ष में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी होकर अब यह निर्यात 66,218 करोड़ रुपये का हो गया है, यह चमत्कार नहीं तो और क्या है? आर्थिक विकास और निर्यात की बदौलत मध्य प्रदेश राष्ट्रीय रैंकिंग में 15 नंबर से 11वें नंबर पर पहुंच गया है।

मध्य प्रदेश की शानदार ब्रांडिंग

प्रदेश का राजकाज तो एक सिस्टम के तहत नियम और कायदे कानून से प्रशासनिक मशीनरी द्वारा मंत्री मंडल के नेतृत्व में चलता रहता है। लेकिन मोहन यादव और उनकी पूरी सरकार का फोकस मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास पर है। वह मध्य प्रदेश के युवाओं की बेरोजगारी और उद्योगों की भारी कमी से भली भांति परिचित हैं। लिहाजा उन्होंने बेहतर प्रशासन और विकास के साथ अपना पूरा ध्यान औद्योगिक विस्तार और रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने पर लगा रखा है। फोकस भी ऐसा किया की मात्र 19 महीने के छोटे से कार्यकाल में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरों का सृजन करके उन्होंने अपनी सफलता की एक नई इबारत लिख दी है। जो शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में एक नजीर बन गई है। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश जो देश के मध्य में स्थित है वो अब उद्योग, फार्मा, कृषि, रक्षा उपकरण निर्माण के साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और खनिज का भी हब बनता जा रहा है। यह सब ऐसे ही नहीं हुआ है बल्कि इसके लिए मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में निवेशकों आकर्षित किया है। निवेशकों को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए बाकायदा एक ऐसा अभियान चलाया जिसने मध्य प्रदेश के लिए आत्मनिर्भता के रास्ते खोल दिए। मुख्यमंत्री ने ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जिससे निवेशकों को सरकारी औपचारिकता पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इस इकोसिस्टम की मॉनिटरिंग खुद मोहन यादव कर रहे हैं। बीते डेढ़ साल में डॉ मोहन यादव ने देश के विभिन्न हिस्सों में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में न सिर्फ मध्य प्रदेश की शानदार ब्रांडिंग की है बल्कि प्रदेश की सभी खासियतों को बेहतर ढंग से पहुंचाया भी है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस

मोहन यादव सरकार का जो सबसे बड़ा कदम है वह यह कि अब मध्य प्रदेश से कृषि और खनिज जिसका वह सबसे बड़ा उत्पादक है, का कच्चा माल अब अकेला बाहर नहीं जाएगा बल्कि इनसे संबंधित प्रसंस्करण यूनिटों को मध्य प्रदेश के अगल-अलग क्षेत्रों में कृषि और खनिज की उपलब्धता के अनुसार लगाया जाएगा। इससे न केवल रोजगार के हजारों अवसर सृजित होंगे बल्कि कृषि के साथ खनिजों का भी उचित मूल्य उत्पादकों को मिलेगा। जिसका लाभ अंतिम छोर यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी बहुत असर कारक साबित होगा। प्रदेश की 70 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है। शायद यही कारण है कि मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के सभी संभागों में उद्योग समिटों को न केवल आयोजित किया बल्कि निवेशकों को इन सुदूर क्षेत्रों तक ले जाने में कामयाबी भी हासिल की। यह डॉ मोहन यादव का ही प्रयास रहा कि उन्होंने ने मध्य प्रदेश के ग्रामों का भोजन यानी मिलेट्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार और बाजार दिलाने के काम को बखूबी अंजाम तक पहुंचाया।

निवेश से रोजगार बढ़ा

मोहन सरकार के प्रयासों से 19 माह के कार्यकाल में 77 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण कर दिया गया। यह छोटी नहीं, एक बड़ी व उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसमें जहां लगभग 1,400 करोड़ रुपये का प्रदेश में निवेश हुआ तो वही लगभग 4,500 से 5,000 के बीच युवाओं को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार भी मिला है। खास बात यह है कि प्रदेश में अब तक डेढ़ सौ औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास भी संपन्न हो गया है। जिसमें करीब 7,400 करोड़ रुपये का निवेश होने के साथ ही 14,000 के करीब रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उम्मीद यह भी है कि जिस तरीके से एलओआई जारी हुए हैं। उसके अनुसार करीब 29,000 करोड़ रुपये का निवेश और 66,000 युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जो मोहन सरकार की बहुत बड़ी सफलता होगी। इसी तरह 909 खनिज ब्लॉकों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव भी मिले हैं। जो खनिज के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। इसी तरह जीआईएस और रीजनल समिट दोनों को मिलाकर मध्य प्रदेश में कुल डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आएगा। जिससे एक लाख पचास हजार से अधिक नए रोजगार भी उपलब्ध होंगे। यानी उद्योग,

- **मुख्यमंत्री ने ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जिससे निवेशकों को सरकारी औपचारिकता पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इस सिस्टम की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बीते डेढ़ साल में मोहन यादव ने देश और दुनिया में मध्यप्रदेश की शानदार ब्रांडिंग भी की है।**
- **समिट में उद्योगपतियों ने इस बात को स्वीकार किया कि जितनी तेजी से मध्य प्रदेश में हमारे सारे काम नौकरशाह और सरकारी तंत्र कर रहा है, अवर्णनीय है, निवेशकों का यह कथन मोहन सरकार की अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता और लगन को दर्शाने के लिए काफी है।**

खनिज, पर्यटन, कृषि और डेयरी समेत अब ऐसा कोई भी सेक्टर डॉ मोहन यादव सरकार ने नहीं छोड़ा जहां से रोजगार की उपलब्धि के साथ आय के नए साधन न सृजित हों। निश्चित रूप से यह मोहन सरकार की वह उपलब्धि है जो उसे विशिष्ट बनाती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने जीआईएस में उपस्थित होकर न केवल मोहन यादव के कामों पर मोहर लगाई बल्कि हौसला भी दिया कि मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को चमकाओ, केंद्र सरकार आपके साथ बराबर खड़ी हुई है। यह मोहन सरकार का ही कमाल है कि मध्य प्रदेश के निर्यात में 1 वर्ष में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी होकर अब यह निर्यात 66,218 करोड़ रुपये का हो गया है। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है? आर्थिक विकास और निर्यात की बदौलत मध्य प्रदेश राष्ट्रीय रैंकिंग में 15 नंबर से 11वें नंबर पर पहुंच गया है। इसे भी मोहन यादव सरकार की उपलब्धियां की फेहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। बरहाल मध्य प्रदेश केवल निवेशकों को ही आमंत्रित नहीं कर रहा बल्कि निवेशकों को वह सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है जो किसी उद्योग को लगाने और चलाने के लिए आवश्यक होती है। खुद समिट में उद्योगपतियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि जितनी तेजी से हमारे सारे काम नौकरशाह और सरकारी तंत्र कर रहा है, अवर्णनीय है। यह कथन मोहन सरकार की अपने काम के लिए प्रतिबद्धता और लगन को दर्शाने के लिए काफी है।

औद्योगिक प्रदेश बनेगा मध्य प्रदेश

डॉ मोहन यादव ने अपनी जिजीविषा और कड़ी मेहनत से प्रदेश को एक विकसित औद्योगिक प्रदेश बनाने के लिए दिन-रात एक कर दिया है। उद्योग लगने लगे हैं, कुछ निर्माणधीन है और कुछ लगने वाले हैं। मगर जिस दिन से यह सभी प्रोडक्शन में आ जाएंगे, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश का देश में क्या मुकाम होगा? कोई बड़ी बात नहीं कि आगामी 5 साल बाद मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे विकसित राज्य के समकक्ष आ जाए। बेशक डॉ. मोहन के प्रयासों का तत्काल लाभ नहीं मिलेगा और न अल्प समय में दिखेगा। मगर 2 साल के बाद उत्पादन की जब श्रृंखला बननी प्रारंभ होगी, रोजगार मिलने का लगातार सिलसिला शुरू होगा, शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के दरवाजे खुलेंगे, आप यकीन मानिए प्रदेश हवा से बातें करने लगेगा। बस जरूरत है धैर्य और सभी चीजों को लाइन अप होने की। इसके लिए आवश्यक है कि सरकारी मशीनरी अपना फर्ज और दायित्व सही तरीके से निभाए। यदि मोहन सरकार की मेहनत सफल हो गई, जो होगी ही, तो आप तय मानिए मोहन यादव का नाम मध्य प्रदेश के विकास पुरुष के रूप में न केवल जाना जाएगा बल्कि यह नजीर भी बन जाएगा। खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार और शाजापुर को मिलाकर एक नए मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। इसी तरह भोपाल, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, जबलपुर और ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

राधाकृष्णन बने उपराष्ट्रपति

विपक्षी प्रत्याशी को 300 वोट मिले जिसे कांग्रेस अपनी जीत के रूप में देख रही है, कांग्रेस कह रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के प्रत्याशी को 2022 के मुकाबले 300 वोट मिलना भी उसकी जीत है, वैसे ये सच है कि राधाकृष्णन ने भले ही बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन जगदीप धनखड़ के मुकाबले उन्हें 76 वोट कम मिले हैं।

उत्तरांचल दीप डेस्क

देश के उपराष्ट्रपति चुनाव के चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। एनडीए को उसकी ताकत से भी अधिक वोट मिले और सीपी राधाकृष्णन 452 वोट पाकर विजयी घोषित हुए हैं। जबकि इंडिया ब्लॉक को उसकी ताकत 315 की तुलना में 15 वोट कम यानी 300 वोट मिले। 15 वोट निरस्त हो गए। इसका मतलब साफ है कि विपक्ष के कई सांसदों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाला तो एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों के सांसदों के वोट निरस्त भी हुए। किंतु शर्मनाक हार के बाद भी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 99 सीटें हासिल कर जैसे जीत का जश्न मना रही थी वैसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में हार को भी अपनी जीत बता रही है। ये कांग्रेस की दृढ़शक्ति ही है कि वो हार कर भी निराश नहीं होती। सीपी राधाकृष्ण ने 15 वें उपराष्ट्रपति की शपथ ले ली। शपथ ग्रहण में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गैरहाजिरी और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हाजिरी सुर्खियों में रही। अब उपराष्ट्रपति चुनाव में संख्याबल को भी समझ लेते हैं-लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को मिलाकर कुल 788 मतदाता हैं। फिलहाल लोकसभा में एक और राज्यसभा में छह सीट रिक्त हैं, इस तरह उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं की संख्या 781 थी। इनमें से 767 सांसदों ने वोट डाले, जिनमें से 752 वोट वैध और 15 वोट निरस्त पाए गए। वोटों की गिनती होने पर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले? जबकि संख्या बल के हिसाब से एनडीए के पास 427 और इंडिया ब्लॉक के 315 वोटर हैं। इसके अलावा 39 वोटर पर किसी गठबंधन का कोई दावा नहीं है। यानी ये 39 वोटर निष्पक्ष हैं। इनमें से वायएसआरसीपी के 11 सांसदों ने एनडीए का समर्थन किया। लिहाजा एनडीए की संख्या बढ़कर 438 हो गई और निष्पक्षों की संख्या घटकर 28 रह गई। इन 28 में से बीजेडी के सात, बीआरएस के चार, अकाली दल के एक और दो निर्दलीय सरबजीत सिंह खालसा और अमृतपाल ने गैरहाजिर रहने का फैसला किया। यानी 14 वोट गैरहाजिर रहे। अब निष्पक्ष सांसदों की संख्या सिर्फ 14 रह गई। एनडीए को वायएसआरसीपी के सांसदों को मिलाकर एनडीए प्रत्याशी को 438 वोट मिलने चाहिए थे, जबकि उसे 452 वोट मिले। यानी एनडीए प्रत्याशी को 14 अतिरिक्त वोट मिले। संभावना है कि 14 निष्पक्ष वोटों में से भी कुछ वोट मिले। इससे माना जा रहा है क्रॉस वोटिंग के कारण ही एनडीए प्रत्याशी के वोटों की संख्या 452 तक पहुंची। इंडिया ब्लॉक के किन दलों के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, इसकी जानकारी मिलने में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन संभावना ये है कि विपक्ष के दस सांसदों ने एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की और इंडिया ब्लॉक को 15 वोटों का नुकसान हुआ। इनमें पांच निरस्त वोट और दस क्रॉस वोटिंग को मिला दें तो यह हिसाब पूरा हो जाता है।

राहुल गांधी से उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर सवाल किया तो वो सिर्फ 'वोट चोर गद्दी छोड़' कहकर निकल गए, इससे हर किसी के जहन में सवाल आएगा कि क्या राहुल गांधी 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे में अपना भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि 'चौकीदार चोर' का नारा देकर 2019 का नतीजा देख चुके हैं।

गठबंधन के नाम पर कांग्रेस बोझ बनी

उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी सपा के अखिलेश यादव, राजद के लालू यादव, टीएमसी की ममता बनर्जी, सहित शिवसेना, एनसीपी आदि अधिकांश क्षेत्रीय दल चाहते थे कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जीतने के लिए उनके पास सांसदों का पर्याप्त संख्याबल नहीं है, लिहाजा विपक्ष को उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए। इसके पीछे कांग्रेस को छोड़कर बाकी इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का तर्क था कि उपराष्ट्रपति चुनाव में हार निश्चित है और इस हार का बिहार विधानसभा चुनाव में गलत संदेश जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने किसी की नहीं सुनी और मनमानी कर बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव में अपना प्रत्याशी बना दिया। ऐसा ही व्यवहार कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में भी किया था। विपक्षी जानते थे कि राष्ट्रपति चुनाव में हार मिलेगी लिहाजा द्रोपदी मुर्मू के मुकाबले प्रत्याशी न उतारा जाए, लेकिन कांग्रेस अड़ गई और यशवंत सिन्हा को अपना प्रत्याशी बना दिया था। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में जैसा विपक्ष को पहले से ही पता था कि उनका प्रत्याशी हारेगा वैसा ही हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 2161 वोट मिले थे जबकि उनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को 1058 वोट मिले। यानी यशवंत सिन्हा 1103 वोट से हार गए थे। कांग्रेस के जिद्दीपन से इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद असहज हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्षेत्रीय दलों की ऐसी क्या विवशता है कि वो इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस का बोझ उठाए घूम रहे हैं?

हार में भी जीत देखती है कांग्रेस

उपराष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान और व्हिप जारी न होने के कारण कई सांसदों को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट देने का मौका मिल जाता है। चूंकि व्हिप नहीं होता तो क्रॉस वोटिंग करने वाले सांसदों के खिलाफ राजनीतिक पार्टियां कार्रवाई भी नहीं कर सकतीं। अलबत्ता यह जरूर है कि इससे आने वाले दिनों के लिए नए राजनीतिक समीकरण जरूर बनते हैं, जिसमें मौजूदा गठबंधनों के टूटने और नए गठबंधनों के बनने की संभावना बढ़ जाती है।

उपराष्ट्रपति चुनाव में एक खास बात ये देखी गई कि विपक्ष शुरुआत से लेकर अंत तक एकजुटता का दावा करता रहा, मगर 15 विपक्षी सांसदों के वोट कहां गए इसका जवाब खुद कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के पास भी नहीं है? चुनाव परिणाम से ठीक पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर दावा किया था कि विपक्षी सांसद एकजुट हैं और सभी 315 सांसदों ने वोट किया है, हालांकि जब परिणाम आए तो जयराम रमेश के दावे की हवा निकल गई। क्योंकि विपक्षी उम्मीदवार को महज 300 वोट मिले थे। अब कांग्रेस ने इसमें भी अपनी जीत तलाश ली है। कांग्रेस कह रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को 2022 के मुकाबले 300 वोट मिलना भी उसकी जीत है। वैसे ये सच है कि राधाकृष्णन भले ही एनडीए की ताकत से ज्यादा बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ के मुकाबले उन्हें 76 वोट कम मिले हैं। यानी राधाकृष्णन को वैध मतों का 60 फीसदी वोट मिला है, जबकि जगदीप धनखड़ को 2022 के चुनाव में कुल वैध मतों का 74.36 फीसदी वोट मिला था। इस तरह धनखड़ से राधाकृष्णन को 14 फीसदी कम वोट मिले हैं। धनखड़ की जीत का अंतर 346 वोटों का था जबकि राधाकृष्णन की जीत का अंतर 152 वोटों का है। यह अंतर 2024 के लोकसभा चुनाव से सांसदों का गणित बदलने की वजह से हुआ है। इसके अलावा इस बार विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा एकजुट रहा। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की होगी। क्योंकि सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र और झारखंड में राज्यपाल रह चुके हैं। लिहाजा इन दोनों राज्यों के विपक्षी दलों के नेताओं ने क्रॉस वोटिंग कर सीपी राधाकृष्णन की जीत पक्की की। उपराष्ट्रपति चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा है कि सत्ताधारी दल सांसद छीन सकता है, लेकिन जनता को नहीं छीन सकता। उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को चुनाव में जीत पर बधाई दी है और आशा जताई है कि वे निष्पक्ष होकर काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि मतगणना से यह साफ है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। क्रॉस वोट करने वालों के अपने हित या निजी प्रभाव रहे होंगे। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग से भाजपा गदगद है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा इसे कांग्रेस गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना रही है। वैसे भी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद इस चुनाव को विपक्षी एकजुटता की परीक्षा माना जा रहा था, कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को जीत के लिए 392 वोटों की आवश्यकता थी, जबकि उसके पास पक्के वोटों की संख्या 315 थी, यानी कांग्रेस सहित पूरे इंडिया गठबंधन को पहले से ही पता था कि जीत तो एनडीए उम्मीदवार की ही होगी, फिर भी कांग्रेस की ओर से एकजुटता दिखाने के लिए ही रेड्डी को मैदान में उतारा गया था। लेकिन 15 सांसदों की क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर पानी फिर गया।

- **उपराष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान और व्हिप जारी न होने के कारण कई सांसदों को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट देने का मौका मिल जाता है, चूंकि व्हिप नहीं होता तो क्रॉस वोटिंग करने वाले सांसदों के खिलाफ राजनीतिक पार्टियां कार्रवाई भी नहीं कर सकतीं।**
- **उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी सपा के अखिलेश यादव, राजद के लालू यादव, टीएमसी की ममता बनर्जी, सहित शिवसेना, एनसीपी आदि अधिकांश क्षेत्रीय दल चाहते थे कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का प्रत्याशी न उतारा जाए क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्याबल नहीं है।**

उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन की एकजुटता तार-तार हुई तो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर तंज कस दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा-मिले तो 300 ही, 15 लोग कौन से भागकर हमको यानी एनडीए प्रत्याशी को वोट दे गए? भाई आपके तो जनता के साथ नेता भी भाग गए। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा- वैसे राहुल गांधी उपराष्ट्रपति का चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से ही हुआ। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया गठबंधन की हार पर निशाना साधते हुए 'वोट चोरी' के आरोपों को काल्पनिक और वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित बताया। हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि कुछ राजनेता, जो बालक बुद्धि से प्रेरित हैं, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर तर्कहीनता और झूठे आंकड़ों के आधार पर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। पुरी ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष एक दिन मतपत्र की वकालत करता है, लेकिन जब मतपत्र आधारित उपराष्ट्रपति चुनाव में उनके 15 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया, तो वे इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसके विपरीत जब मीडिया ने राहुल गांधी से उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को लेकर सवाल किया तो वो सिर्फ 'वोट चोर गद्दी छोड़' कहकर निकल गए। इससे हर किसी के जहन में सवाल आएगा कि क्या राहुल गांधी 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे में अपना भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि 'चौकीदार चोर' का नारा देकर 2019 के नतीजे उनके सामने आ चुके हैं। कहने का मतलब है कि राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी को भले ही वोट चोर कहें, लेकिन देश जानता है कि चोर कौन है। चोरी के आरोपों में कौन फंसा है। खुद राहुल गांधी एक नहीं 10 मामलों में कोर्ट से जमानत पर हैं। उनकी मां सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं। ऐसे में राहुल गांधी का वोट छोड़ गद्दी छोड़ नारे का असर क्या बेअसर नहीं हो जाता। फिर सोशल मीडिया पर इसके जवाब में नेशनल हेराल्ड चोर देश छोड़ के नारे भी बुलंद हो रहे हैं।

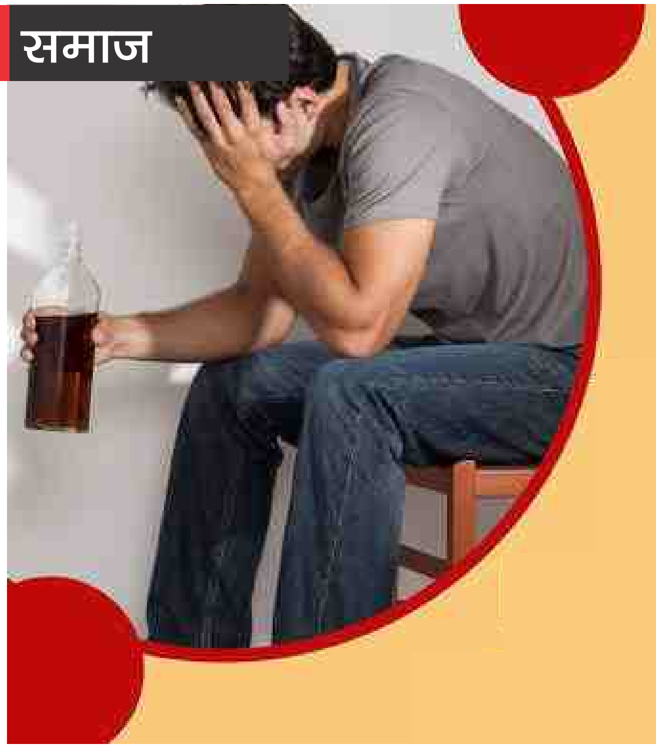

युवाओं में नशे की लत और अपराध

सिनेमा, टीवी व डिजिटल माध्यमों पर नायक अक्सर परेशानी के समय नशे का सेवन करते हुए दिखाए जाते है, यदि इसके बदले उन्हें योग और ध्यान करते दिखाया जाए तो एक सकारात्मक प्रभाव युवा पीढ़ी पर होगा, परंतु इन माध्यमों से जुड़े अधिकतर लोग खुद ही नशे के आदी होते हैं, इसलिए वही दिखाते हैं जो अपनाते हैं।

अर्चना त्यागी
रुड़की, हरिद्वार

सदाबहार गायक दिलकश अवाज के मालिक मुकेश कुमार का यह गीत 1959 में आई फिल्म 'मैं नशे में हूं' का है 'मुझको यारों माफ करना मैं नशे में हूं...' ऐसे फिल्म शराबी का गीत 'लोग कहते हैं मैं शराबी हूं, तुमने भी शायद यही सोच लिया...।' जैसे एक नहीं अनेकों गीत फिल्म इंडस्ट्री में गुनगुनाए गए हैं। शायरों ने भी शराब को लेकर तमाम शेर लिखे हैं, इनमें एक चर्चित शेर है 'अब तो उतनी भी मयस्सर नहीं मय-खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में...।' गाहे बगाहे ये गीत और शेर पढ़ने व सुनने को मिल ही जाते हैं। शराबी कहो या नशेड़ी उसे सिर्फ पीने का बहाना चाहिए। यानी गम दूर करने की दवा नशे में है। तो कोई खुशी का इजहार करने के लिए पीता है। यानी नशा युवाओं की जिंदगी का पर्याय बन गया है। किसी को जीने का नशा है तो किसी को मरने का। कोई जीने के लिए नशा करता है तो कोई मरने के लिए। हर शख्स नशे की गिरफ्त में है। युवाओं को तो इस व्यसन ने अपना दास बना लिया है। सिगरेट, शराब, ड्रग्स के अलावा भी कई तरह के नशे युवा पीढ़ी आंखें बंद करके अपना रही है। यही नहीं अब तो हालात ये हैं कि किशोरावस्था में ही आज की पीढ़ी नशे के आगोश में जा रही है। नशे की जरूरत पूरी करने के लिए नए भारत की पीढ़ी अपराध की दलदल में भी धंसती जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि प्रत्येक नशेड़ी युवा अपराधी है। परंतु नशे में होने के कारण मानसिक अस्थिरता बढ़ती है। सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती चली जाती है और सही गलत का फर्क मालूम ही नहीं चलता है। नशा ही मानसिक रूप से हर किसी को उत्तेजित करता है। जब एक बार अपराध होने पर नशे में होने का बहाना बनाया जाता है तब फिर यही बहाना अपराध करने की आदत बन जाता है। संपन्न परिवारों के बच्चों या फिर रईसजादों पर युवावस्था में कोई दबाव नहीं होता है। उनका सुनहरा भविष्य उनकी पारिवारिक विरासत पहले ही लिख चुकी होती है। मां-बाप ही बच्चों को भरपूर आजादी देते हैं। उनका मानना है कि युवावस्था, जीवन का आनंद लेने के लिए ही होती है। इसी सोच के चलते यदि उनके नौनिहाल नशा और कोई अपराध भी करते हैं तो वे पैसे की ताकत और उच्च पदाधिकारियों से संबंधों के चलते सजा से बच जाते हैं।

एक क्रांति देश की आजादी के लिए थी, लेकिन अब एक और क्रांति की आवश्यक महसूस हो रही है, यह क्रांति सिर्फ अपने देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को नशामुक्त करने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि बुराई, अच्छाई की तुलना में तेजी से फैलती है, प्रयास होना चाहिए कि विश्व में एक भी व्यक्ति नशा न करे।

कितना घातक हो सकता है नशा

पिछले साल जुलाई में मुंबई के वर्ली इलाके में एक राजनेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह ने शराब के नशे में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से स्कूटरी सवार दंपति को कुचल दिया था। इस दुर्घटना में महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस दुर्घटना के बाद रियल एस्टेट कारोबारी राजनेता राजेश शाह ने अपने बेटे को बचाने के लिए कई दाव चले और आखिर बेटे को बचा ही लिया। इस घटना का उल्लेख करने के पीछ मेरा मकसद ये बताना है कि अपराध के बाद माता-पिता अपने बिगड़े हुए बच्चों की पैरवी किस हद तक जाकर करते हैं। राजेश शाह को महिला की मौत का शायद अफसोस नहीं होगा, उसे चिंता सिर्फ इस बात की थी कहीं बेटे को जेल न जाना पड़ जाए। एक और भयावह घटना का उल्लेख करना भी आवश्यक है, यह घटना उत्तराखंड की है जहां नशे के जाल में फंसी युवती पहले खुद एचआईवी संक्रमित हुई और फिर नशे के लिए एचआईवी संक्रमित युवती जिश्मफरोशी करने लगी। उसके संपर्क में आने वाले कई युवा एचआईवी संक्रमित हो गए। यह राज तब खुला था जब उसके संपर्क में आया एक युवक बीमार हुआ और जांच में वह एचआईवी संक्रमित पाया गया।

सीरियल व फिल्मों का प्रभाव

हमारी भारतीय संस्कृति जिसमें मद्य पान राक्षसों का व्यसन था अब विस्मृत हो चुकी है। एक दूसरे की देखा देखी नशे की लत बढ़ती चली जा रही है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र किसी न किसी नशे की गिरफ्त में पड़ ही जाते हैं। कोई भी मां-बाप नशे के लिए शायद पैसे नहीं देता इसलिए युवा चोरी करने लगते हैं, राह चलते लोगों से मोबाइल छीनने से लेकर महिलाओं के गले से सोने की चेन खींच लेने जैसे अपराध को अपराध नहीं मानते। चूंकि सब कुछ नशे के लिए करना होता है इसलिए अपराध करने में उन्हें कोई बुराई नहीं नजर आती। सामाजिक अराजकता फैलाने वाले तत्व ऐसे ही नशेड़ी और भटके हुए युवाओं को बरगला कर अपना उल्लू सीधा करते हैं और समाज में हिंसा फैलाने में कामयाब होते हैं। अराजकता फैलाने वोल तत्व किशोरों को नशे की लत लगाकर अपराध करा रहे हैं। कुछ सिंडीकेट ऐसे भी हैं जो पहले नशे की लत लगाते हैं फिर नशे की पूर्ति के लिए किशोरों और युवाओं से अपराध कराते हैं। नशे की लत को बढ़ावा देने में सिनेमा, टीवी और दूसरे डिजिटल माध्यमों का भी कम योगदान नहीं है। नायक अक्सर परेशानी के समय नशे का सेवन करते हुए दिखाया जाता है। उसके बदले यदि उसे योग और ध्यान का सहारा लेते हुए दिखाया जाए तो एक सकारात्मक प्रभाव युवा पीढ़ी पर होगा। परंतु इन माध्यमों से जुड़े अधिकतर लोग खुद ही नशे के आदी होते हैं। इसलिए वही दिखाते हैं जो अपनाते हैं।

कम खतरनाक नहीं है मोबाइल का नशा

एक नशा ये है जो शराब, चरस, स्मैक, नशीले इंजेक्शन, नशीली दवाओं से किया जाता है इसके अलावा एक नशा और भी है जिसे इस लेख में शामिल करना मैं जरूरी समझती हूं, ये मोबाइल का नशा है। सोशल मीडिया का नशा। मोबाइल पर उपलब्ध सस्ते इंटरनेट के माध्यम से युवा वह सभी कुछ देखते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। बहुत से युवा खुद स्वीकार करते हैं कि मोबाइल पर अथवा टीवी पर या किसी फिल्म को देखकर उन्हें नशे की ओर जाने की प्रेरणा मिली। नशा करके अपराध करने की शक्ति मिलती है। सोशल मीडिया के नशे ने कितने युवाओं को अवसाद में धकेल दिया है। यहां तक कि युवा लाइक, फॉलोअर और पोस्ट रीच कम होने या ट्रॉल होने पर आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं, कि नशा एक राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। इससे होने वाले शारीरिक व मानसिक पतन के कारण देश की धरोहर और संस्कृति को बचाए रखना एक चुनौती बन गया है। नशे में डूबे हुए लोग अमूममन उचित निर्णय लेने की ताकत गंवा देते हैं। इसलिए उन लोगों का दायित्व बढ़ जाता है जो स्वयं नशा नहीं करते हैं। उन्हें ही ऐसे रास्ते निकलने हैं जिन्हें दिखाकर नशे से युवा व किशोर पीढ़ी को बचाया जा सके। विद्यालयों के आस पास नशे का बाजार चलाने वालों पर निगरानी और कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। नशे की लत की शुरुआत इसी उम्र में होती है। इस उम्र में जिंदगी केवल लुत्फ का पर्याय लगती है। 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' जैसे फलसफे खूब आकर्षित करते हैं। नशे की लत यदि किसी युवा को लग भी जाए तो मां-बाप और दोस्तों को चाहिए कि उसको अनदेखा करने के बजाय उससे खुलकर बात करें। उसकी उस समस्या दूर करने की कोशिश की जाए, जिसके लिए वह खुद को मिटाने के लिए तैयार हुआ है। क्योंकि नशा एक धीमा जहर है जो शरीर को खोखला करके एक दिन मृत्यु के दरवाजे को फटाक से खोल देता है। कितनी सड़क दुर्घटनाएं नशे की हालत में वाहन चलाने के कारण ही घटती ये एक जीता जागता सबूत है।

वैदिक जीवन पद्धति में बड़ी ताकत

एक क्रांति देश की आजादी के लिए थी, लेकिन इस समय फिर से एक क्रांति की आवश्यक महसूस हो रही है। यह क्रांति सिर्फ अपने देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को नशामुक्त करने के लिए होनी चाहिए। बुराई, अच्छाई की तुलना में बहुत तेज गति से फैलती है। इसलिए प्रयास यही होना चाहिए कि विश्व में एक भी व्यक्ति नशा नहीं करे। कई लोग मानसिक तनाव के कारण भी नशे को विकल्प के रूप में चुन लेते हैं। खुलकर बात करना और अनावश्यक रीतियों को तोड़ना भी नशे से बचाव की ओर एक सार्थक कदम है। युवाओं के ऊपर पढ़ाई, करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वाह का दबाव अधिक होता है। बहुत बार यह दबाव नहीं झेल पाने के कारण खुद को नशे के हवाले कर देते हैं। ताकि कुछ पलों के लिए सुकून मिल सके। लेकिन क्या नशा दबाव से बाहर आने का सही विकल्प है? मेरी राय में नशे से बेहतर विकल्प मेहनत और अपने कार्य के प्रति समर्पण है। इसके लिए आवश्यकता है एक सकारात्मक वातावरण तैयार करने की। जरूरत है, अध्यात्म को जीवन में समाहित करने की। प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति को अपनाने की। जो लोग नशे की लत से बचे हुए हैं, उनके द्वारा अपने जीवन मंत्र साझा करने की, जिससे सबको प्रेरणा मिल सके। अत्यंत आवश्यक है मंत्रोच्चार की महिमा प्रचारित करने की। वेदों के मंत्र मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। गीता और रामायण जैसे ग्रंथ जीने की कला सिखाते हैं। हम इन्हें पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे तभी सोच सही होगी। समझ विकसित होगी और हम इस मंत्र को चरितार्थ कर पाएंगे।

'सर्वे भवंतु सुखिन।
सर्वे संतु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यंतु।
मा कश्चिद दुख भाग भवेत।'

- **ऐसा नहीं है कि प्रत्येक नशेड़ी युवा अपराधी है, परंतु नशे में होने के कारण मानसिक अस्थिरता बढ़ती है, सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती चली जाती है और सही गलत का फर्क मालूम ही नहीं चलता है, नशा ही मानसिक रूप से हर किसी को उत्तेजित करता है।**
- **एक नशा शराब, चरस, स्मैक, नशीले इंजेक्शन, नशीली दवाओं से किया जाता है इसके अलावा एक नशा मोबाइल का, सोशल मीडिया का है, मोबाइल पर उपलब्ध सस्ते इंटरनेट के माध्यम से युवा वह सभी कुछ देखते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए।**
- **सोशल मीडिया के नशे ने कितने युवाओं को अवसाद में धकेल दिया है, युवा लाइक, फॉलोअर और पोस्ट रीच कम होने या ट्रॉल होने पर आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं, यानी नशा एक राष्ट्रीय समस्या बन चुका है, इससे होने वाले शारीरिक व मानसिक पतन के कारण देश की संस्कृति को बचाए रखना एक चुनौती बन गया है।**

कल्प केदार ने फिर समाधि ली

कल्प केदार भू समाधि ले चुके हैं, ग्रामीणों का कहना है कि वो कल्प केदार को मलबे से बाहर निकालेंगे और पहले की तरह से फिर पूजा करेंगे, कल्प केदार तो पहले भी आधे धरती के अंदर ही थे फिर भी श्रद्धालु पूजा करते थे, हर कोई चाहता है कि इस मंदिर को फिर से अस्तित्व मिले, ताकि श्रद्धालु इसके दर्शन कर सकें।

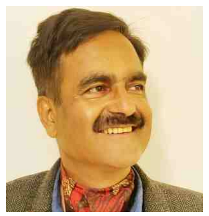

कमल कपूर
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त में आई भयानक प्रलयकाली बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस प्रलयकारी बाढ़ के लिए पहले बादल फटना बताया गया तो बाद में ग्लेशियर पिघलने और झील फटने को बाढ़ की वजह बताया गया। खीग गंगा नदी में आई तबाही ने आधा गांव कब्रिस्तान बना दिया। आधा गांव करीब 20 फीट मलबे के नीचे दब गए। खीर गंगा नदी में आई विनाशकारी बाढ़ से धराली का प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर कल्प केदार भी मलबे में दब गया। यह मंदिर 1945 में जमीन के नीचे से ही खोज कर निकाला गया था। मान्यता है कि यह मंदिर किसी आपदा के कारण पहले भी भूसमाधि ले चुका था। धराली में 1945 में की गई खुदाई के बाद कल्प केदार मंदिर के बारे में पता चला था। तब कई फीट खुदाई करने के बाद जमीन के नीचे यह प्राचीन शिव मंदिर मिला था जिसकी बनावट और शैली केदारनाथ मंदिर के जैसी थी। कत्युर शैली में निर्मित इस शिव मंदिर की वास्तुकला भी केदारनाथ धाम की तरह थी। खुदाई के बाद भी इस मंदिर का एक बड़ा हिस्सा जमीन में कई फीट नीचे था। श्रद्धालुओं को पूजा करने के लिए मंदिर में सीढियों से नीचे जाना पड़ता था। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर खीर गंगा का पानी हमेशा आता रहा है। पानी के लिए रास्ता भी बनाया गया था। क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी का कहना है कि कल्प केदार मंदिर और आसपास जो अवशेष मिले थे वह 17वीं सदी के थे। ये ऐतिहासिक मंदिर पुरातत्व विभाग की सूची में शामिल है। इसका गर्भगृह मंदिर के प्रवेश द्वार से करीब सात मीटर नीचे था। मंदिर के चारों तरफ नक्काशियां थी। मंदिर में शिव की प्रतिमा के साथ नंदी, शेर आदि की प्रतिमाएं भी स्थापित थी। स्थानीय लोगों में इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। गंगोत्री धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री भी इस मंदिर में दर्शन के लिए आते थे। लेकिन अब कल्प केदार मलबे में समाधि ले चुके है। 5 अगस्त की दोपहर तक जहां कल्प केदार मंदिर था वहां अब बड़े-बड़े पत्थरों का ढेर है और मंदिर लुप्त हो चुका है।

हिमालयी सभ्यता के प्रमाण

खीर गंगा नदी में आए विनाशकारी सैलाब ने प्राचीन शिव मंदिर को एक बार फिर से धरती के भीतर धकेल दिया है। अब श्रद्धालु और स्थानीय लोग सबसे अधिक इस बात से व्यथित हैं कि कल्प केदार मंदिर, जो वर्षों की खुदाई के बाद पुनः प्रकट हुआ था, उसने अब फिर से मिट्टी में समाधि क्यों ले ली है? श्रद्धालुओं के लिए कल्प केदारमंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह हिमालयी सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक साक्ष्य था। इसकी दीवारों पर की गई पत्थर की नक्काशी, जल प्रबंधन की प्रणाली, और गहराई में बने गर्भगृह जैसे कई साक्ष्य भारतीय स्थापत्य कला की उत्कृष्टता को दर्शाते थे। मंदिर का दोबारा मलबे में समा जाना, एक बार फिर यह सोचने को मजबूर करता है कि प्राकृतिक आपदाएं केवल वर्तमान को नहीं, हमारे इतिहास और धरोहरों को भी लील सकती हैं। उत्तरकाशी की यह त्रासदी केवल एक भौगोलिक घटना नहीं, बल्कि संस्कृति और आस्था पर प्रहार है।

क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी का कहना है कि कल्प केदार मंदिर और आसपास जो अवशेष मिले थे वह 17वीं सदी के थे, ये ऐतिहासिक कल्प केदार मंदिर पुरातत्व विभाग की सूची में शामिल है, इसका गर्भगृह मंदिर के प्रवेश द्वार से करीब सात मीटर नीचे था।

कल्प केदार मंदिर का इतिहास

कल्प केदार मंदिर और केदारनाथ धाम के बीच एक खास संबंध है, मुख्य रूप से दोनों मंदिर कत्यूरी शैली में बने हैं और उनका गर्भगृह (जहां शिवलिंग स्थापित है) की वास्तुकला एक जैसी है, जिसमें नंदी की पीठ के आकार के शिवलिंग हैं। कल्प केदार मंदिर को छोटा केदारनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि यह केदारनाथ धाम के समान ही है। यह मंदिर भी केदारनाथ धाम की तरह ही जमीन के नीचे स्थित था। और पूजा के लिए सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता था। यह भी माना जाता है कि कल्प केदार मंदिर का नाम कल्प यानी (पुराना या प्राचीन) और केदार (केदारनाथ) शब्दों से मिलकर बना है। अर्थात पुराना या प्राचीन केदारनाथ। कुल मिलाकर कल्प केदार मंदिर, केदारनाथ धाम का ही एक छोटा रूप माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित मंदिर कल्प केदार का अपना अलग इतिहास है। गंगोत्री धाम यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले इस मंदिर की स्थापत्य शैली, बनावट सब कुछ केदारनाथ धाम जैसी ही है। जिस तरह केदारनाथ धाम मंदिर आइस एज में 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था वैसे ही धराली का कल्प केदार मंदिर भी किसी आपदा के कारण जमीन में दब गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 19 वीं सदी में खीर गंगा में विनाशकारी बाढ़ आई थी। तब यह कल्प केदार मंदिर मलबे में दब कर लुप्त हो गया था। 80 साल पहले 1945 में ग्रामीणों ने धरती से बाहर झांकते मंदिर के शिखर को देखा था। यानी शिखर के स्वतः नजर आने पर ग्रामीणों ने खुदाई शुरू की। 12 फीट खुदाई करने के बाद मंदिर का सिर्फ आधा भाग ही बाहर आ सका था। यानी मंदिर के द्वार तक ही खुदाई की गई थी। तब से इस मंदिर में पूजा पाठ हो रही थी। यानी खुदाई में मिले मंदिर का काफी बड़ा भाग जमीन में ही था। माना जाता है कि कल्प केदार मंदिर परिसर 240 मंदिरों के समूह था। इसी समूह का कल्प केदार हिस्सा था, शेष मंदिर समय-समय पर होने वाले भौगोलिक परिवर्तन के कारण लुप्त होते चले गए। दावा किया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर दूर गंगोत्री हाइवे पर धराली गांव चार धाम यात्रा के बीच पड़ता है। प्रमुख तीर्थस्थल गंगोत्री से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर धराली और इसके पास हर्षिल गंगोत्री धाम की यात्रा का आखिरी पड़ाव है। गंगोत्री जाने वाले यात्री आमतौर पर हर्षिल में पड़ाव करते हैं। जो लोग हर्षिल में नहीं रुकते, वो धराली में रुकते रहे हैं। धराली कस्बे के बाद गंगोत्री तक पहाड़ी रास्ता है। हर्षिल और धराली गांव का फासला तीन-चार किलोमीटर है।

केदारनाथ और कल्प केदार में अंतर

कल्प केदार मंदिर के पुजारी प्रथम सिंह पवार का कहना है कि पांडवों ने केदारनाथ से पहले कल्प केदार मंदिर का निर्माण करवाया था। पांडवों पर महाभारत के युद्ध के बाद पितृ हत्या, ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो भगवान श्रीकृष्ण ने पांडवों को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा था, ताकि वह ब्रह्म हत्या और पितृ हत्या के दोष से मुक्त हो सकें, लेकिन देवों के देव महादेव पांडवों से नाराजा थे। वेदव्यास के सुझाव पर पांडवों ने धराली में शिव को समर्पित 240 मंदिरों की स्थापना कर शिव की आराधना की तो शिव धराली छोड़ कर केदारनाथ चले गए थे। इसलिए पांडवों को कल्प केदार मंदिर में शिव के दर्शन नहीं हुए। इसके बाद ही पांडवों ने केदारनाथ में शिव को समर्पित मंदिर का निर्माण कराया था। कल्प केदार मंदिर में केदारनाथ की तरह ही शिवलिंग कूबड़ के आकार में विराजमान हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि केदारनाथ में शिवलिंग काले रंग का है, जबकि कल्प केदार में सफेद रंग में भगवान शिव शिला के रूप में विराजमान हैं। यह शिवलिंग आधा जलमग्न रहता था और इसका एक हिस्सा जमीन के नीचे था। यानी इस शिवलिंग के स्वयंभू होने का भी दावा स्थानीय लोग करते हैं। उनका दावा है कि हजारों साल से यह मंदिर था। क्योंकि इस मंदिर का जिक्र केदार खंड में भी मिलता है। धराली निवासी दीपक पंवार का कहना है कि हाल ही में भगवान गणेश की बहुमुखी प्रतिमा कल्प केदार मंदिर के पास खुदाई में मिली थी। कल्प केदार अब समाधि में पहुंच चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो कल्प केदार को मलबे से बाहर निकालेंगे और पहले की तरह से फिर यहां पर पूजा होगी। कल्प केदार मंदिर तो पहले भी आधा धरती के अंदर ही था फिर भी श्रद्धालु यहां पूजा करते थे। यानी हर कोई चाहता है कि इस मंदिर को खुदाई के बाद फिर से अस्तित्व मिले, ताकि श्रद्धालु इसके दर्शन कर सके। ग्रामीणों व पुजारी का कहना है कि वो रोज शाम 7 बजे यहां आरती करते थे। हम लोग उन्हीं के सहारे यहां जीते थे। पूरे गांव के लोग और टूरिस्ट भी यहां आते थे।

- **धराली के अधिकांश लोग इस बात को देवकृपा मानते हैं कि हार दूध मेले के आयोजन की वजह से गांव के 200 से ज्यादा लोग सोमेश्वर देवता की शरण में होने की वजह से बच गए, यह विनाशकारी घटना बताती है कि परंपराएं, श्रद्धा और सामूहिक एकजुटता कभी-कभी जीवन रक्षक बन जाती हैं।**
- **धराली में 1945 में की गई खुदाई के बाद कल्प केदार मंदिर के बारे में पता चला था, तब 12 फीट खुदाई करने के बाद जमीन के नीचे यह प्राचीन शिव मंदिर मिला था जिसकी बनावट और शैली केदारनाथ मंदिर के जैसी थी, कत्युर शैली में निर्मित इस शिव मंदिर की वास्तुकला भी केदारनाथ धाम की तरह थी।**

धराली में सोमेश्व देवता ने बचाया

समुद्र तल से 1,230 फीट की ऊंचाई से 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी और मलबे का सैलाब नीचे आया, जो मात्र 30 से 58 सेकंड में धराली को तबाह कर गया। इस सैलाब ने न केवल गांव के रिहायशी इलाकों, घरों, होमस्टे, होटल और बाजार की तस्वीर मिटा दी। बल्कि गंगोत्री हाइवे से मात्र 50 मीटर दूरी पर स्थित कल्प केदार मंदिर को भी अपने आगोश में ले लिया। किंतु धराली गांव में 5 अगस्त को जब विनाशकारी सैलाब आया तो गिने चुने घरों और एक मंदिर के अलावा कुछ नहीं बचा। यह धराली का प्राचीन सोमेश्वर देवता का मंदिर है। ये मंदिर 200 सालों से भी पुराना बताया जा रहा है। हालांकि 20 से 25 साल पहले मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया। जो तबाही धराली गांव में आई, उसमें ये मंदिर ही नहीं बचा बल्कि इस मंदिर के साथ कम से कम 200 जिंदगियां भी बच गई। धराली के पास ही मुखबा गांव निवासी मानेंद्र सेमवाल का कहना है कि भटवाड़ी ब्लॉक और हर्षिल घाटी के लगभग हर गांव में सोमेश्वर देवता का मंदिर है। सोमेश्वर को शिव का रूप माना जाता है। इस पूरी बेल्ट में स्थानीय लोग सोमेश्वर देवता को पूजते हैं और रक्षक मानते हैं। धराली गांव में भी सोमेश्वर का प्राचीन लकड़ी का बना मंदिर है। जिसमें भगवान सोमेश्वर की मूर्ति और डोली की पूजा की जाती है। श्रावण माह में हार दूधू मेले का आयोजन होता है। यह पारंपरिक त्यौहार धराली, मुखवा और आसपास के गांवों की आस्था का केंद्र है। बुग्यालों से लाए गए ब्रह्म कमल और जयान जैसे दुर्लभ फूल समर्पित कर समेश्वर देवता की आराधना की जाती है। पहले दिन रात्रि में पूजा और विशेष अनुशष्ठान होता है, दूसरे दिन देव आराधना के साथ मेले का समापन होता है इस बार 5 अगस्त को दिन में हार दूधू मेले का आयोजन हो रहा था। मेले में गांव के 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। जिस समय मलबा आया उसी समय पूजा चल रही थी, लेकिन चंद सेकेंडो में सैलाब आया और सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन सोमेश्वर मंदिर और मंदिर में मौजूद 200 से ज्यादा लोग बच गए। जिस पहाड़ी से सैलाब आया उसी पहाड़ी पर आधा किलोमीटर से कुछ ज्यादा दूरी पर नाग देवता का मंदिर भी है। वह भी सुरक्षित है। हार दूध मेले में नाग देवता को ग्रामीण अपनी गायों दूध को चढ़ाते हैं। दूध चढ़ाने के लिए ही इस मेले का आयोजन होता है। गांव की सभी ध्याणियां, बहुएं और परिवार के लोग सोमेश्वर देवता के मंदिर में दूध एकत्रित करके भगवान को अर्पित करते हैं। इस परंपरा से भी कई लोगों की जान बच गई। अब धराली के अधिकांश लोग इस बात को देवकृपा मानते हैं कि हार दूध मेले के आयोजन की वजह से गांव के अधिकांश लोग एक जगह, देवता की शरण में एकत्र थे। यह विनाशकारी घटना बताती है कि परंपराएं, श्रद्धा और सामूहिक एकजुटता कभी-कभी जीवन रक्षक बन जाती हैं। समेश्वर देवता की यह कृपा धराली गांव की स्मृतियों में हमेशा अमिट रहेगी। ●

नंदादेवी राजजात यात्रा अगले बरस

नंदा देवी राजजात यात्रा लगभग 20 दिनों की पैदल यात्रा है, जो नौटी से शुरु होकर होमकुंड तक जाती है, कुलसारी, वाण, गैरोली पातल, शिला समुद्र, चंदनिया घाट, सुतोल और घाट इसके प्रमुख पड़ाव हैं, हर पड़ाव पर लोकनृत्य, भजन और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जो इस यात्रा को सांस्कृतिक महोत्सव में बदल देते हैं।

डॉ.हरीश चंद्र अंडोला
दून यूनिवर्सिटी

नंदादेवी उत्तराखंड की आराध्य देवी हैं मां नंदा-सुनंदा। समूचे उत्तराखंड में हिमालय पर्वत को देवात्मातुल्य माना जाता है नंदा उसी हिमालय पर्वत की सुपुत्री हैं, इसलिए पर्वतीय राज्य में मां नंदा देवी की बड़ी मान्यता है। देवभूमि उत्तराखंड में नंदादेवी के अनेक मंदिर हैं, यहां की अनेक नदियां एवं पर्वत श्रंखलाएं, पहाड़ और नगर नंदा के नाम पर है। नंदादेवी, नंदाकोट, नंदाभनार, नंदाघूंघट, नंदाघुंटी, नंदाकिनी और नंदप्रयाग जैसी अनेक पर्वत चोटियां, नदियां तथा स्थल नंदा के धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। नंदा के सम्मान में कुमाऊं और गढ़वाल में अनेक स्थानों पर मेले भी लगते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल वासियों के लिए नंदादेवी शिखर केवल पहाड़ न होकर एक जीवंत रिश्ता है। इस पर्वत के वासी देवी नंदा को बहन-बेटी मानते आएं हैं। लिहाजा देवभूमि उत्तराखंड में हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा अगले बरस यानी 2026 में एक बार फिर होगी। यह यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति और मान्यताओं का उत्सव है। 280 किलोमीटर लंबी यह पैदल यात्रा देश-विदेश के श्रद्धालुओं को भी आकर्षित करती है। उत्तराखंड के निवासी नंदा देवी को भगवान शिव की पत्नी के रूप में मानते हैं और कैलाश को नंदा देवी की ससुराल मानते हैं। मान्यता है कि एक बार देवी नंदा मायके आईं और 12 साल तक नहीं लौटीं। इसके बाद उन्हें विशेष विधि-विधान से ससुराल के लिए विदा किया गया। यह यात्रा उसी प्रतीकात्मक विदाई की स्मृति है, जो गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों में रची-बसी है। 7वीं सदी में गढ़वाल नरेश शालिपाल ने इस राजजात यात्रा की नींव रखी थी। राजा कनकपाल ने इस यात्रा को और भी भव्य स्वरूप दिया। यात्रा संपन्न कराने में गढ़वाल राजवंश, नौटी गांव के राजगुरु, ब्राह्मण और सयाने सामूहिक भूमिका निभाते हैं। 'चार सींगों वाली दुर्लभ काली भेड़' (चौसिंगा खाडू) इस राजजात यात्रा को आकर्षित करने वाली विशेषता है। चौसिंगा भेड़ देवी की भेंटों को लेकर यात्रा का नेतृत्व करती है और अंत में होमकुंड से कैलाश की ओर चल पड़ती है। यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए भावनाओं से भरा और चमत्कारी पल होता है।

हर पड़ाव पर सांस्कृतिक महोत्सव

नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा नौटी गांव के सिद्धपीठ में होती है। यहीं से भक्त देवी को वस्त्र, आभूषण और मिठाई अर्पित कर विदा करते हैं। कांसुवा के राजकुमार यात्रा की सफलता का संकल्प लेते हैं, जिससे यह यात्रा राजकीय और धार्मिक रूप से विशेष बन जाती है। नंदा देवी राजजात यात्रा लगभग 20 दिनों की पैदल यात्रा है, जो नौटी से शुरू होकर होमकुंड तक जाती है। कुलसारी, वाण, गैरोली पातल, शिला समुद्र, चंदनिया घाट, सुतोल और घाट इसके प्रमुख पड़ाव हैं। हर पड़ाव पर लोकनृत्य, भजन और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जो इस यात्रा को सांस्कृतिक महोत्सव में बदल देते हैं। उत्तराखंड में मां नंदा देवी को अनेक रूपों में पूजा जाता है। यहां विवाहिता और कुंवारी बहनों को दिशा ध्याणी कहा जाता है। इसलिए इस राजजात यात्रा में बेटियों को खास महत्व दिया जाता है। बहनों को दिशा ध्याणी के रूप में पूजने वाले लोग मां नंदा देवी को धन्य एवं श्रृंगार सामग्री भेंट करते हैं। बेटी के ससुराल पक्ष से मिलने वाली सामग्री को लोकदेवी के प्रसाद के रूप में श्रद्धालु आपस में बांटते लेते हैं। घाट ब्लॉक के कुरूड, नॉटी से लेकर नारायणबगड के भगौती गांव तक को मां नंदा का मायका माना जाता हैं। यहां मां नंदा को बेटी या बहन के रूप में पूजा जाता है। भगौती गांव के बाद मां नंदा की ससुराल शुरू हो जाती है।

वैश्विक पहचान देने के प्रयास

अगले बरस होने वाली नंदादेवी राजजात यात्रा की तैयारी के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज ने 2026 की राजजात यात्रा को सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। यानी अगले बरस इस राजजात यात्रा में लोकसंस्कृति, परंपरागत लोककला और आध्यात्म का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। क्योंकि राज्य सरकार चाहती है कि नंदा देवी राजजात यात्रा न केवल धार्मिक, बल्कि पर्यटन और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाए। इसके लिए सरकार ने आधुनिक सुविधाएं और प्रचार की योजना बनाई है ताकि उत्तराखंड की यह परंपरा विश्व के सामने पूरी गरिमा के साथ प्रस्तुत की जा सके। नंदा देवी राजजात यात्रा को इस बार देश के साथ भारतीय दूतावासों के माध्यम से विदेश तक प्रचारित करने की योजना है। ताकि विश्व समुदाय भी उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बन सके। अधिक से अधिक देशी व विदेशी पर्यटक और तीर्थयात्री इस सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन सकें। वैसे पर्यटक इसलिए भी इस तरह के आयोजनों में रूचि दिखाते हैं, क्योंकि हिमालय के खूबसूरत और अनछुए बुग्याल, झरने और पहाड़ियों से पर्यटक रू-ब-रू होते हैं।

श्रद्धालुओं का मेडिकल व रजिस्ट्रन होगा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राजजात यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इको-फ्रेंडली टेंट कॉलोनी विकसित की जाएंगी, पेयजल, शौचालय और पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, यात्रा मार्ग पर अस्थाई और स्थाई कार्यों की पहचान कर एक महीने में स्वीकृति देकर काम शुरू करा दिया जाएगा। लोक कलाकारों को तत्काल भुगतान की व्यवस्था होगी, जिससे परंपरा और रोजगार दोनों का समन्वय बना रहे। गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय के सहयोग से यात्रा के अभिलेखों का संरक्षण और लेखन भी कराया जाएगा। सरकार की कोशिश होगी कि राजजात यात्रा के मार्ग में पर्याप्त होम स्टे उपलब्ध रहे, मोबाइल नेटवर्क की स्थिति से जूझना न पड़े, सोलर लाइट की मदद से मार्ग को रोशन किया जाए। सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती होगी, ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा, सीसीटीवी निगरानी जैसी व्यवस्था पहली बार देखने को मिलेगी। इस यात्रा में शामिल होने से पहले सभी श्रद्धालुओं का ना सिर्फ मेडिकल चेकअप होगा, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। क्योांकि हिमालयी क्षेत्र की कठिनाइयों के कारण केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ और अनुभवी श्रद्धालु ही इस यात्रा में शामिल हो सकेंगे।

यात्रा में प्राण त्याग देते थे श्रद्धालु

उत्तराखंड की नंदा देवी राजजात यात्रा विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्राओं में से एक है। यह यात्रा उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उत्तराखंड में आज सड़क है, लेकिन जब यह परंपरा शुरू हुई तब बेहद कठिन रास्ते थे। लोग इस यात्रा में जाने के बाद मान लेते थे कि वह वापस नहीं लौटेंगे। फिर रूप कुंड हो या स्वर्गरोहिणी, यह ऐसे स्थान थे जहां लोग अपने प्राण त्याग देते थे। लिहाजा हर साल राजजात यात्रा करना संभव नहीं था। आपदा और दूसरी बड़ी दुर्घटनाओं के बाद इस यात्रा को हर 12 साल बाद आयोजित करने का निर्णय तत्कालीन राजाओं ने लिया। उस समय की राजजात यात्रा में कई तरह के प्रतिबंध भी थे। यानी यात्रा में महिलाओं का जाना वर्जित था। पिछली राजजात यात्रा 2014 में आयोजित हुई थी। जहां तक मुझे याद है 2014 में ही पहली बार महिलाओं ने राजजात यात्रा में भाग लिया था। यात्रा की शुद्धता के लिहाज से

भविष्य पुराण में जिन दुर्गाओं का उल्लेख है उनमें महालक्ष्मी, नंदा, क्षेमकरी, शिवदूती, महाटूंडा, भ्रामरी, चंद्रमंडला, रेवती और हरसिद्धी हैं। शिवपुराण में वर्णित नंदा तीर्थ वास्तव में कुर्मांचल ही है, शक्ति के रूप में नंदा ही सारे हिमालय में पूजी जाती हैं।

इसमें शामिल श्रद्धालु चमड़े से निर्मित कोई भी सामान अपने पास नहीं रख सकते थे। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में यह प्रतिबंध समाप्त हो गया।

गढ़वाल व कुमाऊं में नंदा की उपासना

उत्तराखंड में वैसे तो कई धार्मिक यात्रा होती है किंतु मां नंदा देवी का पूरे उत्तराखंड में विशेष स्थान है। लिहाजा कुमाऊं की संस्कृति को समझने के लिए नंदा देवी राजजात यात्रा और नंदा देवी मेला देखना जरूरी है। ये मेले अल्मोड़ा, नैनीताल, कोटमन्या, भवाली, बागेश्वर, रानीखेत, चंपावत व गढ़वाल क्षेत्र के कई स्थानों पर हर साल आयोजित होते हैं। लोकमान्यता है कि अल्मोड़ा में नंदा देवी मेला तो चंद वंश के शासनकाल से लगता आ रहा है। जिसकी शुरुआत राजा बाज बहादुर चंद के शासनकाल में हुई थी। राजा बाज बहादुर चंद ही 1670 में नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को गढ़वाल बधाणकोट किले से उठाकर अल्मोड़ा लाए थे। इस विग्रह को उस कालखंड में अल्मोड़ा के कचहरी परिसर स्थित मल्ला महल में स्थापित किया गया था। तब से उन्होंने मां नंदा को कुलदेवी के रूप में पूजना शुरू कर दिया था। 1690 में तत्कालीन राजा उद्योत चंद ने अल्मोड़ा में पार्वतीश्वर और उद्योत चंद्रेश्वर नाम के दो शिव मंदिर बनवाए थे। आज भी ये मंदिर उद्योत चंद्रेश्वर व पार्वतीश्वर के नाम से प्रचलित हैं। 1815 में ब्रिटिश हुकुमत के दौरान तत्कालीन कमिश्नर ट्रेल ने नंदा देवी की प्रतिमा को मल्ला महल से दीप चंदेश्वर मंदिर, अल्मोड़ा में स्थापित करा दिया था। गढ़वाल के पंवार राजाओं की भांति कुमांऊ के चंद राजाओं की कुलदेवी भी नंदा देवी ही हैं इसलिए दोनों ही मंडलों में नंदा देवी के उपासक हैं। यानी यहां आदिशक्ति मां नंदा देवी को श्रद्धा से पूजने की परंपरा सदियों से है। नंदा देवी की उपासना प्राचीन काल से ही किए जाने के प्रमाण धार्मिक ग्रंथों, उपनिषद और पुराणों में मिलते हैं। रूप मंडन में पार्वती को गौरी के 6 रूपों में से एक बताया गया है। भगवती की 6 अंगभूता देवियों में नंदा देवी भी एक है। नंदा को नवदुर्गाओं में से भी एक बताया गया है। भविष्य पुराण में जिन दुर्गाओं का उल्लेख है उनमें महालक्ष्मी, नंदा, क्षेमकरी, शिवदूती, महाटूंडा, भ्रामरी, चंद्रमंडला, रेवती और हरसिद्धी हैं। शिवपुराण में वर्णित नंदा तीर्थ वास्तव में कुर्मांचल ही है। शक्ति के रूप में नंदा ही सारे हिमालय में पूजी जाती हैं। ●

संघर्ष से रेखा मजबूत हुई

रेखा ने महज 4 साल की उम्र में 1958 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, तेलुगु फिल्म 'इनती गुट्टू' से एक्टिंग की शुरुआत की थी, परिवार की आर्थिक तंगी ने उन्हें एक्टिंग की दुनिया में धकेल दिया था, जबकि रेखा हमेशा एयर होस्टेस बनने का सपना देखती थीं ताकि वह दुनिया घूम सकें।

अरुण सिंह
मुंबई ब्यूरो

भारतीय सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्री रेखा की जिंदगी में संघर्ष और चुनौतियां कम नहीं थीं। अपने पिता से नाम न मिलने से लेकर आर्थिक तंगी तक, रेखा ने हर मुश्किल का सामना दृढ़ता से किया और बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्रियों की कतार में खड़ी हुईं। हिंदी सिनेमा की दुनिया में हर साल सैकड़ों अभिनेत्रियां अपनी किस्मत आजमाने आती हैं, लेकिन कुछ ही होती हैं जो इंडस्ट्री पर अपनी अमिट छाप छोड़ पाती हैं। उन्हीं में से एक हैं सदाबहार अभिनेत्री रेखा, जिन्होंने न केवल अपनी बेमिसाल अदाकारी बल्कि अपनी एवरग्रीन खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज किया है। 1970 में फिल्म 'सावन भादो' से अपने करियर की शुरुआत करने वाली रेखा आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अदाकाराओं में गिनी जाती हैं। 10 अक्टूबर 1954 को साउथ इंडियन परिवार में जन्मी रेखा का असली नाम भानुरेखा गणेशन है। उनकी जिंदगी का शुरुआती दौर काफी संघर्षपूर्ण रहा। उनके पिता जेमिनी गणेशन, जो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित अभिनेता थे, ने रेखा को कभी नहीं अपनाया और न ही अपना नाम दिया। रेखा की मां पुष्पावल्ली भी साउथ की फिल्मों की बेहतरीन अदाकार थीं, लेकिन पारिवारिक हालात इतने खराब थे कि रेखा को बहुत छोटी उम्र में काम करना पड़ा। रेखा ने महज 4 साल की उम्र में यानी 1958 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, तेलुगु फिल्म 'इनती गुट्टू' से एक्टिंग की शुरुआत की थी। परिवार की आर्थिक तंगी ने उन्हें एक्टिंग की दुनिया में धकेल दिया था, जबकि रेखा हमेशा एयर होस्टेस बनने का सपना देखती थीं ताकि वह दुनिया घूम सकें। लेकिन मजबूरी में रेखा ने फिल्मों में काम करना शुरू किया और पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाईं। रेखा को अपने करियर के शुरुआती दिनों में उनके सांवले रंग और सुंदरता को लेकर कई बार आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता था। 'उमराव जान' जैसी फिल्मों में अपनी बेमिसाल अदाकारी के बावजूद, रेखा ने अपने संघर्ष से कभी हार नहीं मानी।

तंगी में बी और सी ग्रेड फिल्में की

आर्थिक तंगी के कारण उन्हें बी और सी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत और टैलेंट ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। सदाबहार अभिनेत्री रेखा की पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा का विषय रही है। उनकी शादीशुदा जिंदगी में भी काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले। 1990 में उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन एक साल के अंदर ही उनका रिश्ता टूट गया। मुकेश के आत्महत्या करने के बाद रेखा को कई बार इसका जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट में लिखा था कि उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन समाज ने मुकेश अग्रवाल की मौत का जिम्मेदार रेखा को ही ठहराया। उनके चरित्र पर उंगलियां उठाई गईं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने उन्हें 'पति खाने वाली' नाम तक दे दिया। सुभाष घई ने तो यहां तक कहा था कि 'रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे पर इतने दाग लगाए हैं जिन्हें आसानी से धोया नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि इसके बाद किसी भी इज्जतदार घराने को किसी भी अभिनेत्री को उनकी बहू के रूप में स्वीकार करने से पहले दो बार सोचना होगा। कोई भी ईमानदार डायरेक्टर उनके साथ कभी काम नहीं करेगा।' किंतु रेखा ने हर मुश्किल का मजबूती से सामना किया। रेखा के अफेयर की चर्चाएं हमेशा सुर्खियों में रहीं। अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, विनोद मेहरा से लेकर संजय दत्त तक, कई बड़े सितारों के साथ उनका नाम जुड़ा, हालांकि रेखा ने हमेशा अपने रिश्तों पर चुप्पी साधे रखी। एक तरह से कहें तो रेखा को प्यार तो बहुतों से हुआ लेकिन प्यार किसी का न मिला। शादी भी बहुतों से हुई लेकिन पति कोई न रहा। उनके प्यार के किस्से आज हर जगह बिखरे पड़े हैं। रेखा को देखेंगे तो चेहरे पर हमेशा मुस्कान दिखाई देगी लेकिन आंखों की गहराई में सिर्फ खालीपन नजर आता है।

पिता का प्यार नहीं मिला

रेखा ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. 'उमराव जान', 'मुकद्दर का सिकंदर', 'सिलसिला', 'मिस्टर नटवरलाल', 'खून भरी मांग' और 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' जैसी फिल्मों ने उन्हें सिनेमा जगत में अमर कर दिया है। रेखा ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली फिल्मों सहित कई भाषाओं में अभिनय करके अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। बॉलीवुड में उनकी सफलता का मार्ग कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से चिह्नित था। इसके अलावा उन्हें कांजीवरम साड़ी और गजरा (फूलों की माला) हेयरस्टाइल को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। उनका अनोखा फैशन सेंस कई लोगों के लिए प्रेरणा रहा है। रेखा के पास एक्टिंग के अलावा गाने और मिमिक्री करने की भी बेहतरीन कला है। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज दी है। यहां तक कि स्मिता पाटिल और नीतू कपूर जैसी अभिनेत्रियों की डबिंग भी की है। फिल्म 'खूबसूरत' के लिए उन्होंने खुद एक गाना भी गाया है, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। पत्रकार यासीर उस्मान द्वारा लिखी गई रेखा की बायोग्राफी 'रेखा, द अनटोल्ड स्टोरी' में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन्हें जानना जरूरी है। फिल्म अभिनेत्री रेखा के माता और पिता दोनों फिल्मों में कलाकार थे। जब रेखा छोटी थीं तभी मां पुष्पवल्ली और पिता सुपरस्टार जैमिनी गणेशन अलग हो गए थे। रेखा ने कभी अपने पिता के प्यार का अहसास नहीं किया, उन्हें उनके संग बिताया हुआ समय याद नहीं है। रेखा का बचपन बहुत छोटा था, क्योंकि उन्हें बचपने में ही बहुत बड़ा कर दिया गया था। पिता के जाने के बाद मां को घर चलाना था। मां पर कर्ज भी था, तो कर्ज निपटाने और घर चलाने के लिए रेखा को काम पर लगा दिया गया। यानी फिल्मों में रेखा का डेब्यू नहीं हुआ था बल्कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में धकेला गया था। फिल्मों की वो भानुरेखा जो कभी फिल्मों में काम करना नहीं चाहती थीं। रेखा का सिर्फ एक सपना था कि उसे कोई प्यार करने वाला हो जिससे वो शादी करें, घर बसाएं और उनके बच्चे हों। लेकिन मां ने उन्हें बॉलीवुड में काम करने के लिए भेज दिया। वो अकेली मुंबई आई और कोल्हू के बैल की तरह लगी रहीं सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक सिर्फ काम करती थीं। मां से ये भी नहीं कह सकती थीं कि वो ये सब करना नहीं चाहती, क्योंकि ये सब करना उनकी जिम्मेदारी बन गया था। फिर इस जिम्मेदारी को निभाते-निभाते रास्ते में जो कुछ भी उनके साथ घटता गया, वो उसे झेलती गई। रेखा जब फिल्मों में आई तो वो सांवली थीं, छरहरी हिरोइनों की तरह उनकी काया नहीं थी, वजन काफी था, अपने रूप और रंग को लेकर उन्होंने कितना ही सुना था। शशि कपूर ने तो उन्हें काली, मोटी और भद्दी तक कह दिया था। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने खुद को बदला, जिससे लोग उन्हें बदसूरत न कहें। आज उनकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती हैं, वो खूबसूरती जो उनकी उम्र के साथ और बढ़ रही है। रेखा अभिनय को काम की तरह से कर रही थीं लेकिन जब उन्हें पहला अवार्ड मिला तब उन्हें एक कलाकार की कीमत का अहसास हुआ और फिर एक्टिंग उनका पैशन बन गया।

रेखा का मेंटल हैरेसमेंट

1969 में रेखा जब केवल 14 साल की थी तब फिल्म 'अंजाना सफर' की शूटिंग हो रही थी। निर्देशक राजा नवाथे और हीरो विश्वजीत ने प्लान बनाया और निशाना थीं रेखा। उस दिन रेखा और विश्वजीत पर एक किसिंग सीन फिल्माया जाना था। शूट से पहले ही इस प्लान की सारी तैयारियां कर ली गई थीं, कैमरा हर एक पल को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार था। जैसे ही डायरेक्टर ने कहा एक्शन विश्वजीत ने रेखा को अपनी बाहों में कस लिया और अपने होंठ उनके होठों पर गड़ा दिए। रेखा स्तब्ध थीं, इस किस सीन के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। कैमरा चलता रहा, न तो डायरेक्टर ने कट कहा और न ही विश्वजीत ने उन्हें छोड़ा। इस बोल्ड सीन ने रेखा को एक बोल्ड एक्ट्रेस का तमगा दे दिया था। रेखा के संघर्षों की उम्र बहुत लंबी है। लेकिन रेखा कहती हैं कि इसी लंबे वक्त की वजह से उनके घाव भरते चले गए। वो आज बहुत मजबूत हैं और अब पिछली बातों से उन्हें दर्द नहीं होता। वो अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हैं। वो कहतीं भी तो किस-किस के लिए मीटू कहतीं। अपने माता और पिता के लिए जिनकी वजह से वो अपना बचपन सामान्य बच्चों की तरह नहीं जी पाई। क्या ये मेंटल हैरेसमेंट नहीं था? इंडस्ट्री में काम करने वालों के खिलाफ जिन्होंने ये तक न देखा कि वो 14 साल की एक बच्ची है जिसे जबरदस्ती चूमा और सीटियां भी बजवाई गई या उन लोगों पर जो उनके पतियों की मौत का जिम्मेदार उन्हें मानते रहे है या उनपर जिन्होंने उनके चरित्र पर सवाल करने से पहले जरा भी नहीं सोचा। जरा सोचिए आज अगर रेखा के साथ ये सब हुआ होता, तो रेखा की कहानी कुछ और होती, उन्हें बदनाम एक्ट्रेस न कहा जाता।

- **रेखा को अपने करियर के शुरुआती दिनों में सांवले रंग और सुंदरता को लेकर कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था, 'उमराव जान' जैसी फिल्मों में अपनी बेमिसाल अदाकारी के बावजूद, रेखा ने अपने संघर्ष से कभी हार नहीं मानी।**
- **रेखा का अफेयर हमेशा सुर्खियों में रहा, अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, विनोद मेहरा से लेकर संजय दत्त तक, कई बड़े सितारों के साथ उनका नाम जुड़ा, एक तरह से कहें तो रेखा को प्यार तो बहुतों से हुआ लेकिन प्यार किसी का न मिला, शादी भी बहुतों से हुई लेकिन पति कोई न रहा।**
- **मां ने रेखा को बॉलीवुड में काम करने के लिए भेज दिया, वो अकेली मुंबई आई और कोल्हू के बैल की तरह लगी रहीं सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक सिर्फ काम करती थीं, मां से ये भी नहीं कह सकती थीं कि वो ये सब करना नहीं चाहती, क्योंकि ये सब करना उनकी जिम्मेदारी बन गया था।**

मासिक राशिफल

पंडित उपेन्द्र कुमार उपाध्याय
9897450817, 9897791284
ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदरत्न, कथावाचस्पति, यज्ञानुष्ठान विशेषज्ञ
अध्यक्ष-श्री शिवशक्ति ज्योतिष पीठ, बदायूं
निवास प्रभातनगर, निकट इंद्राचौक, सिविल लाइंस, बदायूं (यूपी)

मेष:-

इस माह आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, यदि आप मित्रों के साथ यात्रा पर जा रहे हैं तो पैसा सोच समझकर व्यय करें, धन हानि हो सकती है। व्यक्तिगत मामलों को सुलझाते समय उदारता दिखाएं, लेकिन अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। बहुत करीबी प्रियजन से मिलने का योग बन रहा है। मुश्किल मामलों के समाधान के लिए अपने संपर्क का उपयोग करें, प्रेमी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। जीवनसाथी के साथ कुछ बेहतरीन पल गुजार सकेंगे। उपाय: इत्र, परफ्यूम, कपूर का इस्तेमाल व दान करें कार्य सिद्ध होंगे।

वृषभ:-

इस माह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इस राषि के जो जातक लघु उद्यमी हैं उन्हें किसी करीबी की आर्थिक लाभ पहुंचाने वाली कोई अच्छी सलाह मिल सकती है। पारिवारिक सदस्य या जीवनसाथी तनाव की वजह बन सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और तरक्की साफ नजर आएगी। कोरोनाकाल में खाली समय का पूरा आनंद उठाने के लिए लोगों से दूर रह कर पसंदीदा और महत्वपूर्ण काम निपटाने चाहिए। प्रेमी युगल सामान्य दिनों की अपेक्षा इस समय आपका अधिक ख्याल रखेगा। उपाय: भैरो बाबा के मंदिर में दूध चढ़ाएं कार्य सिद्ध होंगे।

मिथुन:-

इस माह सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। आपका धन आपके काम तभी आएगा जब आप फिजूल खर्ची से बचेंगे। आपका कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। कुछ लोग आपके खिलाफ षडयंत्र रच रहे हैं। ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है जो आपका अहित चाहते हैं। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। आपका प्रिय आपकी खुशी की वजह साबित होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तरक्की के रास्ते खुलेंगे। कर्म-कांड, हवन-पूजन आदि का आयोजन करेंगे। उपाय: खट्टी-मीठी टॉफियां, छोटी कन्याओं में बांटे कार्य सिद्ध होंगे।

कर्क:-

इस माह शारीरिक श्रम आपके सौंदर्य को निखारेगा। घर के सदस्यों को घुमाने ले जा सकते हैं। यात्रा में धन खर्च होगा। जीवनसाथी के साथ खरीदारी करेंगे। दांपत्य जीवन में गलत फहमी दूर होंगी। प्यार जीवन की डोर को मजबूत बनाए रखेगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बाते सुनकर अपने प्यार के बारे में कोई राय न बनाएं। लोग आपको अपने बढ़िया कार्य के लिए पहचानेंगे। यदि आप यात्रा कर रहे है तो सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखे और दिक्कत से बचें। उपाय: सफेद चंदन की जड़ सफेद कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें सभी कार्यसिद्ध होंगे।

सिंह:-

इस माह आपको आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है। धन आपके काम तभी आएगा जब फिजूलखर्ची से बचेंगे। जिस पर भी आप भरोसा करते हैं, मुमकिन है वह आपको धोखा दे दे। न्यायालय संबंधी कार्यों में सफलता से मुश्किले हल करने में कामयाबी मिलेगी। आपका प्रिय आपको सदैव प्यार करता है, उस पर किसी तरह का संदेह न करें। कार्य में धीमी प्रगति हल्का-सा मानसिक तनाव दे सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। उपाय: तामसिक वस्तुओं मांस-मदिरा का सदैव के लिए त्याग कर दें सभी कार्य सिद्ध होंगे।

कन्या:-

इस माह धन संचय करने के लिए परिजनों की सलाह लेना आवश्यक है। परिजनों की सलाह से आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं। सभी विवादास्पद मुद्दों पर अनावश्यक बहस से बचें, इस माह जीवन में सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव करेंगे। चिंता न करें समय के साथ बदलाव आते हैं और आपकी रोमांटिक जिंदगी में फिर बदलाव आएगा। आफिस से घर आते समय सावधानी से वाहन चलाने की जरूरत है, दुर्घटना की संभावना है। जीवनसाथी आप पर शक कर सकता है। उपाय: सूर्यदेव को प्रातःकाल लालपुष्प अर्पित करें कार्य सिद्ध होंगे।

तुला:-

इस माह सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। माह के मध्य में कर्ज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भावनात्मक रूप से खतरा उठाना आपके लिए हितकारी हो सकता है। परिजनों की गैरजरूरी मांगों को नजरअंदाज करने में भलाई होगी। प्रसिद्ध लोगों के मिलन से नई योजना का आइडिया मिलेगा। दूर की यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन सफर के दौरान सावधान रहने की आवश्यकता है, धन की हानि हो सकती है। जीवन संगनी से अनबन हो सकती है। उपाय: अपने प्रिय को सफेद शंख, शिप की वस्तुएं गिफ्ट करें सभी कार्य सिद्ध होंगे।

वृश्चिक:-

इस माह मजबूत और स्पष्टवादी बनें। कठोर फैसले लेने के साथ उनके परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहें। माह के मध्य में धन लाभ के योग हैं, इसलिए स्वभाव को शांत रखने की जरूरत है। आक्रमकता धन लाभ के योग से वंचित कर सकती है। रिश्तेदारों से कीमती तोहफा मिल सकता है। प्यार के नजरिए से देखें तो आप जीवन के रस का भरपूर आनंद लेंगे। कामकाज में अपनों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा। जीवनसाथी का आंतरिक सौंदर्य बाहर भी पूरी तरह महसूस होगा। उपाय: बिस्तर पर क्रीम कलर की चादर बिछाएं कार्य सिद्ध होंगे।

धनु:-

इस माह नफरत से दूर रहे क्योंकि यह आपके मन के साथ शरीर पर भी बुरा प्रभाव डाल सकती है। रात के समय धन लाभ होने की संभावना है, रुके हुए धन की प्राप्ति से मन प्रसन्न होगा। बच्चों की तरफ से कोई खुश खबर मिलने वाली है। शत्रु पक्ष आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करेंगे। पेशेवर तौर पर यह माह सकारात्मक रहेगा। अपनी खुशियों का इजहार करने के लिए उतावलापन न दिखाए। जीवनसाथी का रुखापन देखने को मिल सकता है। उपाय: लक्ष्मीनारायण मंदिर में नियमित प्रसाद चढ़ाएं सभी कार्य सिद्ध होंगे।

मकर:-

इस माह संत महात्मा का आशीर्वाद मानसिक शांति प्रदान करेगा। माता-पिता फिजूलखर्ची से चिंतित हो सकते हैं। आप समूह में हों तो वाणी पर ध्यान रखें वरना कड़ी आलोचना का शिकार हो सकते हैं। यह माह कार्यक्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि बढ़ा सकता है। आपके सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे। बॉस भी आपके काम से खुश होगा। कारोबारी भी आज कारोबार में मुनाफा कमा सकते हैं। खाली समय में कोई गेम खेलना ठीक रहेगा। जीवनसाथी से विवाद की प्रबल संभावना है। उपाय: चंद्रमा की चांदनी में बैठ कर खीर खाएं कार्य सिद्ध होंगे।

कुंभ:-

इस माह व्यापार को मजबूती देने के लिए कोई अहम कदम उठा सकते हैं, कोई करीबी कारोबार में आपकी आर्थिक मदद कर सकता है। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मौज मस्ती करेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कारोबार से जुड़ी गोपनियता किसी के साथ साझा न करें। गोपनियता भंग होने पर बड़ी किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। हालात से उबरने के लिए दृढ़ इच्छा-शक्ति बनाए रखें। माह के मध्य में इस राशि के जातकों को वैवाहिक जिंदगी की अहमियत का अहसास होगा। उपाय: मसूर की लाल दाल किसी गरीब को दान करने से कार्य सिद्ध होंगे।

मीन:-

इस माह आपकी प्रगति की बाधाएं दूर होंगी। घर से बाहर निकलते समय सकारात्मक विचार आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। किसी कीमती वस्तु के चोरी होने से मूड खराब हो सकता है। पुराने संबंधियों के मिलन से पुराने रिश्तों में ताजगी आएगी। किसी प्राकृतिक सौंदर्य से खुद को सराबोर महसूस करेंगे। कार्यालय में सब कुछ आपके पक्ष में रहेगा। जीवन के अहम मुद्दों पर घरवालों के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। यात्रा संभव है, जीवनसाथी का आपके ऊपर खास ध्यान रहेगा। उपाय: शिव मंदिर में नियमित गंगाजल चढ़ाएं सभी कार्य सिद्ध होंगे।